● वर्ष-5

● अंक-257

रायपुर, शनिवार
13 जून 2026

● पृष्ठ-8

● मूल्य-3 रु.

।। संगछध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-8› 12 वर्षों में देश ने विकास की नई ...

टीएमसी में फूट के बीच कांग्रेस का बड़ा आरोप

मानसून सत्र से पहले दो-तिहाई बहुमत जुटाने में लगे अमित शाह

नई दिल्ली। पेपर लीक , वोट चोरी , भ्रष्टाचार समेत तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष केंद्र सरकार और बीजेपी पर हमलावर है। अब कांग्रेस ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर लोकसभा के लिए दो-तिहाई बहुत जुटाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, %अब वे विपक्षी दलों को तोड़ने और लोकतंत्र का पूरा मजाक बनाने में व्यस्त हैं। उनके मंसूबे सफल नहीं होंगे। जयराम रमेश का यह बयान ऐसे समय में आया है, जब तृणमूल कांग्रेस में कलह अपने चरम पर है और बागियों ने टीएमसी पर अपना अधिकार जताया है।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा, %इससे पहले कभी किसी ने लोकसभा में अपनी पार्टी के लिए दो-तिहाई बहुमत जुटाने की ऐसी कोशिश नहीं की, जैसी केंद्रीय गृह मंत्री इन दिनों संसद के मानसून सत्र से पहले पूरी बेचैनी से कर रहे हैं।%

स्वयंभू चाणक्य को होना पड़ा था अपमानित- जयराम रमेश

जयराम रमेश ने आगे कहा, स्वयंभू चाणक्य को 17 अप्रैल, 2026 को अपमानित होना पड़ा था, जब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) आवश्यक दो-तिहाई बहुमत नहीं जुटा पाई और परिसीमन से जुड़ा खतरनाक संविधान संशोधन विधेयक अच्छे अंतर से खारिज हो गया।

विपक्षी दलों को तोड़ने में व्यस्त हैं शाह- कांग्रेस

कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि उस करारी हार से तिलमिलाए हुए शाह अब विपक्षी दलों को तोड़ने और लोकतंत्र का मजाक बनाने में व्यस्त हैं। रमेश ने कहा, लड़ाई जारी है। उनके दुर्भावनापूर्ण मंसूबे सफल नहीं होने चाहिए और सफल नहीं होंगे।

रमेश का यह बयान तब आया जब तृणमूल कांग्रेस के बागी नेता जगदीश चंद्र बर्मा बसुनिया ने शुक्रवार को कहा कि पार्टी के बागी सांसद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से सोमवार को मुलाकात कर खुद को असली तृणमूल कांग्रेस के तौर पर मान्यता दिये जाने की मांग करेंगे।

बसुनिया ने दावा किया कि अभी 19 लोकसभा सदस्य इस गुट का समर्थन कर रहे हैं। कूचबिहार से सांसद और लोकसभा में राजग का समर्थन करने के इच्छुक सांसदों में शामिल बसुनिया ने बताया कि यह गुट सोमवार को लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात करेगा।पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हार और पार्टी के अंदर हुई बगावत के कारण तृणमूल कांग्रेस संकट का सामना कर रही है। इस बगावत ने पार्टी की संगठनात्मक और विधायी ताकत को काफी कमजोर कर दिया है। पिछले हफ्ते, पार्टी के दो-तिहाई से ज़्यादा विधायकों - 80 में से 58 ने आधिकारिक तृणमूल कांग्रेस विधायक दल से अलग होकर, पार्टी से निष्कासित विधायक रिताब्रता बनर्जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल विधानसभा में मुख्य विपक्षी गुट के तौर पर मान्यता हासिल कर ली।

छत्तीसगढ़ के स्कूलों में अब गूंजेंगे राष्ट्रगान

■ **नए शिक्षा सत्र 2026-27 से लागू होगी व्यवस्था- सुबह की प्रार्थना से लेकर छुट्टी के समय तक का शेड्यूल तय, अधिकारियों को रोजाना मॉनिटरिंग के निर्देश**

रायपुर। छत्तीसगढ़ के सरकारी और निजी स्कूलों में अब बच्चों को पढ़ाई के साथ-साथ नैतिक मूल्यों, राष्ट्रीय चेतना और भारतीय संस्कृति से गहराई से जोड़ा जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने नवीन शिक्षा सत्र 2026-27 से प्रदेश की सभी शालाओं में राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राज्यगीत सहित विभिन्न सांस्कृतिक और शैक्षणिक गतिविधियों के नियमित व अनिवार्य संचालन के कड़े निर्देश जारी किए हैं।मंत्रालय महानदी भवन (नवा रायपुर) से जारी इस आदेश के तहत सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में इस व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, स्कूलों में अब प्रतिदिन तीन अलग-अलग समय पर निर्धारित क्रम में गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। प्रात:कालीन सत्र स्कूल प्रारंभ होने पर सुबह की प्रार्थना सभा में एक तय क्रम के अनुसार ये प्रस्तुतियां अनिवार्य होंगी। विद्यालय प्रारंभ होने पर प्रात:कालीन प्रार्थना सभा में क्रमश: राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, दीपमंत्र, सरस्वती वंदना, गुरु मंत्र तथा महापुरुषों की जीवनी का वाचन कराया जाएगा। इसी प्रकार मध्यान्ह भोजन के समय विद्यार्थियों द्वारा भोजन मंत्र का सामूहिक पाठ किया जाएगा। वहीं विद्यालय की छुट्टी के समय संध्या सत्र में राज्यगीत, गायत्री मंत्र एवं शांति मंत्र का सामूहिक वाचन कराया जाएगा।

16 जून से मनेगा शाला प्रवेश उत्सव

रायपुर। छत्तीसगढ़ में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ ही राज्य सरकार विद्यार्थियों के लिए स्वच्छ, सुंदर और गुणवत्तापूर्ण माहौल तैयार करने जा रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (हश्वक्त 2020) के अनुरूप, प्रदेशभर में 16 जून 2026 से शाला प्रवेश उत्सव 2026 का गरिमामय आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने मंत्रालय महानदी भवन (नवा रायपुर) से विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।

बौद्धिक और नैतिक विकास है मुख्य उद्देश्य

स्कूल शिक्षा विभाग का मानना है कि इन गतिविधियों के नियमित और प्रभावी संचालन से छात्रों में न केवल राष्ट्रप्रेम और अनुशासन की भावना मजबूत होगी, बल्कि उनके भीतर नैतिक मूल्यों और सांस्कृतिक चेतना का भी सही विकास होगा। यह पहल विद्यार्थियों को भारतीय परंपराओं और राष्ट्रीय मूल्यों से परिचित कराने में मील का पत्थर साबित होगी।

लापरवाही पर कार्रवाई

शासन ने स्पष्ट किया है कि सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को प्रतिदिन स्कूलों का औचक निरीक्षण करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि इन नियमों का कड़ाई से पालन हो रहा है या नहीं।

रायपुर। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने रेशम उत्पादन बढ़ाने पर विशेष बल देते हुए विभागीय अधिकारियों को प्रभावी कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हथकरघा बुनकरों, शिल्पियों एवं कारीगरों को डिजाइन विकास संबंधी नियमित प्रशिक्षण प्रदान किया जाए, ताकि उनके उत्पादों की गुणवत्ता और बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़े तथा उनकी आय में वृद्धि सुनिश्चित हो सके। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में रायपुर लोकसभा सांसद बृजमोहन अग्रवाल, छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड की अध्यक्ष श्रीमती शालिनी राजपूत, छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष राकेश पाण्डेय, छत्तीसगढ़ राज्य हथकरघा विकास एवं विपणन संघ के अध्यक्ष भोजराज देवांगन, ग्रामोद्योग विभाग के सचिव राजेश सिंह राणा, छत्तीसगढ़ माटी कला एवं हस्तशिल्प बोर्ड के प्रबंध संचालक जयप्रकाश मौर्य, छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की प्रबंध संचालक श्रीमती लीना कमलेश मंडावी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

रक्षा निर्यात: रूस को ब्रह्मोस मिसाइल देगा भारत

नई दिल्ली। भारत और रूस के संयुक्त प्रयासों से विकसित हुई ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल अब वापस रूस को ही बेची जा सकती है। ब्रह्मोस एयरोस्पेस ने स्पष्ट किया है कि यदि मॉस्को की ओर से इस मिसाइल को लेकर कोई ऑर्डर आता है, तो कंपनी उसे पूरा करने के लिए पूरी तरह सक्षम और तैयार है। इसका सीधा मतलब यह है कि जिस अचूक मिसाइल को भारत ने अपनी सैन्य संप्रभुता और सामरिक ताकत का मुख्य स्तंभ बनाया है, वह अब रूस की थलसेना और नौसेना के शस्त्रागार की भी शोभा बढ़ा सकती है। अंतरराष्ट्रीय नौसेना प्रदर्शनी 'फ्लीट-2026' के दौरान ब्रह्मोस एयरोस्पेस के शीर्ष नेतृत्व ने इस बात की पुष्टि की कि उनके पास पर्याप्त उत्पादन क्षमता है और वे

रूस की सैन्य आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से समझते हैं। यह मिसाइल भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और रूस के एनपीओ मशीनोस्ट्रोयेनिया का एक संयुक्त उपक्रम है। दोनों देशों ने साल 1995 में मिलकर ब्रह्मोस एयरोस्पेस की स्थापना की थी। भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मॉस्कवा नदी के नाम पर इस घातक मिसाइल का नाम ब्रह्मोस रखा गया था, जिसे आज दुनिया की सबसे तेज और सटीक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में गिना जाता है।

अब 200 लीटर से ज्यादा नहीं खरीद पाएंगे डीजल

नई दिल्ली। देशभर में पेट्रोल और डीजल की संभावित किल्लत को रोकने और आपूर्ति व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार ने एक बेहद सख्त और बड़ा कदम उठाया है। नए सरकारी आदेश के तहत, अब सामान्य पेट्रोल पंपों से इंडस्ट्रियल और कमर्शियल उपभोक्ताओं द्वारा पेट्रोल-डीजल खरीदने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। अब ऐसे बड़े उपभोक्ताओं को अपनी जरूरत का ईंधन केवल अधिकृत बल्क सप्लाई प्वाइंट्स से ही खरीदना होगा। सरकार ने फिलहाल इस कड़े प्रतिबंध को 90 दिनों की अवधि के लिए लागू किया है, हालांकि स्थिति में संतोषजनक सुधार होने पर इसे तय समय से पहले भी वापस लिया जा सकता है।

प्रमुख समाचार

खड़गे ने राज्यसभा में पहुंचने का पूरा श्रेय सोनिया को दिया

नईदिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा के लिए अपने चुनाव का श्रेय पार्टी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी को दिया है। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने उन्हें अपने पूरे राजनीतिक करियर में लोगों की सेवा करने के लगातार मौके दिए हैं। पत्रकारों से बात करते हुए

खड़गे ने कहा कि यह मेरा 13वां चुनाव है। मैं सोनिया गांधी का आभारी हूं। उन्होंने मुझे लोगों की सेवा करने के मौके दिए हैं। खड़गे उन चार उम्मीदवारों में शामिल थे जिन्हें गुरुवार को कर्नाटक से राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुना गया। नाम वापस लेने की समय-सीमा खत्म होने के बाद नतीजे की पुष्टि हुई, क्योंकि चार खाली सीटों के लिए मुकाबले में केवल चार उम्मीदवार ही बचे थे, जिससे 18 जून को होने वाली वोटिंग की ज़रूरत नहीं रही। उच्च सदन में खड़गे के साथ शामिल होने वालों में मंसूर अली खान, कांग्रेस के मीडिया और प्रचार विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा, एम. नागराजा शामिल हैं।

मीनाक्षी नटराजन की याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज

नईदिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश से कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग द्वारा उनके नामांकन को रद्द किए जाने के फैसले को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस याचिका पर सुनवाई नहीं

करना चाहते और इसे खारिज किया जाता है। न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति अतुल एस चंदुरकर की पीठ ने कहा, एक बार नामांकन खारिज हो जाने के बाद चुनाव आयोग के पास जाने के अलावा और कोई उपाय नहीं होता है। कोर्ट ने पूछा कि क्या न्यायालय का ऐसा कोई निर्णय है, जिसमें हमने इस चरण में हस्तक्षेप किया हो? सुप्रीम कोर्ट द्वारा याचिका किए जाने के बाद कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन ने कहा कि यह कोई उनके लिए व्यक्तिगत झटका नहीं है। यह भारतीय लोकतंत्र और भारत के संविधान के लिए झटका है। मैंने शुरू में ही कहा था कि इलेक्शन कमीशन की सरकार के सांठगांठ है।

ममता बनर्जी की आंखों पर पट्टी बंधी हैं : शाइना एनसी

मुंबई। शिवसेना नेता शाइना एनसी ने टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के बयान पर कहा कि ममता बनर्जी की आंखों पर पट्टी बंधी हुई हैं। वे समझना ही नहीं चाहती हैं कि जो भ्रष्टाचार, सिंडीकेट राज और जिस अहंकार से अभिषेक बनर्जी पार्टी को चला रहे हैं, उसके

कारण लोग (टीएमसी से) बाहर जा रहे हैं। कल्याण बनर्जी एक वरिष्ठ नेता हैं, 4 बार लोकसभा में सांसद रहे हैं और जब वो यह उजागर करते हैं, तो शायद इस कारण से जनता ने बाहर आकर उनको चोर बुलाया है। टीएमसी के बागी सांसद जगदीश बर्मा बसुनिया ने कहा कि अगर हमारे बड़े नेता की सुरक्षा ही पक्की नहीं है, तो कैसी सुरक्षा की उम्मीद कर सकते हैं? हमने 2019 में आवाज़ उठाई थी और बड़ी बैठकों में अपनी बात रखी थी, लेकिन वह सुनती नहीं हैं। अगर कोई ज़्यादा बोलता है, तो उसे किनारे कर दिया जाता है; उन्हें उनके पद से हटा दिया जाता है। बोलने की आज़ादी नहीं है। एक सांसद के तौर पर मेरे पास कोई आज़ादी नहीं है।

ममता बनर्जी को पत्र लिखने की खबर झूठी : काकोली घोष

कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस की बागी सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने शुक्रवार को इस बात से इनकार किया कि उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को कोई पत्र लिखकर पूर्व राज्यसभा सदस्य इमरान के खिलाफ जांच की मांग की हो। यह आरोप लगाया गया था कि इमरान के

बांग्लादेश में सक्रिय चरमपंथी समूहों से संबंध हैं। उन्होंने एक्स पर कहा कि मैंने पश्चिम बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री को किसी भी मुद्दे पर कोई पत्र नहीं लिखा है, जैसा कि मीडिया में फैलाया जा रहा है। मैं इस खबर से किसी भी तरह के संबंध से इनकार करती हूं। इससे पहले खबर आई थी कि दस्तीदार ने इमरान के खिलाफ अधिकारी और विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया था कि इमरान, जिन्हें पूर्व टीएमसी सरकार के समर्थन से उच्च सदन के लिए नामित किया गया था, उनके चरमपंथी समूहों से संबंध हैं। पत्र में कहा गया, पश्चिम बंगाल की अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ कुछ रणनीतिक रूप से संवेदनशील इलाकों जिसमें सिलीगुड़ी कॉरिडोर क्षेत्र भी शामिल है

अमेठी पंचायत वोटर लिस्ट से स्मृति ईरानी का नाम गायब

लखनऊ। अमेठी ज़िले के मेदान मवाई गाँव की पंचायत वोटर लिस्ट से पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का नाम हट गया है, जबकि उस इलाके की लोकसभा और विधानसभा वोटर लिस्ट में उनका नाम मौजूद है। अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी। अमेठी के ज़िला मजिस्ट्रेट संजय

चौहान ने कहा कि इस मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। वर्ष 2019 से 2024 तक लोकसभा में अमेठी का प्रतिनिधित्व करने वाली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की नेता स्मृति ईरानी ने 2019 का लोकसभा चुनाव जीतने के बाद गौरीगंज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मेदान मवई गांव में अपना आवास बनाया। वह गांव की मतदाता के रूप में भी पंजीकृत हैं और उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान किया था। यह मामला 10 जून को पंचायत मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद सामने आया, जिसमें उनका नाम शामिल नहीं था। स्मृति ईरानी का नाम हटाने के पीछे के कारण के बारे में पूछे जाने पर जिलाधिकारी ने बताया कि जांच के आदेश दे दिए गए हैं और रिपोर्ट आने के बाद सही कारण स्पष्ट होगा।

टीएमसी का कांग्रेस में विलय या आत्म-तर्पण?

अजय बोकिल

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में करारी मात खाने और उसके बाद तार-तार हो रही ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस पार्टी के अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में संभावित विलय की चर्चाएं जोरों पर हैं। यह विलय कैसे, कब और किन शर्तों पर होगा, होगा भी या नहीं, यह टीएमसी का आईएनसी में विलीनीकरण होगा या फिर आत्म-तर्पण होगा, इन सब सवालों के जवाब देर-सवेर मिलेंगे। लेकिन भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से लोगों का टूटकर नई पार्टी बनाने और कुछ समय तक जनसमर्थन के सागर में हाथ-पैर मारने की नाकाम अथवा आंशिक रूप से सफल कोशिशों के बाद वापस अपनी मूलगंगा में तिरोहित हो जाने का इतिहास बहुत पुराना है।

1885 में अपनी स्थापना से लेकर 2026 तक 63 बार कांग्रेस से अलग होकर इसके नेताओं ने अपनी नई पार्टियां बनाई हैं। इनमें से केवल 8 पार्टियां अपने दम पर अथवा किसी गठबंधन के साथ सत्ता के सिंहासन तक पहुंचीं और कुल 13 पार्टियां किसी तरह अपना वजूद बचाए हुए हैं। बाकी काल के गाल में समा गईं। इनमें से भी अलग बनी केरल कांग्रेस के कई टुकड़े हो चुके हैं, जबकि कुछ ने भाजपा अथवा वाम दलों का दामन थाम लिया है।

ऐसे में पश्चिम बंगाल में लगातार 15 साल तक सत्ता में रही तृणमूल कांग्रेस का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलीन होने पर क्या हश्र होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। इस विलीनीकरण कथा का अंत जानते हुए भी यदि ममता बनर्जी कोलकाता में अपनी पार्टी को बिखरने से बचाने के उपाय करने की जगह दिल्ली में रुककर अपने पुराने घर कांग्रेस में वापसी की गुहार लगा रही हैं, तो इसी से समझा जा सकता है कि कभी दबंग नेत्री कहलाने वाली और कांग्रेस को ठेंगे पर रखने वाली ममता बनर्जी की मानसिक दशा क्या है। घर में लगी आग को बुझाने के बजाय वे दिल्ली में भाजपा का घर राख करने का शेखचिल्ली सपना देख रही हैं।

दिलचस्प बात यह है कि राष्ट्रीय मुख्यधारा की पार्टी कांग्रेस से अलग होकर नया दल बनाने और नाकाम होने

के बाद घर वापसी की मजबूरी के पीछे भी नेताओं की अपना वजूद बचाने की जद्दोजहद ही मुख्य कारण रही है। ममता बनर्जी को ही लें तो 1998 में उन्होंने अपना राजनीतिक वजूद चमकाने के लिए कांग्रेस से अलग होकर तृणमूल कांग्रेस बनाई और सियासी दृष्टि से वे सफल भी रहीं। लेकिन हाल के चुनावों में करारी पराजय के बाद वे खुद इतनी असहाय महसूस करने लगीं कि उन्हें लगने लगा कि कांग्रेस की छत ही उनकी राजनीतिक लाज बचा पाएगी। यह हताशा-जनित प्रतिशोध का विरल उदाहरण है।

यूं भी कांग्रेस से अलग होने के पीछे नेताओं की राजनीतिक महत्वाकांक्षा ही प्रेरक तत्व रही है। जब इन नेताओं को लगने लगता है कि वे अजेय प्रादेशिक क्षत्रप हैं और राष्ट्रीय पार्टी का छत्र छोड़कर खुद अपनी सल्तनत कायम कर सकते हैं, तो वे अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं में क्षेत्रीय अस्मिता, स्थानीय मुद्दों और जनाकांक्षाओं का तड़का लगाकर अपनी सूबाई फौज तैयार करते हैं, जो मुख्यत: व्यक्ति-निष्ठा और सत्ता-स्वार्थ में पगी होती है। इनका अपना कोई अलग वैचारिक आधार या आग्रह नहीं होता। ऐसी पार्टियों में व्यक्ति का चमत्कार ही मुख्य कारक होता है। जैसे ही संबंधित नेता का जादू खत्म होता है, पार्टी धड़ाम से जमीन पर आ जाती है। सत्ता की सलाइन हटते ही पार्टी में बिखराव शुरू हो जाता है। ऐसे में ममता जैसे नेताओं को लगने लगता है कि अब उसी उद्गम-स्थल पर फिर से राजनीतिक आचमन करना चाहिए, जहां से यह सफर शुरू हुआ था। राजनीतिक हलकों में चर्चा यह भी है कि बंगाल चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस की ओर से दबी जुबान में विलीनीकरण का प्रस्ताव मूल पार्टी से अलग हुई वाईएसआर कांग्रेस और एनसीपी (शरद पवार) को भी दिया गया है। लेकिन इनके वापस कांग्रेस में लौटने की संभावना कम ही है। इसका मूल कारण भी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा ही है। अलग पार्टी बनाने और उसे सत्ता में विराजित करने के बाद कांग्रेस से विलगित नेता खुद को निरंकुश सूबेदार मानने लगते हैं, क्योंकि सत्ता का असली स्वाद भी इसी निरंकुशता में है। ऐसे में किसी 'बादशाह' के अधीन काम करना उनकी फितरत में नहीं बैठता।शरद पवार व्हीलचेयर पर चलने के बाद भी यह माहौल बनाए रखते हैं कि उनमें अभी भी खम ठोंकने का दम है। लिहाजा वे कभी भाजपा तो कभी कांग्रेस को खुश करने वाले बयान देते रहते हैं। राजनीति में सत्ता ही अंतिम लक्ष्य होती है। सत्ताविहीन सियासी दल विपक्ष की भूमिका निभाते जरूर हैं, लेकिन कई बार उसका महत्व राजनीतिक मनोरंजन से ज्यादा नहीं होता। जहां तक विभाजन की बात है, तो खुद कांग्रेस भी दो बार विभाजित हो चुकी है।

बलौदाबाजार के सीमेंट प्लांट में ड्राइवर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत

परिजन और ड्राइलर यूनियन ने जांच और मुआवजे की मांग की है. मेन गेट पर बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी.

परिजनों और ड्राइवर यूनियन का हंगामा

बलौदाबाजार। सीमेंट संयंत्र में एक ट्रक चालक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। परिजनों और ड्राइवर यूनियन ने मामले की जांच की मांग की है। परिजन मुआवजा देने की मांग को लेकर भी अड़े हुए हैं। ड्राइवर यूनियन ने बड़े आंदोलन की भी चेतावनी दी है।

मृतक चालक की पहचान संतोष मानिकपुरी के रूप में हुई है, जो सीमेंट लोड करने के लिए प्लांट के भीतर गया था। बताया जा रहा है कि वह पिछले दो दिनों से संयंत्र परिसर में मौजूद था। इसी दौरान उसकी मौत हो गई। घटना सामने आने के बाद परिजनों और ड्राइवर यूनियन में भारी नाराजगी है। मृतक के परिजनों का आरोप है कि घटना के बाद उन्हें समय पर जानकारी नहीं दी गई। उनका कहना है कि जब तक उन्हें मौत की सूचना मिली, तब तक कई प्रक्रियाएं आगे बढ़ चुकी थीं।परिवार का आरोप है कि यदि घटना गंभीर थी तो सबसे पहले परिजनों को सूचित किया जाना चाहिए था। इसी बात को लेकर परिवार में नाराजगी और अविश्वास दोनों बढ़ गए हैं। परिजनों का कहना है कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे मामले को जल्द से जल्द खत्म करने का प्रयास किया जा रहा हो।

घटना के बाद ड्राइवर यूनियन ने भी मोर्चा खोल दिया है। यूनियन नेताओं का कहना है कि यह सिर्फ एक व्यक्ति की मौत का मामला नहीं है बल्कि पूरे परिवहन समुदाय की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है।

यूनियन का आरोप है कि कई औद्योगिक इकाइयों में ट्रक चालकों को घंटों और कई बार दिनों तक इंतजार करना पड़ता है, लेकिन उनके लिए मूलभूत सुविधाओं का अभाव रहता है। ड्राइवर यूनियन के प्रदेश प्रभारी संतोष देवांगन का कहना है कि यदि चालक दो दिनों से परिसर के भीतर था तो उसकी सुरक्षा, स्वास्थ्य और आवश्यक सुविधाओं की जिम्मेदारी किसकी थी, इसका जवाब प्रबंधन को देना होगा। मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस भी सक्रिय हुई है। क्षेत्र के एसडीओपी कौशल किशोर वासनिक ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और मौत के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए आवश्यक कानूनी प्रक्रिया अपनाई जा रही है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।जांच पूरी होने से पहले किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा। परिजनों और ड्राइवर यूनियन ने साफ कर दिया है कि वे केवल आश्वासन से संतुष्ट नहीं होंगे।

10 करोड़ के गांजा के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार

ओडिशा से ट्रक में भरकर ले जा रहे थे यूपी

बलरामपुर। बलरामपुर जिले में गांजा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने भारी मात्रा में तस्करी किए जा रहे गांजा की खेप को जब्त किया है, जिसकी कीमत करोड़ों में आंकी गई है। यह खेप ट्रक में भरकर ओडिशा के सोनपुर से उत्तरप्रदेश ले जाई जा रही थी। मामले में 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है।

जानकारी के मुताबिक, पूरा मामला बसंतपुर थाना का है। ओडिशा के सोनपुर से एक ट्रक (ऋछ 14 त्त 9078) में भारी मात्रा में गांजा लेकर लाया जा रहा था। शातिर तस्करों ने रात के अंधेरे का फायदा उठाकर तस्करी की प्लानिंग की थी। मुखबीर से सूचना के बाद पुलिस एक्टिव हो गई। पुलिस ने नाकेबंदी कर शुक्रवार तड़के 3 बजे एक संदिग्ध ट्रक को रुकवाया। आरोपियों ने पूछताछ में अपना नाम लोकेश शर्मा और आमिर अंसारी बताया। दोनों उत्तरप्रदेश के रहने वाले हैं। जब पुलिस ने ट्रक की जांच की तो उनके होश उड़ गए। बोरियो में भरा करीब 1941।110 किलो गांजा बरामद किया गया। इसकी अनुमानित कीमत करीब 10 करोड़ रुपये है। मौके पर सायबर सेल की टीम भी मौजूद रही। शुरूआती जांच में गांजा तस्करी के खिलाफ अबतक की यह सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। बरामद गांजे की कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस गांजा तस्करों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवई की गई है। दोनों कों कोर्ट में पेश करने की तैयारी है।

बीच रास्ते में की जाती थी कोयले की अदला-बदली, 6 आरोपी जेल

बिलासपुर। बिलासपुर में कोयले की हेराफेरी करने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। भाटिया एनर्जी एंड कोल बेनिफिकेशन के संचालकों ने कोयले की जांच के दौरान इस हेराफेरी को पकड़ा, जिसके बाद मामला पुलिस को सौंपा गया। इस मामले में सकरी पुलिस ने आरोपी गिरोह में शामिल कोलडिपो संचालक, सुपरवाइजर, ट्रक मालिक व ड्राइवर सहित 6 लोगों के खिलाफ जुर्म दर्ज किया है। वहीं तीन ड्राइवरों सहित 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

दरअसल, लोखंडी भाटिया एनर्जी एंड कोल बेनिफिकेशन के कारखाना प्रबंधक आरके पाण्डेय ने रिपोर्ट लिखाई है कि 9 जून को दीपका कोल माइंस से एफ/ जी ग्रेड का कोयला भाटिया एनर्जी एण्ड बेनिफिकेशन के लिए मंगवाया गया था। 10 जून को सुबह 6 से 7 बजे के बीच ट्रक क्रमांक सीजी 10 बीक्यू. 8285, चालक उज्जैन अंसारी, ट्रक क्रमांक सजी 12 बीएल, 6247 चालक आशिक हुसैन, ट्रक क्रमांक सीजी 12 बीएल, 6251 चालक फजल अंसारी कोयला लेकर आए, जिसे लैब से चेक करने पर एफ/ जी ग्रेड का कोयला नहीं होना पाया गया।

पूछताछ में ड्राइवरों ने दीपका से आते समय रतनपुर गतौरी स्थित बालाजी कोल ट्रेडिंग एण्ड कंस्ट्रक्शन के संचालक दिलीप कुमार एवं सुपरवाइजर से मिलीभगत कर एफ/ जी ग्रेड के कोयले को चोरी कर बेचना और उसकी जगह मिलावटी कोयला भर देना बताया। इससे कंपनी को 25 लाख से अधिक का आर्थिक नुकसान हुआ है।

छात्रवृत्ति के बाद भी शासकीय स्कूलों में घट रही छात्रों की संख्या

नि:शुल्क पाठ्य पुस्तक, गणवेश, मध्यान्ह भोजन का भी कोई असर नहीं

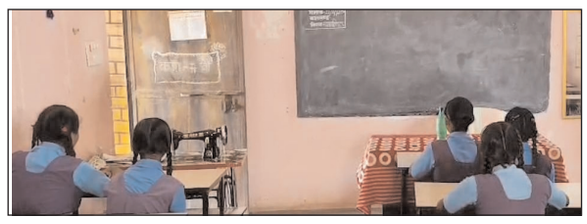

महासमुंद। सरकार बच्चों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए हर साल करोड़ों रुपये खर्च कर रही है। छात्रों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, गणवेश, मध्यान्ह भोजन, छात्रवृत्ति, बालिकाओं को साइकिल और स्कूल भवन जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं, ताकि आर्थिक कारणों से कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे, लेकिन महासमुंद जिले के सरकारी आंकड़े ही एक चिंताजनक तस्वीर पेश कर रहे हैं। जिले में पिछले पांच वर्षों में शासकीय स्कूलों में विद्यार्थियों की दर्ज संख्या लगातार घटती जा रही है। पालकों और शिक्षकों का मानना है कि शिक्षकों की कमी और गैर-शैक्षणिक कार्य इसका बड़ा कारण है, जबकि शिक्षा विभाग इस पर स्पष्ट जवाब देने से बचता नजर आ रहा है। महासमुंद जिले में कक्षा पहली से बारहवीं तक के विद्यार्थियों के लिए कुल 1956 शासकीय स्कूल संचालित हैं। इनमें 1276 प्राथमिक, 492 माध्यमिक, 62 हाई स्कूल और 126 हायर सेकेंडरी स्कूल शामिल हैं। विद्यार्थियों की संख्या पर नजर डालें तो वर्ष 2021-22 में सरकारी स्कूलों में 1 लाख 70 हजार 980 छात्र-छात्राएं दर्ज थे। यह संख्या वर्ष 2022-23 में घटकर 1 लाख 62 हजार 310 हो गई।

वर्ष 2023-24 में 1 लाख 54 हजार 809, वर्ष 2024-25 में 1 लाख 48 हजार 57 और वर्ष 2025-26 में घटकर 1 लाख 41 हजार 503 रह गई। पांच वर्षों में सरकारी स्कूलों से कुल 29 हजार 477 विद्यार्थियों की कमी दर्ज की गई है। पालकों का कहना है कि स्कूलों में पर्याप्त सुविधाओं और शिक्षकों की कमी के कारण वे अपने बच्चों को निजी स्कूलों में भेजने को मजबूर हैं। शिक्षक भी सरकारी स्कूलों में घटती छात्र संख्या के पीछे शिक्षकों की कमी और गैर-शैक्षणिक कार्यों का दबाव जिम्मेदार मान रहे हैं। उनका कहना है कि विभिन्न शासकीय कार्यों में व्यस्त रहने के कारण शिक्षक विद्यार्थियों को पर्याप्त समय नहीं दे पाते।

तेज आंधी-बारिश से गिरा मोबाइल टॉवर

बालोद। जिले में आई तेज आंधी और बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया। अचानक बदले मौसम ने कई क्षेत्रों में भारी नुकसान पहुंचाया। भेड़िया नवागांव क्षेत्र में स्थित बीएसएनएल का मोबाइल टॉवर गिर गया।

राहत की बात रही कि टॉवर आबादी क्षेत्र से दूर खेत में गिरा, जिससे जनहानि नहीं हुई। वहीं बिजली के खंभे और 50 से अधिक पेड़ भी धराशायी हो गए। इसके चलते कई गांवों में ब्लैकआउट जैसे हालात बन गए हैं। तेज हवाओं के कारण जगह-जगह विशाल पेड़ सड़कों पर गिर गए, जिससे आवागमन बाधित हो गया। कई मार्गों पर वाहनों की आवाजाही घंटों तक प्रभावित रही। भेड़िया नवागांव में बीएसएनएल का मोबाइल टॉवर भी तेज आंधी की चपेट में आकर गिर गया। मोबाइल नेटवर्क ठप होने से लोगों को एक-दूसरे से संपर्क करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बिजली आपूर्ति बाधित होने से घरों में अंधेरा छा गया। मौसम में बदलवा का असर बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई। कई क्षेत्रों में विद्युत लाइनें क्षतिग्रस्त हो गई। ग्रामीणों को अंधेरे और अन्य परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

तेज आंधी के दौरान कई मकानों की छतों को भी नुकसान पहुंचा है। घटना की जानकारी मिलते ही बिजली विभाग और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंच गई।

पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में घेराबंदी कर दो मवेशी तस्करों को पकड़ा

माजदा गाड़ी से 19 गोवंश बरामद

आरंग। क्षेत्र में मवेशी तस्करी के अवैध काले कारोबार के खिलाफ आरंग थाना पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर फिल्मी स्टाइल में घेराबंदी कर एक माजदा वाहन से तस्करी किए जा रहे 19 मवेशियों को मुक्त कराया है। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश और स्थानीय क्षेत्र के दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि मामले से जुड़े अन्य आरोपियों की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। आरंग थाना प्रभारी हरीश साहू ने बताया कि पुलिस को मुखबिर से पुख्ता सूचना मिली थी कि एक बड़े वाहन में मवेशियों को अवैध रूप से ले जाया जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम ने तत्काल हरकत में आते हुए ग्राम गुदगुदा के पास मुख्य मार्ग पर नाकेबंदी कर दी। तभी सामने से आ रही संदिग्ध माजदा गाड़ी (वाहन क्रमांक- क्क83 ष्टञ्ज 8790) को पुलिस ने रोकने का इशारा किया। पुलिस बल को सामने देखकर वाहन का चालक घबरा गया और गाड़ी छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाते हुए मौके से फरार हो गया।

जब पुलिस टीम ने लावारिस हालत में छूटे माजदा वाहन की तलाशी ली, तो अंदर का नजारा देखकर हर कोई दंग रह गया। तस्करों ने क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए वाहन के भीतर 19 मवेशियों को बेहद अमानवीय तरीके से ठूंस-ठूंस कर भरा था। बेजुबान जानवरों के लिए न तो पैर हिलाने की जगह थी और न ही उनके लिए चारा-पानी की कोई व्यवस्था की गई थी। पुलिस ने तुरंत सभी 19 मवेशियों को वाहन से सुरक्षित बाहर निकाला और उन्हें राहत पहुंचाई। पुलिस ने अवैध परिवहन में प्रयुक्त माजदा वाहन को जब्त करते हुए आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4, 6, 10 और मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 66/192 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच शुरू की।

मामले की गंभीरता को देखते हुए विवेचना के दौरान पुलिस ने 11 जून 2026 को दो मुख्य आरोपियों को दबोच लिया।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

कोरिया में नवनिर्मित सड़क एक महीने में उखड़ने लगी

कोरिया। जिले की ग्राम पंचायत सरडी में बनाई गई सीसी रोड महज एक महीने बाद ही सवालों के घेरे में आ गई है। आरोप है कि एक महीने के अंदर ही यह जगह-जगह से उखड़ने लगी है। गांव की सुविधा और बेहतर आवागमन के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के तहत यह सड़क करीब 36 लाख रुपये की लागत से बनाई गई थी। ग्रामीणों के अनुसार सड़क की सतह पर जगह-जगह बड़ी दरारें दिखाई दे रही हैं, कई स्थानों पर गिट्टियां बाहर निकल चुकी हैं। वहीं सड़क किनारे बनाई गई रिटर्निंग वॉल में भी दरारें पड़ गई हैं। इसको लेकर ग्रामीणों में निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर नाराजगी है। मामले को लेकर जब संबंधित विभाग के कार्यपालन अभियंता दिलीप कुमार मिंज से जानकारी ली गई तो उन्होंने कैमरे के सामने बयान देने से इनकार कर दिया। हालांकि उन्होंने ऑफ कैमरा कहा कि शिकायत मिलने के बाद उन्होंने मौके का निरीक्षण किया था और उन्हें कोई बड़ी गड़बड़ी नहीं मिली। वहीं मौके की तस्वीरें और ग्रामीणों के आरोप विभागीय दावों पर सवाल खड़े कर रहे हैं।

फीस लेने के बाद भी परीक्षा से वंचित रखने का आरोप

सूरजपुर। तिलसिंवा स्थित एक पैरामेडिकल संस्थान पर छात्रों ने भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का गंभीर आरोप लगाया है। संस्थान में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं ने संचालक और प्राचार्य के खिलाफ थाना सूरजपुर और संयुक्त जिला कार्यालय में लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। छात्रों का आरोप है कि उनसे पूरे कोर्स की फीस लेने के बावजूद मुख्य परीक्षा में शामिल नहीं कराया गया, जिससे उनका एक शैक्षणिक वर्ष बर्बाद हो गया है। स्टूडेंट्स ने बताया कि तिलसिंवा स्थित पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में डीएमएलटी और बीएमएलटी पाठ्यक्रम में अध्ययन कर रहे छात्रों से पूरी फीस जमा कराई गई थी। एडमिशन के समय बताया गया था कि सभी क्लासरूम में कक्षाएं लगती हैं। लेकिन एडमिशन लेने के बाद पता चला कि एक रूम में क्लास लगाई जाती है, जिसमें लैब भी अटैच है। सभी स्टूडेंट्स ने पैसा दिया है। मैंने बीस हजार चार सौ रुपए दिया गया है। हमें कहा गया था कि आपकी फीस में एक्जाम फीस माइनस की जाएगी।

झमाझम बारिश से मिली राहत, किसानों के चेहरे खिले

नारायणपुर। जिले में आखिरकार मानसून ने दस्तक दे दी है। सुबह से हो रही झमाझम बारिश ने जहां कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी और उमस से लोगों को राहत पहुंचाई है, वहीं मानसून आधारित खेती करने वाले किसानों के लिए यह बारिश किसी खुशखबरी से कम नहीं है।पहली बारिश के साथ ही खेतों और किसानों के मन में नई उम्मीदों का संचार हुआ है। नारायणपुर जिले में शुक्रवार सुबह से मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया। आसमान में घने बादल छाए रहे और कई क्षेत्रों में लगातार बारिश दर्ज की गई। बीते कुछ दिनों से तेज धूप और उमस भरी गर्मी से परेशान लोग बारिश शुरू होते ही राहत महसूस करने लगे। बारिश के कारण तापमान में गिरावट आई और वातावरण पूरी तरह से सुहावना हो गया।जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में मानसून की पहली बारिश का लोगों ने उत्साहपूर्वक स्वागत किया। बच्चों ने बारिश का आनंद लिया तो वहीं बुजुर्गों ने भी लंबे समय बाद मौसम में आई ठंडक को राहत भरा बताया। सड़कों, गलियों और खेतों में बारिश का पानी दिखाई देने लगा है।

कांकेर में मनरेगा कार्य के दौरान आकाशीय बिजली का कहर

कांकेर। कांकेर जिले के अंतागढ़ थाना क्षेत्र के कलगांव में आकाशीय बिजली गिरने से बड़ा हादसा हो गया। मनरेगा के तहत तालाब निर्माण कार्य में लगे मजदूरों पर बिजली गिरने से उपसरपंच धनराज पटेल समेत तीन लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि पांच मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों का अंतागढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज जारी है। घटना के बाद पूरे इलाके में शोक और दहशत का माहौल है। जानकारी के मुताबिक कलगांव में मनरेगा योजना के तहत तालाब निर्माण कार्य चल रहा था।सुबह करीब 6 बजे अचानक मौसम बदल गया और तेज गर्जना के साथ बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए मजदूर पास के एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। इसी दौरान आकाशीय बिजली पेड़ के पास गिरी और उसकी चपेट में कई मजदूर आ गए। हादसे में ग्राम के उपसरपंच धनराज पटेल सहित तीन मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन महिलाएं और दो पुरुष गंभीर रूप से घायल हो गए।

बैगा आदिवासी समाज का आबकारी अधिकारियों पर गंभीर आरोप

कवर्धा। कबीरधाम जिले में बैगा आदिवासी समाज ने आबकारी विभाग के दो अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाया है। बैगा आदिवासियों का कहना है कि आबकारी अधिकारी उन पर बेवजह कार्रवाई करते हैं और उनसे रुपयों की भी वसूली की जाती है। गुरुवार को छत्तीसगढ़ आदिवासी विकास परिषद जिला शाखा कबीरधाम के बैनर तले छेतीकेसर गांव के बैगा आदिवासी कलेक्ट्रेट पहुंचे और ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है।समाज के लोगों ने आरोप लगाया है कि विभाग के एक पुरुष एवं एक महिला एसआई द्वारा बैगा समुदाय के लोगों को कथित रूप से झूठे मामलों में फंसाया जा रहा है तथा उनसे अवैध वसूली की जा रही है। समाज के प्रतिनिधियों का कहना है कि महुआ शराब से जुड़े मामलों में वास्तविक मात्रा से अधिक मात्रा दर्शाकर प्रकरण दर्ज किए जा रहे हैं। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि कई ग्रामीणों से कोरे कागजों पर हस्ताक्षर कराए गए और बाद में उनके खिलाफ गंभीर मामले तैयार कर दिए गए।

सुशासन तिहार में शिकायत के बाद जागा प्रशासन

तालाब पाटकर बनाए गए अवैध पहाड़ ध्वस्त, रसूखदार माफियाओं को नोटिस

आरंग। कुटेला गांव में ऐतिहासिक तालाब को पाटकर माफियाओं द्वारा खड़े किए गए रेत के 'अवैध पहाड़ों पर खबर प्रकाशित करने और 'सुशासन तिहार 2026' में शिकायत के बाद शासन-प्रशासन में हड़कंप मच गया। खनिज और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने समोदा, कुरूद, मोहमेला और कुटेला में ताबड़तोड़ छापेमारी कर सैकड़ों ट्रैक्टर अवैध रेत ज़ब्त की। साथ ही रसूखदार माफियाओं को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के प्रतिबंध से ठीक पहले चांदी काटने की फिराक में बैठे रेत चोरों पर प्रशासन ने सर्जिकल स्ट्राइक की है। संचालक खनिज प्रशासन राजेश मालवे ने तुरंत कड़े निर्देश जारी कर एक हाई-प्रोफाइल संयुक्त टीम का गठन किया, जिसमें सहायक खनिज अधिकारी उमेश भार्गव एवं टीम, राजस्व विभाग से नायब तहसीलदार (समोदा) गजानंद सिदार, स्थानीय पटवारी और कोटवार शामिल रहे। इस दौरान ग्राम सरपंच कमलेश्वरी संतोष जलक्षत्री, पंच गण सहित ग्रामीण बड़ी संख्या में उपस्थिति रहे। जब प्रशासनिक अमला ग्राम कुटेला-चिखली मुख्य सड़क के किनारे पहुंचा, तो 'शासकीय भूमि और प्रस्तावित तालाब के हिस्से में बिना किसी अनुमति के सैकड़ों ट्रैक्टर खनिज रेत का अवैध भंडारण (डंप) पाया गया, जिसे ग्रामीणों की मौजूदगी में तुरंत ज़ब्त कर लिया गया। प्रशासन ने इस बार न सिर्फ रेत ज़ब्त की, बल्कि माफियाओं के हौसले पस्त करने के लिए उनके 'सप्लाई रूट' को ही नेस्तनाबूद कर दिया। डंपिंग यार्ड तक भारी वाहनों को पहुंचाने के लिए माफियाओं ने जो 'रैम रास्ता' (अवैध मार्ग) बनाया था, उसे जेसीबी मशीन से खोदकर पूरी तरह काट दिया गया, ताकि भविष्य में वहां अवैध भंडारण न हो सके।

शिकायत के बाद भी नहीं हुई सुनवाई, तो चंदा और श्रमदान से खुद बना रहे सड़क

मोहला-मानपुर। अंबागढ़ चौकी विकासखंड के ग्राम दक्कोटोला के ग्रामीण दशकों से पक्की सड़क की सुविधा से वंचित है और कच्ची सड़क से आवागमन को मजबूर है। शासन और प्रशासन को आवेदन देने के बाद भी जब कोई सुनवाई नहीं हुई, तो ग्रामीण खुद चंदा इकट्ठा कर आपसी श्रमदान से माउंटेन मैन मांझी की तर्ज पर सड़क बनाने में जुटे हैं।

महाराष्ट्र के बॉर्डर पर स्थित दक्कोटोला गांव में आलम ये हैं कि रोजाना सुबह और शाम दो पालियों में प्रत्येक घर से महिला-पुरुष ग्रामीण हाथों में फावड़ा, कुदाल और अन्य आवश्यक सामग्री लेकर गांव से एक ओर चिल्हाटी मुख्य मार्ग तथा दूसरी ओर ग्राम खुर्सीटीकुल को जोड़ने वाले, कच्चे और पथरीले मार्ग में जुटते हैं। साथ ही इस पथरीले सड़क में मुरूम और अन्य मटेरियल से पटाव कर सड़क को आवागमन लायक बनाते हैं, ताकि सुरक्षित व व्यवस्थित आवाजाही सुनिश्चित हो सके। यही नहीं ये ग्रामीण सड़क बनाने के लिए आपसी सहमति से गांव के प्रत्येक घर से 500-500 रुपए चंदा जुटाकर आवश्यक आर्थिक व्यवस्था कर रहे हैं।

ग्रामीणों की माने तो हर साल बारिश से पहले वे इसी तरह से चंदे की राशि और आपसी श्रमदान से गांव की इस कच्ची सड़क को संधारित करते हैं। ग्रामीणों के मुताबिक, उन्हें शासन और प्रशासन के सामने लिखित और मौखिक गुहार लगाते दो दशक से अधिक समय हो चुका है, लेकिन जिम्मेदार अफसर और जनप्रतिनिधि आज तक इस गांव को जोड़ने के लिए एक पक्की सड़क तक बनवा नहीं पाए। ग्रामीणों को माकूल सड़क के अभाव में अपने गांव से लगे ग्राम पंचायत खुर्सीटीकुल तक राशन लेने के लिए दूसरे मार्ग से लंबी दूरी तय कर आवाजाही करनी पड़ती है।

बारिश के दिनों में तो हालात और बद्तर हो जाता है, जब गांव की ये सड़क दलदल में बदल जाती है। इसके कारण स्कूली बच्चों का स्कूल आवागमन और आमजनों की सामान्य आवाजाही भी किसी बड़े खतरे से कम नहीं होती।

संक्षिप्त समाचार

गीतमाला कार्यक्रम में वरिष्ठ कवि छबिलाल सोनी का हुआ सम्मान

रायपुर। नीरवंदन म्यूजिकल ग्रुप द्वारा मायाराम सुरजन हाल में गीतमाला कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें 24 गायकों द्वारा नए और पुराने गीतों की प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम शाम 5 बजे से रात्रि रात 11 बजे तक चलता रहा और उपस्थित श्रोता झूमने पर मजबूर हो गए। कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ कवि व समाजसेवी छबिलाल सोनी का मंच द्वारा सम्मान किया गया। आयोजन के संबंध में ग्रुप डायरेक्टर श्रीमती वंदना तिवारी एवं नीरज पांडे ने बताया कि यह ग्रुप का 6वां आयोजन था जिसमे बिलासपुर से भी गायक आये थे। यह ग्रुप नए और उभरते कलाकारों को मंच प्रदान करता है। ग्रुप का अगला कार्यक्रम 22 अगस्त को इसी जगह होगा। इस अवसर पर संस्था के संरक्षक श्याम मसंद, छत्तीसगढ़ी फिल्म के निर्माता व निर्देशक मोहित साहू, कार्यक्रम संयोजक मनोज मसंद, मुकेश सोनी, सलाहकार विजय जेसवानी, रत्न सोनी, शिव ठाकुर, बी श्रीनिवास राव, मंच संचालक नीरवंदन परिवार, तकनीकी सहायक कुनाल मरकाम के अलावा अन्य गायक कलाकार उपस्थित थे।

खरीफ सीजन के लिए रासायनिक उर्वरकों की दरें तय

रायपुर। खरीफ सीजन 2026 के लिए किसानों को समय पर और निर्धारित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कृषि विभाग ने विभिन्न रासायनिक उर्वरकों की विक्रय दरें निर्धारित कर दी हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि तय दर से अधिक कीमत वसूलने वाले विक्रेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उप संचालक कृषि ने बताया कि यूरिया की कीमत 266.50 रुपये प्रति बोरी निर्धारित की गई है। डीएपी उर्वरक कंपनी के अनुसार अधिकतम 1350 रुपये प्रति बोरी तक उपलब्ध होगा। वहीं एनपीके 12: 32: 16 की कीमत 1190 रुपये, 20: 20: 0: 13 की 1850 रुपये और 12: 26: 26 की 1990 रुपये प्रति बोरी तय की गई है। एमओपी (पोटाश) उर्वरक 1975 रुपये प्रति बोरी की दर से मिलेगा। इसके अलावा एसएसपी पाउडर 551 रुपये, एसएसपी दानेदार 591 रुपये, जिंकटेड एसएसपी 576 रुपये तथा टीएसपी 1300 रुपये प्रति बोरी की दर से उपलब्ध होगा। आधुनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए इफको नैनो यूरिया (500 मिलीलीटर) 225 रुपये और नैनो डीएपी (500 मिलीलीटर) 600 रुपये में उपलब्ध कराया जाएगा। कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि निर्धारित दर से अधिक मूल्य वसूले जाने पर तत्काल नजदीकी कृषि कार्यालय में शिकायत करें।

ओटी टेक्नीशियन पदों की भर्ती के लिए आवेदन शुरू

रायपुर। ओटी टेक्नीशियन पदों की भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभ्यर्थी व्यापमं की वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन 3 जुलाई तक कर सकते हैं। आवेदन में त्रुटि सुधार 4 से 6 जुलाई तक किए जा सकेंगे। परीक्षा 30 अगस्त को संभावित है। परीक्षा रायपुर में ही होगी। संचालनालय द्वारा सरगुजा और बस्तर संभाग में कुल 15 पदों की भर्ती की जाएगी इसके लिए आवेदक को छत्तीसगढ राज्य का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी को जीव विज्ञान, भौतिक व रसायनशास्त्र विषय के साथ 12वीं उत्तीर्ण होने के साथ ही मान्यता प्राप्त संस्थान से ओटी/एनेस्थेसिया टेक्नीशियन पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल कौंसिल से जीवित पंजीयन होना चाहिए।

कम्युनिटी हॉल के जीर्णोद्धार के लिए 80 लाख स्वीकृत

रायपुर। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने जशपुर नगर पालिका में वशिष्ट कम्युनिटी हॉल के जीर्णोद्धार के लिए 80 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन मंत्री श्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने संचालनालय से इसकी मंजूरी के आदेश जारी कर दिए हैं। विभाग द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के अधोसंरचना मद से यह राशि मंजूर की गई है। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने जीर्णोद्धार कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए समय-सीमा में काम पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं।

रायपुर में सरकारी नौकरी पाने 15 जून से पहले करे आवेदन

रायपुर। रायपुर में जल संसाधन विभाग के अंतर्गत अनुरेखक (सिविल) के 35 पदों के लिए लिखित भर्ती परीक्षा हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 जून है और यह लिखित परीक्षा 2 अगस्त को संभावित है। अभ्यर्थी 15 जून तक व्यापमं की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी के पास एक विषय के रूप में रेखाचित्र (ड्रॉइंग) के साथ हायर सेकेंडरी स्कूल प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण या राज्य शासन द्वारा इस निमित्त मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा मंडल से हायर सेकेंडरी (तक) प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। चयनित अभ्यर्थियों को वेतन मैट्रिक्स 19500 - 62000, लेवल-4 के अनुसार वेतन प्रदान किया जाएगा। रायपुर में जल संसाधन विभाग के अंतर्गत अनुरेखक (सिविल) पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 35 अनुरेखक (सिविल) पदों को भरा जाएगा। यह अवसर उन अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है जो तकनीकी क्षेत्र में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं। अनुरेखक (सिविल) पद हेतु अभ्यर्थी को रेखा चित्र (ड्राइंग) विषय सहित हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अथवा राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त मंडल से समकक्ष योग्यता प्राप्त होना चाहिए।

छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए बिछा रेड कारपेट, 9,580 करोड़ रुपये के मिले प्रस्ताव

इन्वेस्टर कनेक्ट में हैदराबाद के निवेशकों को मुख्यमंत्री साय का न्योता, कई क्षेत्र में खुली 7,800 रोजगार की राह

रायपुर। छत्तीसगढ़ ने निवेश आकर्षित करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। हैदराबाद में आयोजित 'छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट' कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों की सात प्रमुख कंपनियों ने 9,580 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव दिए हैं, जिनसे 7,800 से अधिक रोजगार सृजित होने की संभावना है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने देश के प्रमुख उद्योगपतियों और निवेशकों को छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा विकसित भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में छत्तीसगढ़ तेजी से उभर रहा है और राज्य में निवेशकों के लिए 'रेड कारपेट' बिछा हुआ है। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री लखन लाल देवांगन सहित दक्षिण भारत के कई बड़े उद्योगपति, निवेशक और कारोबारी प्रतिनिधि मौजूद रहे।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि नई औद्योगिक नीति लागू होने के बाद दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु के साथ-साथ जापान और दक्षिण कोरिया में आयोजित इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य को 8 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। राज्य सरकार इन प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के लिए तेजी से कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ आज निवेश के लिए देश के सबसे बेहतर राज्यों में से एक बनकर उभर रहा है। राज्य में उद्योगों के लिए आसान प्रक्रियाएं, सिंगल विंडो व्यवस्था, बेहतर बुनियादी सुविधाएं और उद्योग अनुकूल नीतियां उपलब्ध हैं। उन्होंने निवेशकों को छत्तीसगढ़ में उद्योग स्थापित करने का आमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हैदराबाद ने आईटी, फार्मा, बायोटेक्नोलॉजी और एयरोस्पेस जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। छत्तीसगढ़ भी इन क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है और दोनों राज्यों के उद्योगपति एवं उद्यमी मिलकर नए अवसरों का लाभ उठा सकते हैं।

उन्होंने कहा कि मध्य भारत में स्थित छत्तीसगढ़ देश का सबसे उपयुक्त लॉजिस्टिक हब बनने की क्षमता रखता है। छत्तीसगढ़ सात राज्यों से घिरा हुआ है और 60 करोड़ से अधिक उपभोक्ताओं तक सीधी पहुंच प्रदान करता है। रेलवे नेटवर्क, भारतमाला परियोजना, एयर कार्गो सुविधाओं तथा खनिज संसाधनों की उपलब्धता उद्योगों के लिए इसे अत्यंत अनुकूल बनाती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ देश में ग्रीन स्टील को बढ़ावा देने वाले अग्रणी राज्यों में शामिल है। ऊर्जा क्षेत्र में राज्य को 3.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिससे प्रदेश देश के प्रमुख पावर हब के रूप में उभर रहा है।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने सात प्रमुख कंपनियों को छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए 'इन्विटेशन टू इन्वेस्ट' (ऑफर लेटर) प्रदान किए। इनमें डेटा सेंटर, सीमेंट, सेमीकंडक्टर एवं जीपीयू

इंफ्रास्ट्रक्चर, सौर ऊर्जा उपकरण निर्माण, वस्त्र, फार्मास्यूटिकल और डेयरी प्रसंस्करण क्षेत्रों की अग्रणी कंपनियां शामिल हैं।

सबसे बड़ा निवेश प्रस्ताव हाइपरनेक्स्ट डाटा सेंटर लिमिटेड की ओर से प्राप्त हुआ, जिसने छत्तीसगढ़ में भारत का पहला समर्पित डिजास्टर रिकवरी डेटा सेंटर कैंपस स्थापित करने के लिए 4,200 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव दिया। इस परियोजना से राज्य में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिलेगी और छत्तीसगढ़ डेटा सेंटर क्षेत्र का महत्वपूर्ण केंद्र बन सकेगा। इस परियोजना से लगभग 250 रोजगार सृजित होंगे।

फीग्रेड एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ने सीमेंट क्षेत्र में 2,912 करोड़ रुपये निवेश का प्रस्ताव दिया है, जिससे लगभग 4,000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। वहीं निवाई लैब्स प्राइवेट लिमिटेड ने 1,000 करोड़ रुपये के निवेश से एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस), जीपीयू इंफ्रास्ट्रक्चर, एडवांस कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर असेंबली से जुड़ी सुविधाएं विकसित करने का प्रस्ताव दिया। इससे राज्य में आधुनिक तकनीकी उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा एवं लगभग 200 रोजगार सृजित होंगे।

सौर ऊर्जा उपकरण निर्माण क्षेत्र की एसजी मार्ट लिमिटेड ने 700 करोड़ रुपये निवेश का प्रस्ताव दिया है, जिससे लगभग 450 लोगों को रोजगार मिल सकता है। श्री सरवणा मिल्स प्राइवेट लिमिटेड ने 528 करोड़ रूपए के निवेश से अत्याधुनिक टेक्सटाइल और परिधान निर्माण इकाई स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। इस परियोजना से लगभग 2,500 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है।

फार्मास्यूटिकल क्षेत्र की काबरा ड्रग्स ने 200 करोड़ रुपये तथा डेयरी क्षेत्र की दिनशॉज़ डेयरी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड ने 40 करोड़ रुपये निवेश का प्रस्ताव दिया है। इन दोनों परियोजनाओं से क्रमशः लगभग 250 और 150 रोजगार सृजित होंगे। हैदराबाद दौरे के दौरान मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और राज्य के प्रतिनिधिमंडल ने देश की कई अग्रणी कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकें कीं। इनमें पेज इंडस्ट्रीज और डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स, एक्सिस एनर्जी, सेल्कॉन ग्रुप, मैग्नमविंग्स जैसी प्रमुख कंपनियां शामिल रहीं। बैठकों में छत्तीसगढ़ में निवेश की संभावनाओं, उपलब्ध औद्योगिक सुविधाओं और राज्य सरकार की उद्योग-अनुकूल नीतियों पर विस्तार से चर्चा हुई। इसके अलावा स्वामी नारायण गुरुकुल संगठन के प्रतिनिधियों ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रायपुर के टाटीबंध में 650 बिस्तरों वाले चौरिटेबल अस्पताल की स्थापना के प्रस्ताव पर चर्चा की।

इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम में आईटी, डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, एयरोस्पेस एवं रक्षा, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) और उन्नत विनिर्माण जैसे भविष्य के उद्योगों में निवेश के अवसरों को प्रमुखता से प्रस्तुत किया गया। निवेशकों ने इन क्षेत्रों में विशेष रुचि दिखाई।

कार्यक्रम में सीएसआईडीसी के अध्यक्ष श्री राजीव अग्रवाल, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह, उद्योग विभाग के सचिव श्री रजत कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव श्री राहुल भगत, इन्वेस्टमेंट कमिश्नर सुश्री रितु सैन, सीएसआईडीसी के प्रबंध संचालक श्री विश्वेश कुमार, उद्योग विभाग के संचालक श्री प्रभात मलिक एवं अन्य अधिकारी भी शामिल रहे।

नल जल योजना से पानी नहीं मिलने की शिकायतों पर दो ईई से मांगा स्पष्टीकरण

■ **अरुण साव के बस्तर प्रवास के दौरान ग्रामीणों ने की थी शिकायत**

रायपुर। जल जीवन मिशन के तहत संचालित नल जल योजनाओं से पानी नहीं मिलने की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए उप मुख्यमंत्री तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री अरुण साव के निर्देश पर विभाग ने कोंडागांव और दंतेवाड़ा के कार्यपालन अभियंताओं से स्पष्टीकरण मांगा है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव के हाल ही में बस्तर प्रवास के दौरान कोंडागांव जिले के ग्राम बेड़मा तथा दंतेवाड़ा जिले के टेकनार में जल अर्पण कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री से ग्रामीणों ने पानी नहीं आने की शिकायत की थी। इस पर श्री साव ने अधिकारियों पर नाराजगी जताते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए थे। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के प्रमुख अभियंता श्री के.के. मरकाम ने कोडांगांव के कार्यपालन अभियंता वीरेन्द्र पाण्डेय से स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए जारी नोटिस में कहा है कि विगत 5 जून को ग्राम बेड़मा, विकासखण्ड केशकाल, जिला कोण्डागांव में उप मुख्यमंत्री तथा विभागीय मंत्री अरुण साव के प्रवास के दौरान जल जीवन मिशन के अंतर्गत जल अर्पण समारोह का आयोजन किया गया था।

समारोह के दौरान उप मुख्यमंत्री द्वारा गांववालों से नवनिर्मित योजना के संचालन-संधारण के संबंध में चर्चा के दौरान ग्रामवासियों ने शिकायत की थी कि योजना के सुचारू रूप से कार्यरत नहीं होने के कारण नियमित जलापूर्ति नहीं हो रही है एवं योजना का समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा है। विभाग ने ग्रीष्म ऋतु के दौरान नवनिर्मित योजना से जलापूर्ति नहीं होने की शिकायत को गंभीर मानते हुए कार्यपालन अभियंता को शासकीय कार्यों के प्रति घोर लापरवाही बरतने व गुणवत्तापरक कार्य संपादन नहीं होना माना है।

कार्यपालन अभियंता की कार्यप्रणाली से तत्समय अप्रिय एवं असहज़ स्थिति निर्मित हुई, जिससे विभाग की छवि पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। प्रमुख अभियंता ने दंतेवाड़ा के कार्यपालन अभियंता श्री एस.पी. मण्डावी को भी स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए जारी नोटिस में कहा है कि विगत 7 जून को दंतेवाड़ा जिले के ग्राम टेकनार में उप मुख्यमंत्री के प्रवास के दौरान आयोजित जल अर्पण समारोह में उप मुख्यमंत्री ने नवनिर्मित नल जल योजना के संचालन-संधारण के संबंध में ग्रामीणों से चर्चा की थी। इस दौरान ग्रामीणों ने शिकायत की थी कि योजना के सुचारू रूप कार्यरत नहीं होने के कारण गांव के एक मोहल्ले के कुछ घरों में जलापूर्ति नहीं हो रही है जिससे मोहल्लेवासियों को योजना का समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा है। प्रमुख अभियंता ने नोटिस में कहा है कि ग्रीष्म ऋतु के दौरान नवनिर्मित योजना से समग्र रूप से तकनीकी रूपांकन अनुसार जलापूर्ति नहीं होना कार्यों के तकनीकी मापदण्ड अनुसार क्रियान्वयन नहीं किया जाना दर्शाता है।

उप मुख्यमंत्री साव के निर्देश पर ठेकेदार को नोटिस जारी

निरीक्षण के दौरान काम की धीमी प्रगति पर जताई थी नाराजगी

■ **श्री साव ने 6 जून को किरंदुल-विशाखापट्टनम रेलवे लाइन पर बन रहे ओवरब्रिज की देखी थी प्रगति**

रायपुर। उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री श्री अरुण साव के निर्देश पर विभाग ने रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण की धीमी प्रगति पर ठेकेदार को नोटिस जारी किया है। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने अपने बस्तर प्रवास के दौरान 6 जून को राष्ट्रीय राजमार्ग-30 पर केशलूर-जगदलपुर मार्ग में किरंदुल-विशाखापट्टनम रेलवे लाइन के ऊपर बन रहे फोरलेन रेलवे ओवरब्रिज का निरीक्षण किया था। उन्होंने निरीक्षण के दौरान काम के पिछड़ने एवं लेट-लतीफी पर ठेकेदार और अधिकारियों को फटकार लगाई थी। उन्होंने अनुबंध के अनुसार कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर गहरी नाराजगी जताते हुए ठेकेदार को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए थे। बस्तर जिले में केशलूर के पास 69 करोड़ 36 लाख रुपए की लागत से इस रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण किया जा रहा है।

लोक निर्माण विभाग के राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता ने निर्माण एजेंसी मेसर्स अशोक कुमार मित्तल को जारी नोटिस में कहा है कि साइट उपलब्ध होने के बावजूद मैन-पॉवर, मटेरियल और मशीनरी की खराब व्यवस्था के कारण अलग-अलग चरणों में निर्माण के समयबद्ध लक्ष्यों को हासिल नहीं किया जा सका है। कार्यस्थल पर काम की प्रगति मंजूर किए गए निर्माण कार्यक्रम से काफी पीछे है और तय किए गए माइलस्टोन्स (महत्वपूर्ण पड़ावों) के अनुरूप नहीं है। विभाग द्वारा प्रगति की लगातार समीक्षा कर कार्यों में तेजी लाने के लिए बार-बार निर्देशित और नोटिस जारी करने के बावजूद काम की गति असंतोषजनक है।

विभाग ने ठेकेदार को जारी नोटिस में कहा है कि उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री द्वारा विगत 6 जून को साइट के निरीक्षण के दौरान काम की बेहद धीमी प्रगति पर गंभीर चिंता जताई गई थी। उन्होंने अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार ठेकेदार के विरूद्ध तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए थे। उप मुख्यमंत्री के निर्देश पर मुख्य अभियंता ने ठेकेदार को नोटिस जारी कर तुरंत पर्याप्त मैन-पॉवर, मशीनरी, सामग्री और अन्य जरूरी संसाधन जुटाकर काम में तेजी लाने तथा प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने के लिए तय लक्ष्यों को हासिल करने सभी जरूरी उपाय करने के निर्देश दिए हैं। काम की प्रगति में उल्लेखनीय सुधार नहीं पाए जाने पर विभाग द्वारा अनुबंध के प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे गिरिराज सिंह

रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12साल पूरे होने पर उनकी उलब्धियां गिनाने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह दो वसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने ऑपरेशन लोटस पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कोई ऑपरेशन नहीं चलता। जो जैसी करनी करता है उसका फल वैसा ही भोगता है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह रायपुर में आयोजित विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में शामिल होंगे। हैंडलूम, हस्तशिल्प, सिल्क और टेक्सटाइल अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसके अलावा सड्डु, बैरन बाजार और शांति नगर में जनसंपर्क कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह 13 जून को सफाई अभियान और पौधरोपण कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही सदर बाजार-बुढ़ातालाब क्षेत्र में जनसंपर्क करेंगे।केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि 2 दिवसीय के प्रवास पर छत्तीसगढ़ आया हूं। पीएम के 12 साल नेतृत्व में सभी क्षेत्रों में काम किया गया है। छत्तीसगढ़ की जनता के सामने यही सब पेश करना है। डबल इंजन की सरकार ने नक्सलवाद खत्म किया इसलिए देश के प्रधानमंत्री का भी धन्यवाद करता हूं।

ओवररेटिंग मामले मे चार आबकारी उप निरीक्षक निलंबित

रायपुर। आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़ ने राज्य के विभिन्न जिलों में शराब दुकानों में निर्धारित दर से अधिक कीमत पर बिक्री और नियंत्रण में लापरवाही के मामलों में सख्त कार्रवाई करते हुए चार आबकारी उप निरीक्षकों को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई राज्य स्तरीय उड़नदस्ता की जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई। निलंबित अधिकारियों में धमतरी जिले के कुरूद के वृत्त प्रभारी पुरूषोत्तम सिन्हा, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले के गंडई वृत्त प्रभारी प्रभाकर सिरमौर, बलौदाबाजार जिले के सिमगा वृत्त प्रभारी मनराखन नेताम (आबकारी उप निरीक्षक) तथा रायपुर जिले के पंडरी वृत्त प्रभारी कौशल किशोर सोनी (आबकारी उप निरीक्षक) शामिल हैं। जांच में गंडई, हिरमी, कुरूद और फाफाडीह शराब दुकानों में छद्म ग्राहकों के माध्यम से की गई खरीद में निर्धारित दर से 10 से 60 रुपये तक अधिक वसूली की पुष्टि हुई।

कार्यालय खण्ड चिकित्सा अधिकारी
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मैनपुर जिला: गरियाबंद (छ.ग.)
(sthapnashakhamainpur@gmail.com)

क्रमांक/लेखा/2026/1119 दिनांक :- 10.06.2026

" निविदा सूचना "

कार्यालय खण्ड चिकित्सा अधिकारी विकासखण्ड मैनपुर जिला-गरियाबंद (छ.ग.) पता देवभोग रोड मैनपुर की ओर से विकासखण्ड मैनपुर में संचालित शासकीय अस्पताल 02 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (मैनपुर/अमलीपदर) एवं 03 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (शोभा, झरगांव, उरमाल) में आंतरिक एवं बाह्य परिसर में साफ़-सफाई / स्वच्छता (HOUSE KEEPING) कार्य (सफाई सामग्री सहित) हेतु मोहरबंद निविदाए आमंत्रित की जाती है । निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु विकासखण्ड मैनपुर के खण्ड चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में राशि रु 500 /- (अक्षरी राशि रु पाच सौ मात्र) का बैंक ड्राफ्ट/चेक (BLOCK MEDICAL OFFICER BLOCK MAINPUR A/C NO. 2689000100031299 के नाम से देय, जो की नॉन रिफंडेबल है) दिनांक 10.06.2026 से 30.06.2026 को अपरान्ह 12 बजे तक जमा कर निविदा प्रपत्र प्राप्त किया जा सकता है।

क्र	विवरण	तिथि	समय
01	निविदा विक्रय की प्रारंभ तिथि एवं समय	10.06.2026	अपरान्ह 03 बजे से
02	निविदा जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	30.06.2026	अपरान्ह 12 बजे तक
03	निविदा खोलने की अंतिम तिथि एवं समय	30.06.2026	अपरान्ह 03 बजे से

संलग्न - (1) परिशिष्ट * अ* :- निविदा हेतु आवेदन।
(2) परिशिष्ट * ब * :- घोषणा - पत्र।
(3) परिशिष्ट * स * :- वित्तीय दर ।

खण्ड चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मैनपुर, जिला-गरियाबंद (छ.ग.)

जी-262701368/3

कार्यालय अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग, दुर्ग मण्डल दुर्ग (छत्तीसगढ़)

दुर्ग, दिनांक 03.06.2026

(ई-प्रोक्योरमेंट निविदा सूचना)
(प्रथम आमंत्रण)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल की ओर से ऑनलाईन निविदायें प्रपत्र "अ" में प्रतिशत दर पर दिनांक 23.06.2026 तक आमंत्रित की जाती है:-

निविदा आमंत्रण सू. क्र./ सि. क्र	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (राशि लाख में)
1	2	3
115/192641	जिला कबीरधाम के वि.ख. कवर्धा के ग्राम सोनपुरी से भुडकुड़ा मार्ग कि.मी.3/2 पर माध्यम पुल का निर्माण कार्य	94.35
116/192642	साजा उपसंभाग के अंतर्गत आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों में विशेष मरम्मत का कार्य (जोनल एजेन्सी)	40.00
117/192643	नवागढ़ उपसंभाग के अंतर्गत आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों में विशेष मरम्मत का कार्य (जोनल एजेन्सी)	40.00
118/192644	बेमेतरा उपसंभाग के अंतर्गत आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों में साधारण मरम्मत, वाटर प्रुफिंग का कार्य (जोनल एजेन्सी)	20.00
119/192645	बेमेतरा उपसंभाग के अंतर्गत आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों में एम.ओ.डब्ल्यू. का कार्य (जोनल एजेन्सी)	40.00
120/192646	बेमेतरा उपसंभाग के अंतर्गत आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों में विशेष मरम्मत का कार्य (जोनल एजेन्सी)	70.00
121/192647	बेमेतरा विश्रामगृह साजा बेरला थानखम्हरिया नवागढ़ नांदघाट बेमेतरा सर्किट हाउस बेमेतरा में गार्डन का साधारण मरम्मत कार्य	30.00
122/192648	खैरागढ़ उपसंभाग के अंतर्गत आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों में एम.ओ.डब्ल्यू. का कार्य (जोनल एजेन्सी)	12.50
123/192649	खैरागढ़ उपसंभाग के अंतर्गत आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों में रंगाई-पोताई एवं पेंटिंग का कार्य (जोनल एजेन्सी)	42.50
124/192650	छुईखदान उपसंभाग के अंतर्गत विभिन्न मार्गों में विशेष मरम्मत कार्य (जोनल एजेन्सी)	25.00
125/192651	राजनांदगांव के मुढीपार से झुराडबरी मार्ग लं. 1.10 कि.मी निर्माण कार्य	100.24
126/192652	उपसंभाग क्र. 01 दुर्ग के अंतर्गत आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों में साधारण मरम्मत कार्य (जोनल एजेन्सी)	35.00

टीप- 1. उपरोक्त निर्माण कार्यों की निविदा की सामान्य शर्तें, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति, निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी ई-प्रोक्योरमेंट वेब portal एवं विभागीय वेबसाइट http://eproc.cgstate.gov.in से डाऊनलोड की जा सकती है।
2. पंजीकृत डाक द्वारा कार्यालय में भेजे जाने वाले लिफाफे के ऊपर एन.आई.टी. क्रमांक एवं कार्य का नाम अनिवार्य रूप से अंकित किया जायें ।

अधीक्षण अभियंता
लोक निर्माण विभाग दुर्ग, मण्डल दुर्ग

जी-262701334/8

छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने मोहर्रम-उर्स में डीजे बैंड-बाजा और आतिशबाजी पर लगाई रोक

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने मोहर्रम, उर्स और अन्य आयोजन को लेकर महत्वपूर्ण अपील जारी करते हुए प्रदेश की सभी ताजिया कमेटियों, दरगाह कमेटियों, उर्स कमेटियों, मुतवल्लियान और इंतेजामिया कमेटियों से कहा है कि सभी धार्मिक कार्यक्रम केवल कुरआन, हदीस और शरीअत के मुताबिक ही आयोजित किए जाएं। मोहर्रम, उर्स और अन्य मजहबी आयोजनों में डीजे, धुमाल, बैंड-बाजा, नाच-गाना, आतिशबाजी तथा अन्य गैर-शरई गतिविधियों की किसी भी स्थिति में अनुमति नहीं होगी। वक्फ बोर्ड ने कहा है कि धार्मिक आयोजनों की गरिमा और पवित्रता बनाए रखना सभी संबंधित समितियों की जिम्मेदारी है।

बोर्ड ने चेतावनी दी है कि किसी जुलूस, उर्स या मजहबी तकरीब में प्रतिबंधित गतिविधियां पाए जाने पर संबंधित समिति और उसके जिम्मेदार पदाधिकारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आवश्यकता पडने पर संबंधित समिति की मान्यता समाप्त करने की भी कार्रवाई की जा सकती है। वक्फ बोर्ड ने यह भी कहा है कि नियमों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित समिति और इंतेजामिया पर 50 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। बोर्ड ने सभी आयोजकों से अपील की है कि वे कार्यक्रमों को पूरे अदब, एहतराम और अनुशासन के साथ संपन्न कराएं तथा किसी भी विवाद या अनुचित गतिविधि से बचें।

वक्फ बोर्ड ने प्रदेश के मुस्लिम समाज से हजरत इमाम हुसैन और शहीद-ए-कर्बला की कुर्बानियों की याद में मोहर्रम को सादगी, इबादत, सब्र और अखलाक के साथ मनाने की अपील की है। साथ ही सभी मस्जिदों के इमाम साहबान, मुतवल्लियान और इंतेजामिया कमेटियों को निर्देश दिया गया है कि इस ऐलान को जुमे की नमाज से पहले पढ़कर सुनाया जाए और मस्जिदों के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा किया जाए।

इंडिया गठबंधन की बैठक के राजनीतिक मायने क्या हैं?

कमलेश पांडे

विगत दो-तीन वर्षों में कांग्रेस की सियासी विसात पर अपना अपना-सबकुछ लुटा-पिटा देने के बाद इंडिया गठबंधन के सहयोगियों की जो नई दिल्ली बैठक हुई, उसके राजनीतिक मायने कांग्रेस के लिए बेहद फायदेमंद साबित हुए। क्योंकि इस बैठक में पहली बार नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की आवाज ध्यान से सुनी गई और उनके नेतृत्व को तथा उनकी पार्टी को गाहे-बगाहे चुनौती देने वाले क्षेत्रीय दलों के सुरमा भोपाली नेता दबी जुबान में अपनी भावना प्रकट करने को अभिशप्त हुए। खासकर नेशनल कांफ्रेंस के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, सपा प्रमुख अखिलेश यादव को छोड़कर।

इसलिए यह बैठक केवल एक नियमित विपक्षी बैठक तक सीमित नहीं रही, क्योंकि यह बैठक ऐसे समय हुई, जब कई सहयोगी दलों और कांग्रेस के बीच मतभेदों की बढ़ती-घटती खबरें सामने आई थीं, इसलिए इसके संदेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार, 8 जून को इंडिया गठबंधन की बैठक में लगभग 23 दलों के राजनेता शामिल हुए। बैठक में विपक्षी दलों ने अपनी एकजुटता दिखाने और आगे की राजनीतिक रणनीति पर चर्चा की। प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, बैठक में लगभग 23 विपक्षी दलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। जिनमें मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, सुप्रिया सुले के अलावा प्रमुख वामपंथी दलों के अनेक नेता उपस्थित रहे। वहीं, इस बैठक की कतिपय चुनौतियां भी सामने आईं, क्योंकि जहां तमिलनाडु में सत्ता से बेदखल हुई डीएमके ने कांग्रेस से नाराजगी होने के चलते इस बैठक से दूरी बनाई, जिससे गठबंधन के भीतर मतभेदों की चर्चा तेज रही। वहीं, आप के सुप्रीमो अरबिंद केजरीवाल की अनुपस्थिति भी चर्चा में रही। जबकि कुछ अन्य सहयोगी दलों की भूमिका और भागीदारी को लेकर भी सवाल बने रहे। जहां तक इंडिया गठबंधन की इस बहुप्रतीक्षित बैठक के राजनीतिक मायने की बात है तो यह बैठक लोकसभा चुनाव 2024 के बाद विपक्ष की सबसे महत्वपूर्ण गैर-संसदीय बैठकों में से एक मानी जा रही है। जिसके माध्यम से विपक्ष ने संदेश देने की कोशिश की कि मतभेदों के बावजूद भाजपा के खिलाफ साझा मंच अभी कायम है। वहीं, भाजपा ने डीएमके की अनुपस्थिति और अन्य अंतर्विरोधों को लेकर गठबंधन की एकता पर सवाल उठाए हैं। इस बैठक के सबसे बड़े राजनीतिक निष्कर्ष निम्नलिखित हैं- पहला, इंडिया गठबंधन अभी समाप्त नहीं हुआ है: सबसे बड़ा संदेश यही रहा कि तमाम मतभेदों, चुनावी झटकों और सहयोगी दलों की नाराज़गी के बावजूद विपक्षी दलों ने एक साझा मंच बनाए रखने का निर्णय लिया। 23 दलों की भागीदारी ने कांग्रेस को यह कहने का अवसर दिया कि गठबंधन अभी भी प्रासंगिक है। दूसरा, 2029 की तैयारी अभी से शुरू हो गई: बैठक का प्रमुख उद्देश्य केवल वर्तमान राजनीतिक मुद्दों पर प्रतिक्रिया देना नहीं था, बल्कि 2029 लोकसभा चुनाव के लिए दीर्घकालिक रणनीति तैयार करना भी था। विपक्ष भाजपा के विरुद्ध एक व्यापक राष्ट्रीय नैरेटिव गढ़ने की कोशिश में दिखा। तीसरा, कांग्रेस फिर से समन्वयक की भूमिका में: बैठक से यह संकेत मिला कि कांग्रेस गठबंधन की धुरी बनी रहना चाहती है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने विपक्षी एकता पर जोर दिया और केंद्र सरकार के विरुद्ध साझा संघर्ष का आह्वान किया। चौथा, गठबंधन की कमजोरी भी उजागर हुई: एमके स्टालिन की डीएमके और अरविंद केजरीवाल की आप का बैठक से दूर रहना बताता है कि विपक्षी एकता अभी भी कई अंतर्विरोधों से घिरी हुई है।

मोदी युग के 12 वर्ष: विकास और विश्वास का उदय

ललित गर्ग

भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में कुछ कालखंड केवल शासन परिवर्तन के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्रीय चेतना के पुनर्जागरण के लिए याद किए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते बारह वर्षों का दौर ऐसा ही एक कालखंड है। यह केवल एक प्रधानमंत्री के लंबे कार्यकाल की कहानी नहीं है, बल्कि उस भारत की कहानी है जिसने स्वयं को नए आत्मविश्वास, नई ऊर्जा और नई वैश्विक पहचान के साथ स्वयं को स्थापित किया है। नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। यह उपलब्धि केवल राजनीतिक सफलता नहीं है, बल्कि जनता के उस विश्वास का प्रमाण है जो बार-बार लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्त हुआ है। भारत जैसा विशाल, बहुभाषी, बहुधार्मिक और सांस्कृतिक विविधताओं से भरा देश किसी नेतृत्व को लगातार तीन बार राष्ट्रीय जनादेश दे, यह अपने आप में असाधारण एवं ऐतिहासिक घटना है।

मोदी युग की सबसे बड़ी विशेषता केवल विकास नहीं, बल्कि विकास और विश्वास का समन्वय है। नेहरू युग को आधुनिक भारत के निर्माण का काल कहा गया, तो मोदी युग को उस भारत के आत्मविश्वास के पुनर्जागरण का काल कहा जा सकता है। मोदी ने केवल सड़कों, पुलों, हवाई अड्डों और डिजिटल नेटवर्क का निर्माण नहीं किया, बल्कि करोड़ों भारतीयों के मन में यह विश्वास भी जगाया कि भारत किसी से कम नहीं है और वह विश्व मंच पर नेतृत्वकारी भूमिका निभा सकता है। मोदी की सबसे विलक्षण विशेषता यह रही कि उन्होंने राजनीति को केवल सत्ता संचालन का माध्यम नहीं माना, बल्कि उसे जनभावनाओं और राष्ट्रीय आकांक्षाओं से जोड़ा। वे उन विरले नेताओं में हैं जिन्होंने सरकारी योजनाओं को केवल प्रशासनिक दस्तावेज नहीं रहने दिया, बल्कि उन्हें जनआंदोलन का स्वरूप दिया। स्वच्छ भारत अभियान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सफाई का विषय जो कभी सरकारी विभागों तक सीमित था, उसे राष्ट्रीय चरित्र और सामाजिक जिम्मेदारी से जोड़ दिया गया।

मोदी युग को भारत की गुम होती सांस्कृतिक अस्मिता की पुनर्स्थापना के लिए भी याद किया

जाएगा। सदियों से उपेक्षित राष्ट्रीय प्रतीकों, तीर्थस्थलों और सांस्कृतिक विरासत को नई गरिमा मिली। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण केवल एक धार्मिक घटना नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों की सांस्कृतिक चेतना के सम्मान का प्रतीक बना। काशी विश्वनाथ धाम, महाकाल लोक, केदारनाथ पुनर्निर्माण और सोमनाथ जैसे तीर्थों का विकास यह संकेत देता है कि आधुनिकता और परंपरा एक-दूसरे की विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हो सकती हैं। मोदी की एक और विशेषता यह है कि उन्होंने भारत की विदेश नीति को आत्मविश्वास का नया आयाम दिया। कभी विश्व शक्तियों के बीच संतुलन साधने वाला भारत आज वैश्विक विमर्श को प्रभावित करने वाला राष्ट्र बनकर उभरा है। रूस-यूक्रेन युद्ध हो, पश्चिम एशिया का संकट हो, जी-20 का नेतृत्व हो अथवा वैश्विक दक्षिण (ग्लोबल साउथ) की आवाज उठाने का प्रश्न- भारत ने निर्णायक भूमिका निभाई है। यह वही भारत है जिसे कभी विकासशील देशों की कतार में खड़ा माना जाता था, लेकिन आज दुनिया उसकी ओर समाधान प्रदाता राष्ट्र के रूप में देख रही है।

इन बारह वर्षों की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यह भी है कि शासन के केंद्र में पहली बार अंतिम व्यक्ति को रखने का गंभीर प्रयास दिखाई दिया। जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, पीएम आवास योजना, मुफ्त राशन योजना तथा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण जैसी योजनाओं ने करोड़ों गरीबों के जीवन में बदलाव लाने का काम किया। शासन की पारदर्शिता बढ़ी और बिचौलियों की भूमिका सीमित हुई। डिजिटल इंडिया अभियान ने तकनीक को केवल महानगरों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि गांव-गांव तक पहुंचाया। नरेंद्र मोदी की नेतृत्व शैली का एक विशिष्ट पक्ष उनका संकल्पबोध है। वे बड़े लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उन्हें राष्ट्रीय अभियान का स्वरूप देते हैं। चाहे 370 का उन्मूलन हो, तीन तलाक पर रोक हो, जीएसटी लागू करना हो, महिला आरक्षण विधेयक हो अथवा नक्सलवाद और आतंकवाद के विरुद्ध कठोर नीति-इन सभी निर्णयों में राजनीतिक जोखिम था, लेकिन उन्होंने जोखिम उठाने का साहस दिखाया। यही साहस उन्हें सामान्य राजनेताओं से अलग करता है।

हालांकि, किसी भी लोकतांत्रिक शासन की तरह चुनौतियां भी कम नहीं हैं। बेरोजगारी, महंगाई, कृषि संकट, शिक्षा और स्वास्थ्य की बढ़ती लागत, सामाजिक विषमताएं तथा आर्थिक अवसरों का असमान वितरण ऐसे प्रश्न हैं जिनका समाधान अभी अपेक्षित है। भारत यदि 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है तो केवल आर्थिक वृद्धि पर्याप्त नहीं होगी, बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुलभ चिकित्सा, रोजगार सृजन और भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन को भी समान प्राथमिकता देनी होगी। मोदी सरकार के आगामी वर्षों से सबसे बड़ी अपेक्षा यही है कि वह भ्रष्टाचार के विरुद्ध अपने अभियान को और अधिक प्रभावी बनाए। भारत को ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता है जहां ईमानदारी अपवाद नहीं, सामान्य व्यवहार बने। शिक्षा और स्वास्थ्य को व्यावसायिक माफियाओं के प्रभाव से मुक्त कर आम नागरिक की पहुंच में लाना भी समय की मांग है। साथ ही उद्यमिता को बड़े औद्योगिक घरानों तक सीमित रखने के बजाय गांवों, युवाओं और महिलाओं तक पहुंचाना होगा ताकि प्रत्येक नागरिक रोजगार खोजने वाला नहीं, बल्कि रोजगार देने वाला बन सके।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुझे अनेक अवसरों पर मिलने और उन्हें निकट से देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वर्ष 2007 में, जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब गुजरात के आदिवासी अंचल कवांट में पूज्य आदिवासी जैन संत गणि राजेंद्र विजयजी के सान्निध्य में आयोजित एक विराट आदिवासी सम्मेलन में उनसे विस्तृत संवाद का अवसर मिला। उस सम्मेलन में वे केवल औपचारिक अतिथि के रूप में नहीं आए थे, बल्कि अपने संपूर्ण मंत्रिमंडल के साथ उपस्थित होकर आदिवासी समाज के विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का परिचय दिया था। उसी अवसर पर उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों के शैक्षिक उत्थान हेतु एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय को हमारे सुखी परिवार फाउंडेशन को संचालित करने के लिए प्रदान किया तथा आदिवासी विकास की दिशा में ऐतिहासिक 15,000 करोड़ रुपये की वनबंधु कल्याण योजना की घोषणा की। यह उनकी दूरदृष्टि और समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने की सोच का प्रमाण था। इसी सम्मेलन के दौरान एक अत्यंत रोचक और ऐतिहासिक प्रसंग भी सामने आया। गणि राजेंद्र विजयजी ने नरेंद्र मोदी से कहा-अब आपको दिल्ली जाना चाहिए और देश की बागडोर संभालनी चाहिए। उस समय मोदीजी ने सहज मुस्कान के साथ उत्तर दिया-मुझे दिल्ली कौन ले जाएगा? किंतु संतों की वाणी में एक विशेष शक्ति होती है। जो बात उस समय एक साधारण संवाद प्रतीत हुई, वही कुछ वर्षों बाद भविष्यवाणी के रूप में सत्य सिद्ध हुई।

उन दिनों गुजरात सचिवालय में भी अनेक बार जाने और मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का अवसर मिला। वहां जो सबसे अधिक प्रभावित करने वाली बात थी, वह उनकी कार्यसंस्कृति का प्रभाव था। सचिवालय में बड़े से बड़े आईएएस अधिकारी भी आत्मानुशासन, समयपालन और स्वावलंबन का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करते थे। अपने छोटे-छोटे कार्य स्वयं करना, अनावश्यक तामझाम से दूर रहना, समय का सदुपयोग करना और जिम्मेदारी को सर्वोपरि मानना वहां की प्रशासनिक संस्कृति का हिस्सा बन चुका था। स्पष्ट महसूस होता था कि यह कार्यशैली शीर्ष नेतृत्व की प्रेरणा से विकसित हुई है। नरेंद्र मोदी केवल आदेश देने वाले प्रशासक नहीं हैं, बल्कि अपने आचरण से व्यवस्था को दिशा देने वाले नेतृत्वकर्ता हैं। यदि इस ऊर्जा को कौशल, नवाचार और उद्यमिता से जोड़ा गया तो भारत केवल विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो सकता है। मोदी युग की सबसे बड़ी उपलब्धि शायद आंकड़ों, परियोजनाओं या चुनावी जीतों में नहीं, बल्कि उस मनोवैज्ञानिक परिवर्तन में है जो भारत के जनमानस में दिखाई देता है। नरेंद्र मोदी ने बारह वर्षों में विकास की संरचनाएं खड़ी की हैं, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि उन्होंने करोड़ों भारतीयों के भीतर भविष्य के भारत की एक आकांक्षा जगाई है। 2047 के विकसित भारत का उनका संकल्प तभी साकार होगा जब विकास के साथ विश्वास, समृद्धि के साथ समान अवसर और शक्ति के साथ संवेदनशीलता भी जुड़ेगी। यदि यह संतुलन बना रहता है, तो इतिहास मोदी युग को केवल एक लंबे राजनीतिक कार्यकाल के रूप में नहीं, बल्कि भारत के आत्मविश्वास, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और वैश्विक उदय के युग के रूप में याद करेगा।

पुराण दिग्दर्शन ....

सन्देहाभासनिकारणाध्यायः (नौवां अध्याय)

(गतांक से आगे...)

हम एक प्रत्यक्ष घटना द्वारा भी आपको शङ्कापङ्क से निकालने का प्रयत्न करेंगे, जरा आंख उघाड़ कर पढ़िये - सात महीने की लड़की के शिर से बच्चा पैदा हुआ।

जलालपुर - जट्टां (पंजाब) का समाचार है कि एक सात महीने की लड़की के सिर में रसौली की तरह कई पौण्ड वजन का फालतू मांस बढ़ा हुवा था, लड़की के संरक्षकों ने कई डाक्टरों से उसे कटा देने का प्रयत्न किया परन्तु किसी भी डाक्टर को औपरेशन करने की हिम्मत न हुई, आखीर डाक्टर बोधराज साहिब ने उसका औपरेशन किया तो उस कटे हुवे माँस पिण्ड में से एक बच्चा निकला जिसके सब अङ्ग मुकम्मल बन चुके थे, हड्डिये भी बराबर थीं- जिस लड़की का औपरेशन किया गया वह अभी जीवित है, लोग दूर दूर से देखने आते हैं।

ता0 22-5-33 अखबार तालीम (लाहौर) से

शिल्प निंदा का आक्षेप

महाशय कर्मानन्द सरस्वती समाजी ने पुराणों पर कुछ आक्षेप किये थे हम उन पर भी विचार करना आवश्यक समझते हैं। इस सिलसिले में पहिले उनका आक्षेप और फिर अपना सभाधान रक्खा गया है, पाटक मनन करें-शिवपुराण वायुसंहिता अध्याय 31 श्लोक 36 में लिखा है-

शिल्पिनः कारवो वैद्या हेमकारा नृपध्वजाः।
भूतकाः कूटसंयुक्ताः सर्वे ते नारकाः स्मृताः।।

अर्थात् - कारीगर, शिल्पी, वैद्य, सुनार, राजा की ध्वजा उठाने वाले नौकर और मक्कार ये सब नरकगामी हैं अर्थात् दोजखी हैं। जब से इन सब पुराणों ने इस प्रकार की शिक्षा देनी आरम्भ की, तभी से भारतवर्ष का सुख नष्ट होगया और अन्यों से पदाक्रान्त होकर यह आज अनेक प्रकार के असह्य कष्ट भोग रहा है। क्या आप इसको वेदानुकूल सिद्ध कर सकते हैं?

क्रमशः ...

विश्वास टूटने पर प्रेम भी टिक नहीं पाता

आशुतोष गर्ग

राजा ब्रह्मदत्त के महल में पूजनीया नाम की एक अद्भुत चिड़िया रहती थी। उसके शरीर का अधिकांश भाग काला था, किंतु सिर लाल रंग का था। इसलिए वह दूर से ही अलग दिखाई देती थी। धीरे-धीरे उसका राजा ब्रह्मदत्त से गहरा स्नेह हो गया और वह राजमहल की सदस्य बन गई। उसने महल के भीतर अपना घोंसला भी बना लिया। प्रतिदिन वह महल से उड़कर दूर-दूर तक विचरण करती। कभी समुद्र तट पर घूमती, कभी कमलों से भरे तालाबों में उतरती। जिन सरोवरों में हंस, सारस और कारंडव पक्षियों का मधुर कलरव गूंजता रहता, वहां वह घंटों बिताती। संध्या होते ही वह महल में लौट आती और ब्रह्मदत्त को दिनभर की घटनाएं सुनाया करती। इस तरह ब्रह्मदत्त और पूजनीया मित्र बन गए। कुछ समय बाद राजा ब्रह्मदत्त के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया-सर्वसेन।

उसी समय पूजनीया ने भी एक अंडा दिया। कुछ दिनों बाद उस अंडे में से एक छोटा-सा बच्चा निकला। धीरे-धीरे उसके पंख निकल आए और आंखें भी खुल गईं। पूजनीया अपने बच्चे और राजकुमार सर्वसेन को समान स्नेह से देखती थी। प्रतिदिन वह कहीं से दो मीठे और स्वादिष्ट फल लाती। एक अपने बच्चे को खिलाती और दूसरा राजकुमार सर्वसेन को देती। दोनों उन फलों को बड़े आनंद से खाते और साथ-साथ खेलते थे। राजमहल की धाय कभी-कभी पूजनीया के बच्चे को घोंसले में से निकाल लाती और वह राजकुमार के साथ खेलने लगता था। सर्वसेन उसे अपने हाथों में लेकर खेलता और हंसता रहता। पूजनीया यह सब देखकर बहुत प्रसन्न होती थी, क्योंकि उसे विश्वास था कि उसका बच्चा राजमहल में पूरी तरह सुरक्षित है। एक दिन राजकुमार ने खेलते-खेलते पूजनीया के छोटे बच्चे को अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया। बालक की पकड़ बहुत कठोर थी। धाय ने लाख प्रयत्न किया, परंतु राजकुमार ने मुट्ठी नहीं खोली। बहुत देर तक ज्यादा दबाव पड़ने से नन्हे पक्षी ने प्राण त्याग दिए। जब राजा ब्रह्मदत्त ने यह देखा, तो वे अत्यंत दुखी हो उठे। उन्होंने किसी प्रकार पक्षी के बच्चे को राजकुमार के हाथ से छुड़ाया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। छोटा पक्षी निर्जीव पड़ा था। राजा की आंखों में आंसू थे। उन्होंने धाय को बहुत डांटा और स्वयं भी शोक में डूब गए।

वह मूर्छित होकर गिर पड़ी। कुछ देर बाद जब उसे होश आया, तो वह करुण स्वर में विलाप करने लगी। वह राजा की ओर देखकर बोली, राजन! मैंने आप पर विश्वास किया था। अपने बच्चे को आपके घर में सुरक्षित समझा था, परंतु आज मेरा बच्चा आपके सामने मारा गया। शोक और क्रोध से व्याकुल पूजनीया अचानक उड़कर राजकुमार सर्वसेन के पास गई और उसने अपने तीखे पंजों से राजकुमार की दोनों आंखें फोड़ डालीं। राजकुमार पीड़ा से चीत्कार कर उठा और अंधा हो गया। पूजनीया ने गंभीर स्वर में कहा, राजन! मैं जानती हूं कि पुत्र का दुख क्या होता है! जैसे मुझे अपने बच्चे से प्रेम था, वैसे ही आपको भी अपने पुत्र से है। मैंने आपके पुत्र को अंधा करके भयंकर अपराध किया है। अब मैं आपके घर में रहने व आपके विश्वास के योग्य नहीं रही। यह कहकर चिड़िया उड़ गई।

क्या ममता भी टीएमसी छोड़ कर कांग्रेस में जा रही हैं?

नीरज कुमार दुबे

पश्चिम बंगाल की राजनीति इस समय अपने सबसे उथल पुथल भरे दौर से गुजर रही है। कभी बंगाल की निर्विवाद ताकत मानी जाने वाली ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस अब अंदरूनी बगावत, सांसदों और विधायकों के पलायन तथा राजनीतिक अस्तित्व के संकट से जूझती दिखाई दे रही है। दिल्ली में सोनिया गांधी के साथ ममता बनर्जी और राहुल गांधी के साथ अभिषेक बनर्जी की बैठकों ने इस संकट को और अधिक राजनीतिक रंग दे दिया है। भले ही कांग्रेस और तृणमूल दोनों सार्वजनिक रूप से किसी विलय की संभावना से इंकार कर रहे हों, लेकिन घटनाक्रम यह संकेत दे रहा है कि बंगाल की राजनीति में एक बड़ा पुनर्संयोजन शुरू हो चुका है। एक तरह से यह साफ नजर आ रहा है कि सिर्फ टीएमसी के सांसद, विधायक और पार्षद ही पाला नहीं बदल रहे हैं खुद टीएमसी प्रमुख अपनी पार्टी को खत्म कर कांग्रेस में वापस लौटना चाह रही हैं।

हम आपको बता दें कि दिल्ली में राहुल गांधी और अभिषेक बनर्जी की डेढ़ घंटे लंबी मुलाकात तथा उससे पहले सोनिया गांधी और ममता बनर्जी की बैठक ने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। तृणमूल कांग्रेस ने इन बैठकों को लोकतंत्र और संविधान बचाने की साझा प्रतिबद्धता बताया, लेकिन राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि यह महज औपचारिक बातचीत नहीं थी। बंगाल विधानसभा चुनावों के बाद जिस तरह तृणमूल कांग्रेस कमजोर हुई है और पार्टी के भीतर टूट की स्थिति बनी है, उसके बाद कांग्रेस से नजदीकी बनाना ममता बनर्जी की राजनीतिक मजबूरी बन गई है।

स्थिति यह है कि तृणमूल कांग्रेस के भीतर विद्रोह अब खुली चुनौती का रूप ले चुका है। पार्टी के 80 में से 58 विधायक अलग होकर निष्कासित विधायक रितब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट के साथ चले गए हैं। इस गुट को विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल के रूप में मान्यता भी मिल चुकी है। रितब्रत बनर्जी लगातार दावा कर रहे हैं कि वही असली तृणमूल

कांग्रेस हैं और कांग्रेस के साथ किसी भी प्रकार के विलय या समझौते के खिलाफ हैं। उनका दावा है कि उनके साथ विधायकों की संख्या लगातार बढ़ रही है और कई सांसद भी उनके संपर्क में हैं।

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि कांग्रेस के साथ संभावित विलय या अत्यधिक नजदीकी की अटकलों ने तृणमूल कांग्रेस के भीतर असुरक्षा और बेचैनी को और बढ़ा दिया है। पार्टी के कई विधायक, सांसद और क्षेत्रीय नेता अपनी पूरी राजनीतिक पहचान कांग्रेस विरोध की जमीन पर बनाकर आगे बढ़े थे। ऐसे में उन्हें यह डर सता रहा है कि यदि ममता बनर्जी अंततः कांग्रेस के साथ विलय या व्यापक राजनीतिक समझौते की राह पर चलती हैं, तो उनकी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान समाप्त हो जाएगी। यही कारण है कि तृणमूल में भगदड़ और तेज होने की संभावना जताई जा रही है। पार्टी के भीतर एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो कांग्रेस में लौटने के पक्ष में नहीं है और वह या तो अलग गुट के साथ रहना चाहता है या फिर नए राजनीतिक विकल्प तलाश रहा है। यही बेचैनी अब खुले विद्रोह और लगातार इस्तीफों के रूप में सामने आती दिखाई दे रही है।

संकट केवल विधानसभा तक सीमित नहीं है। संसद में भी तृणमूल कांग्रेस की नींव हिलती दिख रही है। राज्यसभा सांसद प्रकाश चिक बराइक के इस्तीफे ने पार्टी की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। उनसे पहले सुष्मिता देव और सुखेंदु शेखर राय भी पार्टी और राज्यसभा से इस्तीफा दे चुके हैं। सुष्मिता देव की असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा से मुलाकात ने यह अटकलें और तेज कर दी हैं कि तृणमूल कांग्रेस के कई नेता अब भारतीय जनता पार्टी की ओर रुख कर सकते हैं।

लोकसभा में भी तृणमूल के भीतर विद्रोही खेमे की ताकत बढ़ती दिखाई दे रही है। काकोली घोष दस्तिदार के नेतृत्व वाला गुट दावा कर रहा है कि उसे बीस से अधिक सांसदों का समर्थन हासिल है। सयोनी घोष, माला राय, युसुफ पठान, शताब्दी राय, शत्रुघ्न सिन्हा और रचना बनर्जी जैसे कई चर्चित नाम विद्रोही खेमे के साथ बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह गुट राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार को समर्थन देने के लिए लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिख चुका है।

इन घटनाओं के बीच कांग्रेस की भूमिका बेहद दिलचस्प हो गई है। बंगाल कांग्रेस के भीतर भी मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। अधीर रंजन चौधरी और अब्दुल मन्नान जैसे वरिष्ठ नेता ममता बनर्जी के साथ किसी भी तरह की नजदीकी के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। मन्नान ने तो यहां तक कह दिया कि गंदे पानी को साफ पानी में मिलाने से साफ पानी भी गंदा हो जाता है। अधीर रंजन चौधरी ने ममता पर कांग्रेस को बंगाल से खत्म करने का आरोप लगाते हुए कहा कि अब वही ममता गांधी परिवार के सहारे की तलाश में हैं।

दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शुभंकर सरकार ने अपेक्षाकृत नरम रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि जो राहुल गांधी को भविष्य का प्रधानमंत्री और विपक्ष का नेता मानता है, उसका स्वागत है। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार के आरोपों से बचने के लिए कांग्रेस की छतरी का इस्तेमाल करने वालों के लिए दरवाजे खुले नहीं हैं। यह बयान सीधे तौर पर तृणमूल के उन नेताओं की ओर इशारा माना जा रहा है जिन पर विभिन्न घोटालों के आरोप लगे हैं।

हम आपको याद दिला दें कि ममता बनर्जी का पूरा राजनीतिक उदय ही कांग्रेस के खिलाफ विद्रोह की जमीन पर खड़ा हुआ था। वर्ष 1998 में उन्होंने जोरशोर से कांग्रेस से अलग होकर तृणमूल कांग्रेस का गठन किया था। उस समय ममता ने कांग्रेस नेतृत्व पर बंगाल की राजनीति की अनदेखी करने और वामपंथ के सामने आत्मसमर्पण करने का आरोप लगाया था। इसके बाद उन्होंने खुद को कांग्रेस के विकल्प के रूप में स्थापित किया और धीरे धीरे बंगाल में कांग्रेस की जड़ें कमजोर कर दीं। वर्ष 2011 में वाम मोर्चे को सत्ता से हटाने के बाद ममता बनर्जी ने अपने राजनीतिक विस्तार के लिए कांग्रेस से पूरी दूरी बना ली थी और लगातार गांधी परिवार तथा कांग्रेस नेतृत्व पर तीखे हमले करती रहीं। लेकिन अब जब तृणमूल कांग्रेस भीतर से टूट रही है, सांसद और विधायक पार्टी छोड़ रहे हैं और राजनीतिक जमीन खिसकती दिखाई दे रही है, तब वही ममता बनर्जी एक बार फिर कांग्रेस की जड़ों की ओर लौटती नजर आ रही हैं। यही वजह है कि दिल्ली में गांधी परिवार के साथ उनकी बैठकों को केवल शिष्टाचार मुलाकात मानने को राजनीतिक विश्लेषक तैयार नहीं हैं।

दरअसल, बंगाल की राजनीति अब केवल सत्ता की लड़ाई नहीं रह गई है, बल्कि यह अस्तित्व की जंग बन चुकी है। तृणमूल कांग्रेस संगठनात्मक बिखराव से जूझ रही है और बात सिर्फ संसद या विधानसभा में उसके सदस्यों तक सीमित नहीं रह गयी है। बंगाल में कई निगमों से उसके महापौर या पार्षद इस्तीफा दे चुके हैं और पंचायतों में भी इसी तरह के इस्तीफों का दौर जारी है। इस सबके बीच भाजपा यह स्पष्ट कर चुकी है कि तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के लिए उसके दरवाजे बंद हैं वहीं कांग्रेस इस संकट को अपने पुनर्जीवन के अवसर के रूप में देख रही है। राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी एकता की राजनीति को मजबूती देने के लिए कांग्रेस बंगाल में नई संभावनाएं तलाश रही है। बहरहाल, सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ राजनीतिक समझौते की राह पर चलेंगी, या फिर पार्टी के भीतर का विद्रोह उन्हें और कमजोर कर देगा। फिलहाल इतना तय है कि बंगाल की राजनीति में शुरू हुई यह हलचल केवल राज्य तक सीमित नहीं रहने वाली, बल्कि राष्ट्रीय विपक्ष की राजनीति पर भी इसका गहरा असर पड़ने वाला है।

आज का इतिहास

1932 ब्रिटेन और फ्रांस के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर किये गये।
1935 चैंपियनशिप मुक्केबाजी में सबसे बड़े उतार-चढ़ाव में से एक में, जेम्स जे। ब्रैडॉक ने मैक्स बेयर को हराकर दुनिया का सबसे भारी चैंपियन बन गया।
1955 सोवियत भूवैज्ञानिकों ने मीर खदान की खोज की, यूएसएसआर में पहला डियामिनॉन्ड खदान और पूर्वी साइबेरिया में दूसरा सबसे बड़ा खुदाई छेद था।
1956 अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन (आईसीपीओ) को गठन किया गया।
1956 72 वर्षों तक अपने नियंत्रण में रखने के बाद ब्रिटेन ने स्वेज नहर का नियंत्रण मिस्र को सौंपा।
1963 न्यूयॉर्क कमोडिटी एक्सचेंज ने चांदी के वायदा अनुबंधों का कारोबार शुरु किया।
1966 मिरांडा बनाम अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार एरिज़ोना के भूभाग ने मिरांडा चेतावनी की स्थापना की, कानून प्रवर्तन अधिकारियों को अपने अधिकारों के संरक्षण में एक संदिग्ध को चुप रहने और वकील प्राप्त करने की सलाह दी।
1970 द लॉन्ग एंड विंडिंग रोड संयुक्त राज्य अमेरिका में बीटल्स का बीसवां और अंतिम नंबर का एकल बन गया।
1971 न्यूयॉर्क टाइम्स ने पेंटागन पेपर्स, एक 7,000 पन्नों के शीर्ष-गुप्त संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा विभाग के इतिहास को वियतनाम युद्ध में राजनीतिक और सैन्य भागीदारी के लिए प्रकाशित करना शुरू किया।
1981 इंग्लिश किशोरी मार्कस सरजेनट ने क्वीनएलीज़बेथ द्वितीय में छह खाली शॉट लगाए क्योंकि वह मॉल ऑफ द ट्रूपिंग द कोलोरिसन में सवार हुई।
1982 फहद सऊदी अरब के बादशाह बने, अपने सौतेले भाई खालिद को बाद की मौत के बाद उत्तराधिकारी बनाया।
1982 1982 का फीफा विश्व कप स्पेन में शुरू किया गया।
1983 पायनियर 10 (पायनियर पट्टिका चित्र) नेपच्यून की कक्षा से गुजरी, सौर मंडल के ज्ञात ग्रहों से परे यात्रा करने वाली पहली मानव निर्मित वस्तु बन गई।
1991 यू.एस. ओपन में एक दर्शक को बिजली से मरा।
1993 किम कैंपबेल कनाडा की पहली महिला प्रधानमन्त्री बनीं।
2005 पॉप गायक माइकल जैक्सन को 13 साल के बच्चे के यौन उत्पीड़न मामले में बरी कर दिया गया था।
2006 नाइजीरिया और कैमरून ने सीमा विवाद पर समझौता किया।

बदलते राजनीतिक समीकरणों के बीच अस्तित्व की लड़ाई में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस

कांतिलाल मांडोत

दिल्ली में राहुल गांधी और अभिषेक बनर्जी की मुलाकात तथा उससे पहले सोनिया गांधी और ममता बनर्जी के बीच हुई बातचीत ने राष्ट्रीय राजनीति में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। इन बैठकों को लेकर भले ही किसी भी पक्ष ने औपचारिक रूप से किसी गठबंधन या विलय की संभावना की पुष्टि नहीं की हो, लेकिन राजनीति में संकेतों का महत्व हमेशा शब्दों से अधिक माना जाता है। विशेष रूप से तब, जब दोनों दल अपने-अपने राजनीतिक जीवन के कठिन दौर से गुजर रहे हों। ऐसे समय में लगातार हो रही मुलाकातें केवल शिष्टाचार तक सीमित नहीं मानी जा सकतीं। इनके पीछे बदलते राजनीतिक समीकरणों और भविष्य की रणनीतियों की झलक भी दिखाई देती है।

भारतीय राजनीति में कांग्रेस कभी देश की सबसे शक्तिशाली राजनीतिक पार्टी रही है। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत और लंबे समय तक केंद्र तथा राज्यों में सत्ता के कारण कांग्रेस का प्रभाव लगभग पूरे देश में फैला हुआ था। लेकिन पिछले एक दशक में पार्टी का जनाधार लगातार कमजोर हुआ है। कई राज्यों में उसका संगठन लगभग निष्क्रिय हो चुका है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे बड़े राज्यों में कांग्रेस अब मुख्य राजनीतिक शक्ति नहीं रह गई है। राष्ट्रीय स्तर पर भी उसका वोट प्रतिशत और सीटों की संख्या पहले की तुलना में काफी घट चुकी है।

कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती यह रही है कि वह भाजपा के उभार के सामने एक प्रभावी वैकल्पिक राजनीतिक कथा प्रस्तुत नहीं कर सकी। कई राज्यों में क्षेत्रीय दलों ने कांग्रेस के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगाई। कहीं जातीय राजनीति ने जगह बनाई तो कहीं क्षेत्रीय अस्मिता का मुद्दा कांग्रेस पर भारी पड़ा। परिणाम यह हुआ कि राष्ट्रीय पार्टी होने के बावजूद कांग्रेस का प्रभाव सीमित क्षेत्रों तक सिमटता गया। हालांकि राहुल गांधी की यात्राओं और विपक्षी एकता के प्रयासों ने पार्टी को कुछ हद तक राजनीतिक चर्चा के केंद्र में बनाए रखा, लेकिन यह भी सच है कि कांग्रेस अभी तक अपनी पुरानी ताकत हासिल नहीं कर सकी है।

दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में तीन दशक से अधिक समय तक सत्ता में रही वामपंथी सरकार को हटाकर एक नई राजनीतिक शक्ति खड़ी की थी। बाद में उन्होंने भाजपा की चुनौती का भी सफलतापूर्वक मुकाबला किया। एक समय ऐसा लगा कि तृणमूल कांग्रेस केवल बंगाल तक सीमित पार्टी नहीं रहेगी बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। गोवा, त्रिपुरा और पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में

पार्टी ने विस्तार की कोशिशें भी कीं।

लेकिन राजनीति में सफलता स्थायी नहीं होती। यदि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को अपेक्षित समर्थन नहीं मिलता और पार्टी के भीतर असंतोष बढ़ता है, तो यह उसके लिए गंभीर चुनौती बन सकती है। किसी भी क्षेत्रीय दल की ताकत उसके मजबूत संगठन और निर्विवाद नेतृत्व पर आधारित होती है। जब संगठन में टूट-फूट शुरू होती है और नेताओं का विश्वास डगमगाने लगता है, तब राजनीतिक भविष्य को लेकर चिंताएं स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती हैं। ऐसे माहौल में राष्ट्रीय स्तर पर सहयोगी तलाशना एक व्यावहारिक राजनीतिक विकल्प बन जाता है।

यही कारण है कि राहुल गांधी और अभिषेक बनर्जी की मुलाकात को केवल एक सामान्य राजनीतिक बैठक के रूप में नहीं देखा जा रहा। यह मुलाकात ऐसे समय हुई है जब कांग्रेस अपने खोए हुए जनाधार को वापस पाने की कोशिश कर रही है और तृणमूल कांग्रेस अपने राजनीतिक प्रभाव को बनाए रखने की चुनौती से जूझ रही है। दोनों दलों की परिस्थितियां अलग-अलग हैं, लेकिन उनकी चिंता एक जैसी है—राजनीतिक प्रासंगिकता को बनाए रखना।

कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के संबंधों का इतिहास भी उतार-चढ़ाव से भरा रहा है। ममता बनर्जी स्वयं कांग्रेस की ही उपज हैं। उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर तृणमूल कांग्रेस बनाई थी और बाद में बंगाल की राजनीति में कांग्रेस को काफी पीछे छोड़ दिया। लंबे समय तक दोनों दलों के बीच प्रतिस्पर्धा और अविश्वास का माहौल रहा। कई चुनावों में दोनों एक-दूसरे के खिलाफ लड़े। इसलिए आज यदि दोनों दलों के बीच संवाद बढ़ रहा है तो यह केवल वैचारिक निकटता का परिणाम नहीं बल्कि राजनीतिक आवश्यकता का संकेत भी माना जा सकता है।

राजनीति में स्थायी मित्र और स्थायी शत्रु नहीं होते। परिस्थितियां बदलती हैं तो रणनीतियां भी बदलती हैं। यदि कांग्रेस को लगता है कि क्षेत्रीय दलों के साथ बेहतर तालमेल के बिना भाजपा का मुकाबला कठिन है, तो वह पुराने मतभेदों को पीछे छोड़ सकती है। इसी प्रकार यदि तृणमूल कांग्रेस को लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पर अकेले आगे बढ़ना मुश्किल है, तो वह भी पुराने रिश्तों को फिर से मजबूत करने की कोशिश कर सकती है।

हालांकि किसी संभावित गठबंधन या समझौते के सामने कई चुनौतियां भी हैं। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और उसकी अपनी संगठनात्मक संरचना है। वहीं तृणमूल कांग्रेस का पूरा राजनीतिक मॉडल ममता बनर्जी के नेतृत्व के इर्द-गिर्द विकसित हुआ है। दोनों दलों के कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं के बीच भी कई क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा रही है। ऐसे में किसी भी बड़े राजनीतिक समझौते को जमीन पर लागू करना आसान नहीं होगा।

फिर भी यह तथ्य नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि भारतीय राजनीति में जनाधार का क्षरण दलों को नए विकल्प तलाशने के लिए मजबूर करता है। जब राजनीतिक समर्थन घटने लगता है तो विचारधारात्मक मतभेद भी अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण हो जाते हैं और अस्तित्व का प्रश्न प्रमुख हो जाता है। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस की वर्तमान स्थिति को इसी दृष्टि से देखा जाना चाहिए।

आज कांग्रेस अपने गौरवशाली अतीत और अनिश्चित भविष्य के बीच खड़ी है। वहीं तृणमूल कांग्रेस अपने क्षेत्रीय प्रभुत्व को बचाए रखने की चुनौती का सामना कर रही है। दोनों दलों के सामने सबसे बड़ी आवश्यकता जनता का विश्वास दोबारा अर्जित करने की है। केवल राजनीतिक समीकरणों और नेताओं की मुलाकातों से जनाधार वापस नहीं आता। इसके लिए मजबूत संगठन, स्पष्ट नेतृत्व, विश्वसनीय नीतियां और जनता के मुद्दों से निरंतर जुड़ाव आवश्यक होता है।

राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की हालिया मुलाकातों ने राजनीतिक अटकलों को जरूर हवा दी है, लेकिन इन मुलाकातों का वास्तविक महत्व आने वाले समय में ही स्पष्ट होगा। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि यह दौर भारतीय राजनीति में नए समीकरणों के निर्माण का है। जिन दलों ने कभी एक-दूसरे के खिलाफ अपनी राजनीतिक पहचान बनाई थी, वे आज बदलती परिस्थितियों के कारण संवाद की राह पर दिखाई दे रहे हैं।

यह केवल दो दलों की कहानी नहीं है, बल्कि भारतीय राजनीति के उस बड़े सत्य का उदाहरण है जिसमें जनाधार ही सबसे बड़ी शक्ति होता है। जब जनाधार मजबूत होता है तो दल आत्मविश्वास से भरे रहते हैं, लेकिन जब वह कमजोर पड़ने लगता है तो नए सहयोगियों की तलाश और पुराने रिश्तों की पुनर्स्थापना राजनीति की अनिवार्यता बन जाती है। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस की मौजूदा स्थिति भी इसी राजनीतिक यथार्थ को प्रतिबिंबित करती है। आने वाले महीनों में यह स्पष्ट होगा कि ये मुलाकातें केवल राजनीतिक शिष्टाचार थीं या फिर भारतीय राजनीति में किसी नए अध्याय की शुरुआत का संकेत।

मतदान से पहले मात: जब चुनाव का निवाला मुंह तक आकर छिन गया

गिरीश उपाध्याय

राजनीति में हार हमेशा मतपेटियों से नहीं निकलती। कई बार पराजय की पटकथा मतदान से पहले ही लिख दी जाती है। कभी नामांकन पत्र की मेज पर, कभी कानूनी व्याख्या में, कभी रणनीतिक चूक में और कभी राजनीतिक प्रबंधन के किसी ऐसे मोड़ पर, जहां चुनाव औपचारिकता बनकर रह जाता है। मध्यप्रदेश के राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन के साथ जो हुआ, वह इसी श्रेणी की घटना है। 11 जून को भारतीय जनता पार्टी के तीनों प्रत्याशी - तरुण चुघ, रजनीश अग्रवाल और महेश केवट - निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिए गए।

इससे पहले मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र निर्वाचन अधिकारी द्वारा निरस्त किया जा चुका था। कांग्रेस चुनाव आयोग पहुंची, सुप्रीम कोर्ट पहुंची, विरोध प्रदर्शन हुए, संवैधानिक सवाल उठाए गए, लेकिन तत्काल राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार करते हुए मामले की सुनवाई बाद के लिए रखी। परिणामस्वरूप राजनीतिक फैसला पहले हो गया और कानूनी बहस बाद के लिए बची रह गई। यही इस पूरे प्रकरण का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। अदालत का अंतिम निर्णय जो भी हो, फिलहाल भाजपा तीन सीटें जीत चुकी है और कांग्रेस एक ऐसी चुनावी लड़ाई हार चुकी है, जिसमें मतदान तक नहीं हुआ। यह घटना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह केवल एक राज्यसभा सीट का मामला नहीं है। यह चुनावी कानून, निर्वाचन अधिकारियों की शक्तियों, राजनीतिक दलों की तैयारी, चुनावी प्रबंधन और लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा की प्रकृति से जुड़ा प्रश्न बन गया है। कांग्रेस का तर्क है कि मीनाक्षी नटराजन के विरुद्ध कोई ऐसा लंबित आपराधिक मामला नहीं था जिसे छिपाने का आरोप लगाया जा सके। पार्टी का कहना है कि नामांकन निरस्त करना कानून और चुनाव आयोग की स्थापित परंपराओं के विपरीत है। कांग्रेस नेताओं ने चुनाव आयोग से हस्तक्षेप की मांग की और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया। दूसरी ओर भाजपा का पक्ष है कि शपथ पत्र में आवश्यक जानकारी का खुलासा न करना गंभीर मामला है और चुनावी पारदर्शिता के सिद्धांत के तहत निर्वाचन अधिकारी ने सही निर्णय लिया। भाजपा इसी तर्क के आधार पर इसे कानून की स्वाभाविक प्रक्रिया बता रही है। कानूनी दृष्टि से विवाद का केंद्र जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 36 और नामांकन पत्रों की जांच की प्रक्रिया है। प्रश्न यह है कि क्या कथित रूप से छूटी हुई जानकारी इतनी महत्वपूर्ण थी कि उसके आधार पर नामांकन निरस्त किया जा सके। कांग्रेस का कहना है कि नहीं। भाजपा और निर्वाचन अधिकारी की कार्रवाई का समर्थन करने वाले लोग कहते हैं कि हां। यही प्रश्न आगे न्यायिक समीक्षा का विषय बनेगा। लेकिन राजनीति में अक्सर कानूनी सत्य और राजनीतिक सत्य अलग-अलग रास्तों पर चलते हैं। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो कांग्रेस की पहली हार अदालत में नहीं, तैयारी में हुई है। यह मानना कठिन है कि राहुल गांधी की निकट सहयोगी और पूर्व सांसद जैसी वरिष्ठ नेता का नामांकन भरने से पहले कानूनी जांच नहीं हुई होगी। यदि हुई थी तो यह त्रुटि कैसे रह गई? यदि नहीं हुई थी तो यह और भी गंभीर प्रश्न है। यहीं से यह मामला कांग्रेस की संगठनात्मक क्षमता पर सवाल खड़े करता है। मध्य प्रदेश की राजनीति में यह पहली बार नहीं हुआ कि चुनाव का निवाला मुँह तक आकर छिन गया हो।

नीति आयोग की बैठक से निकला नया विकास मंत्र

विनोद कुमार सिंह

नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में सम्पन्न नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक केवल एक प्रशासनिक औपचारिकता नहीं थी,बल्कि भारत के भविष्य की विकास दिशा तय करने वाला एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय विमर्श था। विकसित राज्य से विकसित भारत की थीम पर आयोजित इस बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने- अपने प्रदेशों की आवश्यकताओं, चुनौतियों और विकास संबंधी सुझावों को केंद्र सरकार के समक्ष रखा।सर्वविदित रहे यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा है। वर्तमान में देश की अर्थव्यवस्था लगभग 4.3 ट्रिलियन डॉलर के स्तर पर पहुंच चुकी है और अगले दशक में इसे 10 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है।ऐसे में राज्यों की भागीदारी और उनकी विकास क्षमता निर्णायक महत्व रखती है।बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट कहा कि विकसित भारत का सपना दिल्ली में बैठकर पूरा नहीं किया जा सकता।इसके लिए राज्यों को विकास का इंजन बनना होगा। उन्होंने राज्यों से निवेश आकर्षित करने, रोजगार सृजन,कृषि आधुनिकीकरण,कौशल विकास और डिजिटल प्रशासन को बढ़ावा देने का आह्वान किया।इस बैठक का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों द्वारा रखे गए सुझाव और मांगें रहीं।इन सुझावों ने यह स्पष्ट कर दिया कि राज्यों की प्राथमिकताएं अलग-अलग हो सकती हैं,लेकिन लक्ष्य एक ही है—तेज,समावेशी और सतत विकास। मोहन यादव ने मध्य प्रदेश को कृषि एवं औद्योगिक हब बनाने के लिए सिंचाई परियोजनाओं, लॉजिस्टिक कॉरिडोर और कृषि प्रसंस्करण उद्योगों के विस्तार पर बल दिया। उन्होंने केंद्र से अधोसंरचना परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त सहयोग की माँग की।नबाब सिंह सैनी ने हरियाणा को विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए औद्योगिक गलियारों, कौशल विकास और एमएसएमई क्षेत्र को और मजबूत बनाने की आवश्यकता बताई।उन्होंने कृषि में ड्रोन तकनीक तथा आर्टिफिशियल

इंटेलिजेंस के उपयोग को बढ़ावा देने का सुझाव भी दिया।भजन लाल शर्मा ने जल संकट को राजस्थान की सबसे बड़ी चुनौती बताते हुए नदी जोड़ो परियोजनाओं और जल संरक्षण कार्यक्रमों में केंद्र के सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया।साथ ही उन्होंने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में राजस्थान की भूमिका को और मजबूत करने की बात कही।योगी आदिनाथ ने उत्तर प्रदेश के तेजी से बढ़ते औद्योगिक निवेश,एक्सप्रेसवे नेटवर्क और डिफेंस कॉरिडोर का उल्लेख करते हुए राज्यों को अधिक वित्तीय लचीलापन देने की मांग रखी ताकि विकास परियोजनाओं को गति मिल सके।देवेन्द्र फडनवीस ने मुंबई महानगर क्षेत्र, सेमीकंडक्टर उद्योग और हरित ऊर्जा निवेश को राष्ट्रीय विकास का प्रमुख आधार बताते हुए वैश्विक निवेश आकर्षित करने के लिए राज्यों को अधिक नीति समर्थन देने की बात कही।पूर्वोत्तर राज्यों के प्रतिनिधियों ने सड़क,रेल और डिजिटल कनेक्टिविटी को अपनी प्रमुख प्राथमिकता बताया।उनका मत था कि बेहतर संपर्क व्यवस्था ही क्षेत्रीय विकास और राष्ट्रीय एकीकरण का आधार बनेगी।इस बैठक में कृषि क्षेत्र पर विशेष चर्चा हुई।आज भी लगभग 45 प्रतिशत भारतीय आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। राज्यों ने प्राकृतिक खेती,सूक्ष्म सिंचाई,कृषि निर्यात और भंडारण सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया। कई मुख्यमंत्रियों ने कृषि मूल्य श्रृंखला को मजबूत बनाने के लिए केंद्र और राज्यों के संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता बताई।स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र भी चर्चा के केंद्र में रहे। राज्यों ने चिकित्सा शिक्षा संस्थानों की संख्या बढ़ाने, जिला अस्पतालों को सुदृढ़ बनाने तथा नई शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता पर बल दिया।भारत की 65 प्रतिशत से अधिक आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है। इसलिए कौशल विकास और रोजगार सृजन को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाने पर व्यापक सहमति दिखाई दी। हरित ऊर्जा को लेकर भी महत्वपूर्ण विचार सामने आए। भारत ने वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर- जीवाश्म ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य रखा है।राजस्थान,गुजरात,तमिलनाडु और महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने सौर एवं पवन ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश बढ़ाने के लिए केंद्र के साथ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।

डिजिटल इंडिया की उपलब्धियों का भी उल्लेख हुआ।आज भारत में 150 करोड़ से अधिक आधार प्रमाणीकरण प्रतिमाह हो रहे हैं और यूपीआई लेन-देन विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान नेटवर्क बन चुका है।राज्यों ने डिजिटल प्रशासन और सेवा वितरण में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्रणालियों को अपनाने का सुझाव दिया।इस बैठक का सबसे महत्वपूर्ण संदेश सहकारी संघवाद की भावना का और अधिक मजबूत होना रहा।केंद्र और राज्यों के बीच संवाद,सहयोग और साझेदारी के माध्यम से विकास के नए मॉडल विकसित करने पर सहमति बनी। यह स्पष्ट हुआ कि विकसित भारत का मार्ग राज्यों से होकर ही गुजरता है।

निष्कर्षत: नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक ने केवल नीतिगत चर्चा नहीं की,बल्कि भारत के अगले दो दशकों के विकास का व्यापक खाका प्रस्तुत किया।मुख्य मंत्रियों के सुझावों और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की विकास दृष्टि ने यह संकेत दिया है कि आने वाले वर्षों में भारत का विकास मॉडल अधिक विकेंद्रीकृत,सहभागी और परिणामोन्मुख होगा।यदि इस बैठक में सामने आए सुझावों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है, तो वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य केवल एक सरकारी संकल्प नहीं,बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की सामूहिक उपलब्धि बन सकता है।यही इस बैठक का सबसे बड़ा संदेश और सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष है।

मोदी के 12 साल: भरोसे के हकीकत में बदलने का दौर

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा

यदि मॉर्निंग कंसल्ट की माने तो दुनिया के नेताओं की सूची पर एक नजर दौड़ाई जाएं तो केई भी वैश्विक नेता स्वीकार्यता में नरेन्द्र मोदी के आसपास भी नहीं टिकते। विपक्षी पार्टियां द्वारा लगातार देश और विदेश में अभियान चलाने के बावजूद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रेंकिंग या स्वीकार्यता के मामलें में वैश्विक नेताओं से बहुत आगे हैं। 68 प्रतिशत स्वीकार्यता नरेन्द्र मोदी की है जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की स्वीकार्यता रेंक लगातार नेगेटिव जा रही है। फालोवर्स में भी नरेन्द्र मोदी सबसे आगे हैं। दुनिया का संभवत: हमारा ही देश होगा जहां देश के बाहर भारत की छवि खराब करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही उसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की यह स्वीकार्यता निश्चित रुप से भारत ही नहीं दुनिया के अन्य देशों में भी उनकी लोकप्रियता और सर्वमान्यता को दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले चुनिंदा प्रधानमंत्री बन गए हैं। चुनिंदा इसलिए कि देश में पहले लोकसभा चुनाव 1952 में हुए पर पं. नेहरु 1947 से 1952 तक भी प्रधानमंत्री रहे। लगातार 12 साल कोई कम नहीं होते और वह भी लगातार 12 साल। सबसे बडी बात यह कि इस दौरान नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा ऐसे साहसिक निर्णय किये गये हैं जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। माना तो यही जाता था कि कश्मीर में धारा 370 और 35 ए हटाना, राममंदिर का निर्माण, डिजिटल क्रांति, वैश्विक नेतृत्व, नोटबंदी, एक देश एक कर, घर घर शोचालय, घर घर कचरा संग्रहण, रक्षा उपकरणों का निर्यात, किसान सम्मान, मेक इन इंडिया, इंडिया फर्स्ट, बड़ी अर्थ व्यवस्था, तेजी से ढांचागत विकास, डिजिटल भुगतान, नक्सलवाद की नेस्तनाबूदी, आत्मनिर्भर भारत, परिवहन क्षेत्र में ढांचागत बदलाव आदि आदि समय पर की जाने वाली घोषणाएं केवल चुनाव जीतने के जुमले हैं पर लगभग असंभव माने जाने वाले यह काम आज धरातल पर उतरना सबसे बड़ी उपलब्धी मानी जा सकती है। इससे सबके साथ ही सबसे आश्चर्य

जनक बात यह है कि लाख विरोध के बावजूद विपक्ष आज हाशिये में चला गया है।

कश्मीर से धारा 370 और 35 ए की समाप्ति हो चुकी है। दुनिया के किसी देश ने खुलकर इसका विरोध करने की हिम्मत नहीं दिखाई। बाबरी मस्जिद के स्थान पर राममंदिर का निर्माण हो चुका है तो तीन तलाक, सीएए, यूसीसी और यहां तक कि सर्जीकल स्ट्राइक के बाद ऑपरेशन सिन्दुर तक पर दुनिया के किसी देश की भारत के खिलाफ खुलकर आवाज उठाने की हिम्मत नहीं हो पाई है। आज अर्थ व्यवस्था में जिस तेजी से बदलाव आया है और चौथी बड़ी अर्थ व्यवस्था बनने के बाद अब तीसरी बड़ी अर्थ व्यवस्था बनने की और तेजी से कदम बढ़ चुके हैं। जनधन योजना के समय जिस तरह से आलोचना का दौर चला था आज भुगतान में डिजिटलीकरण में इसकी बड़ी भूमिका तय हो चुकी है। जो लगभग असंभव माना जा सकता था वह आज डिजिटल भुगतान के माध्यम से संभव हो पाया है और पांच रु. के टमाटर का भुगतान भी सब्जीवाले तक को यूपीआई से आसानी से होने लगा है। सरकारी सामाजिक सुरक्षा योजना के भुगतान, पेंशन, अनुदान आदि आज सीधे खातों में जाने लगे हैं। यह किसी दिवा स्वप्न से कम नहीं है। आईपीसी सीपीसी में बदलाव किया जा चुका है। तो जीएसटी में लाख कमियां गिनाने के बावजूद आज समूचा देश एक देश एक कर के छाते के नीचे आ चुका है। बुनियादी ढांचें में तेजी से बदलाव आया है। आज वंदे भारत और नमो भारत ट्रेन चलने लगी है तो 33 किमी प्रतिदिन हाईवे का निर्माण हो रहा है। एक्सप्रेस हाईवे से आवागमन आसान हुआ है। आयुष्मान योजना से 50 करोड़ लोगों को जोड़ा जा चुका है तो सस्ती जेनेरिक दवाओं की उपलब्धता का नेटवर्क विस्तारित किया गया है। आज 98 प्रतिशत घरों से घर घर कचरा संग्रहण होने लगा है तो अब घर घर में शोचालय बन चुके हैं। कोरोना के दौरान हमारे प्रयासों को सारी दुनिया द्वारा सराहा गया यहां तक कि कोरोना के दौरान जीवन रक्षक की भूमिका में भारत ने भूमिका निभाई। किसानों की आय में बढ़ोतरी के ठोस प्रयास हुए हैं तो किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों को उनका आत्मसम्मान उपलब्ध कराया गया है। एमएसपी व्यवस्था में सुधार हुए हैं तो खेती किसानी के क्षेत्र में बदलाव छाप दिखाई दे रहा है। मेक इन इंडिया और इंडिया फर्स्ट भी आज साकार होता दिखाई दे रहा है। आज हम रक्षा उपकरणों का निर्यात करने लगे हैं तो सहस्त्रबलों के आधुनिकीकरण और निर्णय की स्वतंत्रता का परिणाम है कि आज सेनाएं आत्मगौरव के साथ आगे बढ़ रही है। आज देश आत्म निर्भर भारत की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

जहां तक कूटनीतिक स्तर पर सफलता की बात है तो भारत आज पिछलग्गू देशों में नहीं बल्कि दुनिया का नेतृत्व करने की स्थिति में आ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लाख प्रयासों के बावजूद भारत के खिलाफ कुछ खास कर नहीं पा रहे हैं। पाकिस्तान के पक्ष में आज तुरकिया जैसे एकाध को छोड़कर कोई देश बोलने की स्थिति में नहीं है। मालदीव को नरेन्द्र मोदी के एक फोटो ट्वीट ने सबक सीखा दिया तो दूसरे देश भी भारत की ताकत को समझने लगे हैं।

खैर यह सब होते हुए भी नरेन्द्र मोदी सरकार के सामने अभी चुनौतियां कम नहीं हैं। रोजगार सृजन, प्रति व्यक्ति आय में अंतर, शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, जल जीवन मिशन के बावजूद पेयजल की सहज उपलब्धता, खेती की बरसात पर निर्भरता, परिसीमन आदि ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिन पर ठोस काम किया जाना है। देश में जिस तरह से पेपर लीक होने के मामले सामने आये हैं इससे युवाओं में निराशा हुई है उसे दूर करने की चुनौती सामने हैं तो स्टार्ट अप और

विपक्षी एकता क्या महज दिवास्वप्न है?

अभिलाष खांडेकर

बिखरते हुए इंडिया गठबंधन की नई दिल्ली में बैठक में बड़ी संख्या में ऐसे मतदाताओं को निराशाजनक रूप से कुछ भी नया नहीं मिला, जो इस विचार से सहमत हैं कि एक मजबूत लोकतंत्र के लिए विपक्षी दलों का वर्तमान स्थिति से अधिक मजबूत होना आवश्यक है। इससे एक बार फिर यह बात साफ हो गई कि हमारे राजनेता कितने स्वार्थी हैं और नरेंद्र मोदी जैसे दिग्गज के सामने वे कितने छोटे और कमजोर नजर आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पंडित नेहरू का सर्वाधिक समय तक शीर्ष पद पर रहने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मैं इंडिया गठबंधन के गठन के बाद से ही इसके उतार-चढ़ाव भरे सफर को करीब से देख रहा हूं। असम और बंगाल में हार के बाद पिछले हफ्ते दिल्ली में दो साल बाद इनकी मुलाकात हुई। इससे लगता है कि स्वार्थपरक रवैया ही इस समूह को बांधे रखने वाला प्रमुख कारक है, जिसमें ज्यादातर पार्टियां एक-दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करतीं, साझा मंच पर बात करना तो दूर की बात है। यह विशेषता ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल में साफ तौर पर दिखाई देती है। अब पराजित डीएमके नेता एमके स्टालिन भी इनके साथ जुड़ गए हैं, जिससे यह एक अनोखी तिकड़ी बन गई है। बेंगलुरु से पहले पटना में 15 से अधिक पार्टियों की प्रारंभिक बैठक हुई, जिसकी मेजबानी अब भले ही अविश्वसनीय लगे, लेकिन नीतीश कुमार ने की। कुमार, जो अब मुख्यमंत्री नहीं हैं, एनडीए की आरामदायक कुर्सी पर मजबूती से बैठे हैं और संसद के ऊपरी सदन के सदस्य के रूप में भाजपा की प्रशंसा कर रहे हैं। खैर! उनके बारे में बहुत कुछ लिखा जा चुका है। ममता और केजरीवाल - दोनों गठबंधन के संस्थापक सदस्य - ने गठबंधन में सक्रिय रूप से शामिल होने को लेकर अक्सर अपनी गंभीर आपत्तियां व्यक्त की थीं। दूसरे शब्दों में, भले ही वे गठबंधन के साझेदारों के साथ एकजुट दिखाई देते थे, लेकिन गुप्त रूप से उनकी अपनी योजनाएं थीं। अपने-अपने राज्यों के मुख्यमंत्री के रूप में दोनों ने स्वयं को हमेशा के लिए अजेय मान लिया था। दोनों क्षेत्रीय शक्तियां रही हैं और उनकी पार्टियों की लोकप्रियता पार्टी कार्यक्रमों या संगठनात्मक ताकत से कहीं अधिक उनके लोकप्रिय नेताओं पर निर्भर करती थी। सबसे पहले 'ईमानदार राजनेता' अरविंद केजरीवाल सत्ता से बाहर हुए, जिन्हें शराब घोटाले में जेल हुई। उसके बाद ममता बनर्जी का नंबर आया, जिन्हें एक महीने से भी कम समय में तीन बार करारी हार का सामना करना पड़ा। पहले तो वे खुद चुनाव हार गईं, फिर उनकी पार्टी ने बंगाल में सत्ता खो दी और अब पार्टी विभाजित हो चुकी है। भवानीपुर सीट पर करारी हार के बाद उनकी चमक फीकी पड़ गई है। अब वे इंडिया गठबंधन की बैठक में दिखना तो चाहती हैं, लेकिन उनके पास देने के लिए कुछ खास नहीं है। एक समय ऐसा था जब ममता खुलेआम 23 दलों के विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व करने की कांग्रेस की क्षमता पर सवाल उठाती थीं और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि वह इस गठबंधन का नेतृत्व कहीं बेहतर तरीके से करेंगी। केजरीवाल, जिन पर पहले से ही भाजपा की 'बी टीम' होने का आरोप है, अपने निजी कारणों से इंडिया गठबंधन के नेताओं से दूरी बना रहे हैं। उनकी पार्टी में भी फूट पड़ रही है। जून में हुई बैठक में वे अनुपस्थित रहे, जिससे कांग्रेस के प्रति उनकी गहरी नापसंदगी जाहिर होती है, जो इस समय गठबंधन में सबसे आगे है। इससे पहले, उन्होंने गठबंधन को अनिश्चित स्थिति में रखा था और सीट बंटवारे के फार्मूले को मानने से इनकार कर दिया था। सभी दलों के लिए एकता न तो ममता की प्राथमिकता थी और न ही केजरीवाल की। अगर सभी विपक्षी दल 2024 के आम चुनावों में एक जीतने योग्य उम्मीदवार उतारने पर सहमत हो जाते - जो कि एक मुश्किल काम है - तो वोटों का बंटवारा टाला जा सकता था। नतीजा बिलकुल अलग होता। फिर भी, खंडित विपक्ष भाजपा को 400 सीटों से काफी नीचे रोकने में कामयाब रहा। अगर ममता और केजरीवाल ने सहयोग किया होता तो स्थिति बिल्कुल अलग हो सकती थी। इसलिए सवाल यह है कि अस्सी वर्षीय मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, उम्रदराज और बीमार शरद पवार, उमर अब्दुल्ला, उद्धव ठाकरे और अन्य नेताओं के लिए 2029 में भाजपा की उस विशाल लहर को रोकना कितना आसान या कठिन है, जिसके लिए वे अभी से जमीन तैयार कर रहे हैं।

बालों के हिसाब से चुनें शैंपू ...

आजकल बाजार में कई प्रकार के शैंपू और कंडीशनर उपलब्ध हैं तो, ऐसे में सवाल यह उठता है कि आप अपने बालों के हिसाब से कौन सा शैंपू चुनेंगी जो बालों को सूट करे। कभी भी विज्ञापन देख कर शैंपू और कंडीशनर नहीं खरीदना चाहिए। हमेशा देख लें कि जो शैंपू आप खरीदने जा रही हैं, उसमें क्या-क्या सामग्री मिली हुई है। अगर आपके बाल कर्ली हें तो आपको क्रीमी और नमी प्रदान करने वाला शैंपू प्रयोग करना चाहिए। इसमें शिया बटर, जर्म ऑयल और नट ऑयल मिला होना चाहिए। इसके अलावा आपको अल्ट्रा कंडीशनिंग मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए। अगर आपके बाल ऑयली है तो आपको क्रीमी शैंपू और कंडीशनर नहीं लगाना चाहिए। ऐसा प्रोडक्ट चुनें जिसमें पेन्थिनॉल मिला हो। यह ऐसा तत्व है जो बालों की मोटाई बढाता है। स्प्रे कंडीशनर का प्रयोग कीजिए जो कि बालों सिर की त्वचा तक नहीं जाता है और केवल बालों तक ही सीमित रहता है। टूटे और रूखे बालों के लिए क्रीमी शैंपू सही होता है। इसके साथ ही रोजाना कंडीशनिंग की भी जरुरत होती है। ऑयली एंड ड्राय बालों में जड़े तो ऑयली रहती हैं लेकिन बालों का आखिरी छोर रूखा रहता है। तो, ऐसे में आपको रोजाना साधारण शैंपू का प्रयोग कर के बाल धोने चाहिए। कंडीशनर का प्रयोग कीजिए लेकिन उसे बालों की जड़ों पर मत लगाइए वरना वह ऑयली हो जाएंगे। सिलीकॉन मिला हुआ कंडीशनर ना प्रयोग करें वरना यह कलर किए हुए बालों को खराब कर सकता है।

देर तक ऐसे टिकाएं लिपस्टिक...

मेकअप में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखने वाली लिपस्टिक ज्यादातर महिलाओं की प्रिय होती है। पर समस्या यह आती है कि लिपस्टिक होठों पर ज्यादा देर तक टिकी नहीं रहती। लिपस्टिक का शेड स्किन टोन से बिल्कुल मैच करते हुए होना चाहिए, तभी वह आपके होठों पर भाएगी। यदि आपको होठों पर लिपस्टिक ज्यादा समय के लिए टिका कर रखना है तो उसे होठों पर लगाने से पहले प्रिटोलियम जैली लगा लें। इस तरह से वह ज्यादा देर तक होठों पर टिकी रहेगी। यदि आप चाहती हैं कि आपकी लिपस्टिक ज्यादा देर के लिए टिकी रहे तो, लगाने के एक रात पहले उसे फ्रिज में रख दें। एक्सपर्ट का मानना है कि ऐसा करने से लिपस्टिक लंबे समय तक होठों पर टिकी रहती है। सही तरह का बेस लगाने के लिए आपको होठ पर हल्का सा पाउडर लगाना चाहिए। पाउडर लगे होठ पर लिपस्टिक लगाएं। ऐसा करने के बाद यदि आप एक कप कॉफी भी पीती हैं तो भी आपकी लिपस्टिक नहीं छूटेगी। मोटे होठों पर डार्क कलर की लिपस्टिक बहुत अच्छी दिखती है और इससे होठ ज्यादा सुंदर और गुलाबी दिखाई देते हैं। अगर आपको होठों पर उभार दिखाने हैं तो उसके किनारे पतली लिप लाइनर लगा कर उसे होठों पर लिपस्टिक के साथ भर लें। बुजुर्ग महिलाओं को लिपस्टिक लगानी है तो वे बोल्ड और डार्क लिपस्टिक न लगाएं। लिपस्टिक के दो शेड्स को कभी नहीं मिला कर लगाना चाहिए।

आंख हमारे शरीर का वह हिस्सा है, जो सच्ची फिलिंग को व्यक्त करता है। अगर आप इसे और आकर्षक बनाना चाहती हैं तो इनका अच्छे से मेकअप करना होगा। हर किसी की आंखों का आकार एक समान नहीं होता। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि हम अपनी आंखों के आकार के अनुसार ही मेकअप करें।

ऐसे करें आंखों का मेकअप...

आंखे मानव शरीर के सबसे अहम हिस्सों में से एक है। इसके बिना इस सुंदर दुनिया की सिर्फ हम कल्पना कर सकते। आपकी आंखों का मेकअप हिट भी हो सकता है और फ्लॉप भी। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप मेकअप कैसे करती हैं और किससे कराती हैं। आप सावधानी से मेकअप करके अपनी आंखों को जीवंत बना सकती हैं। चमकदार आंखें हर जगह चर्चा में रहती हैं और ध्यान भी आकर्षित करती हैं। जब भी आप किसी मेकअप का चुनाव करें तो थोड़ी सावधान रहें। यह जरूर देख लें कि आपका मेकअप आपके आउटफिट से मेल खाता हो। आप चाहे परंपरागत आउटफिट को पसंद करती हों या फिर मॉडर्न आउटफिट को, पर आंखों का मेकअप ही आपको भीड़ से अलग दिखाएगा। यह भी सच है कि हर किसी की आंखों का आकार एक समान नहीं होता। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि हम अपनी आंखों के आकार के अनुसार ही मेकअप करें। अगर आपकी आंखों का आकार छोटा है तो आंखों का मेकअप इस प्रकार करें कि आपकी आंखें बड़ी लगें। गोल आंखों के लिए डार्क आईशैडो परफेक्ट होते हैं। क्लोज सेट आईज आपस में लगभग सटी हुई लगती हैं। ऐसी आंखों के लिए इनर कॉर्नर पर लाइट आईशैडो और आउटर कार्नर पर इंटेल कलर अप्लाई करें।

उभरी आंखें

उभरी आंखें यानी कॉन्वेक्स आईज वैसी आंखें होती है जो बाहर की तरफ निकली हुई होती हैं। इसलिए इन्हें बल्जिंग या प्रोट्रूडिंग आईज भी कहते हैं। इन आंखों को मीडियम कलर से गहरे रंग तक के आई शैडो से पलकों पर शेड दें। इन पर कभी भी फ्रॉस्टेड शेड्स या हाईलाइटर न इस्तेमाल करें। इससे आंखें और ज्यादा उभरी नजर आएंगी और आपकी खूबसूरती बिगाड़ सकती है। आंखों के निचले किनारों पर काजल पेंसिल लगाएं। ऊपरी आईलैशेज पर मसकारा के एक-दो हलके कोट्स लगाए जा सकते हैं।

गहरी आंखें

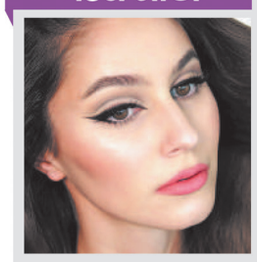

डीप सेट यानी गहरी आंखें भीतर धंसी हुई दिखती हैं। इनमें ब्रो बोन यानी आंखों और भौंहों के बीच की हड्डी का उभार भी कम होता है। इन पर ऐसा मेकअप किया जाना चाहिए जिससे आंखें उभरी दिखें। पलकों पर हलका दबा हुआ पिंक या बेज शैडो लगाना अच्छा रहेगा। आंखों की ऊपरी रेखा यानी क्रीज की तरफ उसे हलका करें। मीडियम-टोंड आई शैडो का इस्तेमाल करें और ब्रो बोन से शुरू करके ब्रो के किनारों तक लगाएं। आंखों के ऊपरी हिस्से में बनी लाइन को स्मोकी-कलर शैडो से गहरा करें। यह पूरे मेकअप से मैच करने वाला हो। और आखिर में काली या भूरी पेंसिल से काजल लगाएं।

क्लोज-सेट आईज

क्लोज-सेट आईज में दोनों आंखों के बीच की दूरी कम दिखाई पड़ती है। यानी नाक से इनकी दूरी जरा कम होती है। इन आंखों के मेकअप के लिए पलकों के भीतरी हिस्से पर हलका और बीच के हिस्से पर मीडियम शेड लगाएं। ऊपरी पलकों के बाहरी किनारों पर एक लाइन सी खींचें। अब ब्रो बोन के बाहरी यानी कान की ओर वाले हिस्से पर गहरा शैडो लगाकर उसे अच्छी तरह एकसार करें। आंखों में ब्लैक काजल लगा सकती हैं। अगर आप मसकारा लगाना चाहती हैं तो भीतरी लैशेज पर हलके रंग का और बाहरी तरफ थोड़ा गहरे रंग को इस्तेमाल में लाएं। बाहरी तरफ उसे थोड़ा उभारने की कोशिश करें और भौंहों की ओर थोड़ा कम उभारें।

एशियन आईज

नाक की तरफ भीतरी किनारों की ओर थोड़ी झुकी हुई आंखों को एशियन आईज कहते हैं। इनमें शैडो का प्रयोग करते समय लेयरिंग इफेक्ट देने के लिए तीन रंगों का प्रयोग करें। आई लैशेज के पास हलका शैडो लगाएं, पलकों पर मीडियम कलर और ब्रो बोंस पर बेहद हलके रंग का प्रयोग करें। आंखों के किनारे लाइन या ऊपरी तरफ क्रीज बनाने से बचें। आई लाइनर का प्रयोग केवल आंखों के ऊपरी हिस्से पर करना बेहतर रहेगा।

वाइड सेट आईज

क्लोज-सेट आई की तुलना में वाइड सेट आईज की दूरी नाक से थोड़ी ज्यादा होती है। इसलिए ऐसे मेकअप की जरूरत होती है जो आंखों को बैलेंस दिखाए। आंखों और नाक के बीच वाले हिस्से पर छोटे ब्लशर ब्रश से अपने स्किन टोन से थोड़ा गहरे टोन पाउडर लगाएं। नाक की तरफ ब्रश करते हुए पाउडर को एकसार करें। ब्रो की बाहरी रेखा पर न्यूट्रल-टोंड हाईलाइटर का इस्तेमाल करें। क्रीज लाइन यानी आंखों के ऊपरी हिस्से पर पडने वाली रेखा पर शेड दें और आंख के भीतरी किनारे यानी नाक की तरफ वाले हिस्से को उभारें। आंख के बाहरी किनारे पर हलके मैट शैडो से ब्रश करके आई मेकअप को पूर्णता दें। मसकारा लगाते समय लैशेज सीधी रखें। उसके बाहरी हिस्से पर दाहिनी तरफ ज्यादा मसकारा लगाएं।

उनींदी आंखें

उनींदी आंखों यानी हूडेड आईज में आईलैशेज बहुत कम होते हैं, वैसी आंखें उनींदी सी लगने लगती हैं। इस तरह की आंखों को ऐसा मेकअप करने की जरूरत होती है जिनसे ये थोड़ी सजग दिखाई दें। सोई-सोई सी या नशीली सी न दिखें। पलकों के भीतरी आधे हिस्से पर मैट या न्यूट्रल कलर का आई शैडो लगाएं। उसके आसपास के हिस्से पर थोडा गहरा रंग लगाएं, लेकिन इसे बाहरी हिस्से में न लगाएं। गहरे रंग के इस्तेमाल से परहेज करें। इससे आपकी पलकें भारी लगने लगेंगी। आंखों के ऊपरी और निचले किनारों पर भी गहरे रंगों का इस्तेमाल न करें। ऊपरी लैशेज को थोड़ा कर्ल करें और मसकारा के एक-दो कोट्स ही लगाएं। ब्रो बोन पर मीडियम शेड्स का इस्तेमाल करें। यहां न तो बहुत चटख और चमकीले रंगों का प्रयोग करें और न ही बहुत हलके रंगों का।

आमंड शेप्ड आईज

आमंड शेप्ड आईज को सर्वोत्तम माना जाता है। इन्हें कई तरह से सजाया जा सकता है। जैसे बारीक आई लाइनर, कृत्रिम आई लैशेज, ब्राइट कलर्स। सबसे पहले ब्रो बोन में स्किन टोन के मुताबिक हलके रंग का शैडो प्रयोग में लाएं। आई लिड (पलकों) से कुछ शेड गहरा रंग चुनें। आंख के निचले किनारों पर ब्लैक या ब्राउन काजल पेंसिल से रेखा बनाएं। आंखों के बाहरी किनारों की तरफ उभारने की कोशिश करें। अगर आपकी आंखें नीली हैं तो ब्लू पेंसिल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

राउंड आईज

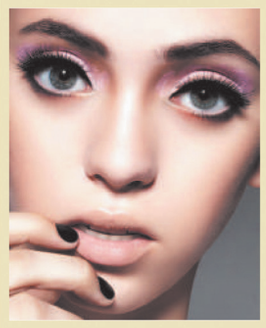

राउंड आईज यानी गोल आंखों के लिए गहरे रंग का शैडो चुनें। नाक की ओर से शुरू करके ब्रो के बाहरी तरफ ऊपर ले जाते हुए शैडो को अच्छी तरह एकसार करें। निचली पलक पर हलके टोंड शैडो या पेंसिल का प्रयोग करें और इसे ऊपर की ओर बाहरी हिस्से तक ले जाएं। ब्रो लाइन के पास म्यूटेड हाईलाइटर लगाएं।

छोटी आंखें

आंखें यदि छोटी हैं तो इन्हें बड़ा दिखाने के लिए पलकों के बाहरी किनारे पर ऊपर की तरफ हलके रंग का पाउडर शैडो छोटे ब्लशर की मदद से लगाएं। क्रीज के पास गहरा शैडो प्रयोग करें। लेकिन नाक की तरफ आंखों के भीतरी हिस्से पर कोई रंग न प्रयोग करें, क्योंकि इससे आंखें और छोटी दिखने लगेंगी। किनारों पर शैडो लगाने के लिए ब्रश का प्रयोग करें। इसके बाद आंख के निचले हिस्से पर हलकी ग्रे कलर की काजल पेंसिल से रेखा बनाएं।

निस्तेज आंखें

निस्तेज आंखों के लिए आई मेकअप आंखों के भीतरी हिस्से से शुरू करें। ऊपरी और बाहरी तरफ मीडियम टोंड शैडो ब्रश की मदद से लगाएं। इसे ब्रो लाइन के ठीक पास तक लाकर छोड़ दें। पलकों की बाहरी रेखा पर किसी भी रंग का प्रयोग न करें। लेकिन आंख की ऊपरी क्रीज लाइन को थोड़ा उभारने की कोशिश करें, मीडियम ब्राउन आई शैडो से रेखा बनाएं, फिर अपनी पलकों को थोडा कर्ल करें। मसकारा के कुछ कोट्स भी इसमें मदद करेंगे।

चावल के पानी से चेहरा धोने के फायदे

उबले चावल के पानी यानी मांड के स्वास्थ्य लाभों के बारे में शायद आप जानती होंगी। लेकिन क्या आप जानती हैं कि यह पानी सेहत के लिए जितना फायदेमंद है, त्वचा के लिए उतना ही गुणकारी। जीं हां चावल आपकी खूबसूरती में चार चांद लगा सकता है। त्वचा की देखभाल के लिए घरेलू उपायों का प्रयोग करने वालों को पके चावल के पानी से बहुत फायदा हो सकता है। चावल के पानी का इस्तेमाल त्वचा की देखभाल के लिए भी किया जा सकता है। सप्ताह में एक बार इस घरेलू उपाय का इस्तेमाल करने से सौंदर्य से जुड़ी कई समस्याओं का निदान आसानी से हो जाता है।

त्वचा के लिए चावल का पानी

चावल के पानी में मौजूद प्रोटीन, विटामिन और एंटी-ऑक्सीडेंट की पर्याप्त मात्रा के कारण यह त्वचा में नमी बरकरार रहती है। इसके इस्तेमाल से त्वचा की रंगत निखरती है। चेहरे के दाग-धब्बे और झुर्रियां दूर होती हैं। इसके अलावा माड़ से त्वचा में कसावट आती है और पोर्स टाइट होते हैं। इन खूबियों के चलते यह पानी एक अच्छा क्लींजर भी है।

इस्तेमाल का तरीका

- एक कप चावल को अच्छी तरह से साफ करके पानी में भिगो दें।
- आधे घंटे के बाद जब चावल में मौजूद पोषक तत्व पानी में घुल जाए तो बर्तन को गैस में रख दें और चावल को पकने दें।
- चावल पकने के बाद उसका माड़ निकाल लें और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दें।
- फिर इस पानी से अपने चेहरे पर हल्के हाथों से मसाज करें।
- मसाज करने के 10 मिनट बाद चावल के पानी से ही अपना चेहरा धोकर सूखे कपड़े से चेहरा पोंछ लें।
- आपको तुरंत अपनी त्वचा में बदलाव नजर आने लगेगा।

बालों के लिए फायदेमंद

त्वचा के साथ-साथ बालों के लिए भी चावल का पानी बहुत फायदेमंद होता है। अगर आप पतले और बेजान बालों की समस्या से परेशान है तो चावलों के पानी से बालों को धोएं। चावल के पानी से बालों को धोने से बाल घने होने के साथ-साथ बालों में चमक भी बनी रहती है। चावल के पानी को अपने बालों में लगाकर 20 मिनट के लिए छोड़ दें। फिर शैम्पू और कंडीशनर से धो लें। आप महंगे ट्रीटमेंट के बिना पा सकते हैं, सुंदर और चमकीले बाल। लेकिन इस उपाय को अपनाने से पहले चिकित्सक से सलाह जरूर लें।

अगर आपको बारिश में भीगने का मनकर रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। बरसात में वाटरप्रूफ मेकअप करना चाहिए। वाटरप्रूफ मेकअप की सब से खास बात यह होती है कि बारिश का पानी भी इस का कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। रेन डांस और स्विमिंग पूल में मजा लेते वक्त भी वाटरप्रूफ मेकअप का कमाल दिखता है। पसीना आने पर मेकअप त्वचा के रोमछिद्रों में घुल कर अंदर चला जाता है, जिस से मेकअप बदरंग दिखाई देने लगता है। मेकअप रोमछिद्रों के जरिए शरीर के अंदर न जाए, वाटरप्रूफ मेकअप में यही किया जाता है। त्वचा के रोमछिद्रों को बंद कर के किया गया मेकअप ही वाटरप्रूफ मेकअप कहलाता है।

वाटरप्रूफ मेकअप प्रोडक्ट्स

वाटरप्रूफ मेकअप की बढ़ती मांग को देखते हुए मेकअप प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनियों ने वाटरप्रूफ मेकअप प्रोडक्ट्स बनाने शुरू कर दिए हैं। इन प्रोडक्ट्स के अंदर ऐसे तत्व डाल दिए जाते हैं, जो मेकअप करने के दौरान त्वचा के रोमछिद्रों को बंद कर देते हैं। इस से मेकअप त्वचा के अंदर नहीं जा पाता और पसीना या पानी उसे बहा नहीं पाता है। वाटरप्रूफ मेकअप की सब से खास बात यह होती है कि यह चाय, काफी आदि पीने से भी खराब नहीं होता है। इस तरह के मेकअप प्रोडक्ट्स से मेकअप करते समय त्वचा को वाटरप्रूफ करने की जरुरत नहीं रहती है। वाटरप्रूफ मेकअप प्रोडक्ट्स में क्रीम, लिपस्टिक, फेस बेस, रूज, मस्कारा और काजल जैसी ढेर सारी चीजें अब बाजार में मिलने लगी हैं।

जरा सावधान रहें

वाटरप्रूफ मेकअप प्रोडक्ट्स सिलिकोन का प्रयोग कर के बनाए जाते हैं। इन में प्रयोग होने वाला डाइनोथिकोन आयल त्वचा को चमकदार बनाता है। यह वाटरप्रूफ मेकअप को आसानी से फैलने में मदद करता है, लेकिन वाटरप्रूफ के जहां तमाम फायदे हैं, वहीं इस के साथ कुछ खराबियां भी हैं, जिन्हें जान लेना जरूरी होता है। वाटरप्रूफ मेकअप को हटाने के लिए पानी का प्रयोग ही काफी नहीं होता है। इस को हटाने के लिए बेबी आयल या फिर सिलिकोन आयल का प्रयोग करना होता है। वाटरप्रूफ मेकअप का प्रयोग त्वचा पर खराब प्रभाव डालता है। इस से त्वचा को नुकसान पहुंचता है। त्वचा पर इन्फैक्शन हो जाता है। ज्यादा प्रयोग करने से समय से पहले त्वचा पर झुर्रियां भी पड़ने लगती हैं। वाटरप्रूफ मेकअप का प्रयोग खास अवसरों पर ही करें, रोज इस का प्रयोग न करें।

डेली मेकअप

बारिश के दिनों में फाउंडेशन का इस्तेमाल करना सुरक्षित नहीं होता है। कॉम्पैक्ट पाउडर के जरीए मैट लुक सब से बेहतर विकल्प है। फाउंडेशन की जगह फेस पाउडर का इस्तेमाल करें। कॉम्पैक्ट के साथ हलका मेकअप करें। इस से पूरा फेस भी कवर हो जाएगा और वह तैलीय भी नहीं दिखेगा। लाइलैक ब्लौसम और प्रीसियस पिंक कलर के परिधान के साथ सौफ्ट पिंक और डीप रास्पबैरी लिपस्टिक बेहतर रहेगी। काजल के इस्तेमाल से आंखों को खूबसूरत बनाएं। लाइलैक ब्लौसम और प्रीसियस पिंक कलर के परिधान के साथ सौफ्ट पिंक और डीप रास्पबैरी लिपस्टिक बेहतर रहती है। अपनी आंखों को ऐटिटयूड काजल से हाईलाइट करें।

पार्टी मेकअप

मानसून सीजन के दौरान चेहरे को ब्लशर के हलके प्रयोग से निखारें। अगर आप भीग जाती हैं तो चेहरे को टिशू पेपर से सुखा लें। टिशू पेपर को पूरे चेहरे पर न मलें। गालों पर ब्लशर को बाहर की तरफ ब्लैंड करें। हलके रंगों का ज्यादा इस्तेमाल करें। क्रीम की जगह पाउडर्ड आईशैडो का प्रयोग करें। यह चेहरे पर आईशैडो को फैलने से रोकेगा। अगर आप मसकारे का इस्तेमाल करना चाहती हैं, तो वाटर रैसिस्टैंस मसकारे का इस्तेमाल करें ताकि भारी बारिश में भी वह सुरक्षित रहे। मानसून के दौरान लिक्विड आईलाइनर की जगह पैंसिल आईलाइनर का इस्तेमाल करें।

बालों का रखें ख्याल

मौसम में नमी के कारण पसीना ज्यादा बहता है जिस वजह से स्कैल्प तैलीय हो जाती है और बाल चिपचिपे हो जाते हैं। लगातार मौसम में नमी और शरीर से पसीना आने की वजह से सिर बिल्कुल चिपचिपी हो जाती है जिस वजह से सिर की त्वचा पर जीवाणु और फंगस अपना घर बना लेते हैं। पर्यावरण प्रदूषण भी हवा के द्वारा सिर और बालों पर चिपक जाते हैं जो कि पहले से ही चिकनापन लिए होते हैं।

हेयर केयर के लिए टिप्स

अपनी सिर को बिल्कुल सूखा रखने की कोशिश करें। मानसून में अपने बालों को हर रोज शैंपू करें क्योंकि इस समय पसीना ज्यादा बहता है। माइल्ड शैंपू का प्रयोग सही रहेगा। बालों के हिसाब से कंडीशनर चूज करें। ऑयली बालों के लिए लाइट कंडीशनर और सूखे बालों के लिए जरा सा स्ट्रांग कंडीशनर अच्छा होता है। अपने आप को हाइड्रेट रखने के लिए खूब सारा पानी पिएं और फलों का जूस। इस समय बालों का झड़ना आम बात है, तो ऐसे में बिल्कुल भी ना घबराएं।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

कांग्रेस ही बीजेपी और संघ से मुकाबला करने में सक्षम

नई दिल्ली। कांग्रेस नेतृत्व द्वारा बुलाई गई गुरुवार की बैठक का मकसद नीट, सीबीएसई, महंगाई, बेरोजगारी और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर मोदी सरकार के खिलाफ रणनीति बनाना था। इस बैठक की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें कांग्रेस के सभी महासचिव, राज्य प्रभारी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शामिल हुए। हालांकि, चर्चा के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की टिप्पणी मोदी ने मरवा दिया ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बनीं।मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में हुई बैठक में राहुल गांधी ने पीएम मोदी और उनकी नीतियों की कड़ी आलोचना की। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने कहा कि बेरोजगारी युवाओं को परेशान कर रही है, परीक्षा पेपर लीक होने से छात्र परेशान हैं, विदेश नीति में कमियों की वजह से महंगाई बढ़ रही है, जिससे आम और गरीब नागरिक परेशान हैं।

असम में आया 4.7 तीव्रता का भूकंप

गुवाहाटी। असम के कछार जिले में गुरुवार रात 4.7 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया, जिसके झटके मेघालय सहित पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में महसूस किए गए। हालांकि, राहत की बात यह रही कि भूकंप से किसी प्रकार के जान-माल के नुकसान या बड़े हादसे की कोई सूचना नहीं मिली है।

अधिकारियों के अनुसार भूकंप गुरुवार रात करीब 9ः10 बजे आया। इसका केंद्र असम के कछार जिले में स्थित था। भूकंप की गहराई जमीन से लगभग 39 किलोमीटर नीचे दर्ज की गई, जिससे इसके झटके आसपास के राज्यों तक महसूस किए गए। भूकंप विज्ञान केंद्र के आंकड़ों के अनुसार, भूकंप का केंद्र 24.941 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 93.007 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित था। झटके महसूस होते ही कई लोग एहतियातन अपने घरों और इमारतों से बाहर निकल आए। कुछ क्षेत्रों में लोगों के बीच थोड़ी देर के लिए दहशत का माहौल भी देखा गया।

शरद पवार की पार्टी से तीन विधायक हुए बागी

मुंबई। महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, कांग्रेस हाईकमान ने शरद पवार को अपनी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) का कांग्रेस में पूरी तरह से विलय करने का एक बड़ा प्रस्ताव दिया है। इस बड़े सियासी घटनाक्रम के बीच शरद पवार के नेतृत्व वाले गुट में आंतरिक कलह और फूट भी खुलकर सामने आ गई है, जिसने राज्य की राजनीति में हलचल तेज कर दी है। एक तरफ जहां विलय की चर्चाएं गर्म हैं, वहीं दूसरी तरफ शरद पवार गुट के तीन विधायकों—उत्तमराव जानकर, अभिजीत पाटिल और नारायण पाटिल—ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण से मुलाकात की है। माना जा रहा है कि टिकट वितरण से नाराज ये तीनों विधायक जल्द ही भाजपा में शामिल हो सकते हैं। यह मुलाकात सोलापुर में महायुति के नेताओं की एक बैठक के दौरान हुई।

इंडिगो फ्लाइट में बम लिखा टिशू पेपर मिला

लखनऊ। लखनऊ से दिल्ली जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट में शुक्रवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब उड़ान भरने से पहले विमान के टॉयलेट में बम लिखा हुआ एक टिश्यू पेपर मिला। लखनऊ से सुबह 11.15 बजे इंडिगो एयरलाइन के दिल्ली जाने वाले विमान 6ई2111 के टॉयलेट में किसी ने एक टिश्यू पेपर पर बम होने की सूचना लिखकर रख दी। इसके बाद विमान को एसटीसी से संपर्क के बाद टैक्सी वे एरिया में लाया गया।मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सीआईएसएफ समेत सभी सुरक्षा एजेंसियों ने यात्रियों और उनके सामान को उतार नीचे उतारा। विमान और सामान की तलाशी ली गई। सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत करीब 180 यात्रियों वाली इस फ्लाइट को एप्रन पर ही रोक दिया गया। सुरक्षा कर्मियों ने विमान की सघन तलाशी ली गई, जिसमें कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। जरुरी सुरक्षा और कानूनी प्रक्रियाओं के चलते विमान की उड़ान में देरी हुई।

पाक पीएफआई तंजीम मिशन से जुड़े गुर्गे को एटीएस ने दबोचा

भोपाल। केंद्रीय जांच एजेंसियों से मिले सुराग के बाद भोपाल आतंक निरोधी दस्ते ने हनुमानगंज स्थित काजीकैंप से एक युवक को हिरासत में लिया है। प्राथमिक विवेचना प्रस्तावित अफगानिस्तान यात्रा को लेकर की जा रही है। खबर है कि वह पाकिस्तान के इशारे पर एजेंट बना था। वह पाकिस्तान से संचालित पीएफआई तंजीम मिशन के लिए लड़ाकों के दल को बनाने की मुहिम में जुटा था। एटीएस भोपाल ने बताया कि आरोपी मोहम्मद फराज उर्फ खालिद सैफुल्लाह पिता मोहम्मद फिरोज उम्र 34 साल है। वह काजी कैंप में ही एक डॉक्टर की क्लीनिक में नौकरी करता है। वह कांग्रेस नगर बैरसिया रोड पर रहता है। आरोपी मोहम्मद फराज पाकिस्तान से संचालित एक व्हाट्स एप ग्रुप से जुड़ा था। इस काम में उसका सहयोग नईम अब्दुल्ला ने किया। वह उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित देवबंद के मदरसे से जुड़ा है। उसने ही पाकिस्तान के हैंडलर से मुलाकात कराई थी। एटीएस ने उसे भी आरोपी बनाया है। मोहम्मद फराज ने बताया कि उसे पाकिस्तान में बैठे हैंडलर ने पीएफआई तंजीम मिशन 2047 के लिए तैयार किया गया है। उसके जैसे अन्य लोगों को जोड़ने का भी काम चल रहा था।

19 सांसदों ने छोड़ी ममता बनर्जी की टीएमसी

असली पार्टी होने का ठोका दावा!

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने राजनीतिक करियर के सबसे भीषण अंतर्विरोध और संकट के दौर से गुजर रही हैं। विधानसभा चुनावों में मिली करारी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) का आंतरिक कलह अब पूरी तरह सड़क पर आ गया है। पार्टी के 28 लोकसभा सांसदों में से 19 सांसदों ने खुली बगावत कर दी है। इंडिया टुडे को बागी सांसदों के उस ग्रुप की सीक्रेट चिट्ठी की कॉपी मिली है, जो उन्होंने लोकसभा स्पीकर को सौंपी है। इन सांसदों ने खुद को असली तृणमूल कांग्रेस बताते हुए संसद में एक अलग गुट बनाने और पार्टी के चुनाव चिह्न पर दावा ठोकने का फैसला किया है। इस बगावत के बाद ममता बनर्जी के पाले में अब केवल 9 सांसद ही बचे हैं।

18 मई की तारीख वाली इस चिट्ठी पर 19 लोकसभा सांसदों के हस्ताक्षर हैं। इन सांसदों ने एक अलग संसदीय गुट बनाने का समर्थन किया है और अब टीएमसी के चुनाव चिह्न पर अपना दावा ठोक रहे हैं। उनका कहना है कि वे ही असली तृणमूल कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस घटनाक्रम के बाद पार्टी के 28 लोकसभा सांसदों में से केवल नौ ही बागी गुट से बाहर बचे हैं, हालांकि कुछ सदस्यों की स्थिति अभी भी साफ़ नहीं है।

हस्ताक्षर करने वालों में ये शामिल हैं- काकोली घोष दस्तीदार, शताब्दी रॉय, बापी हलदर, डॉ. शर्मिला सरकार, प्रसून बनर्जी, जगदीश बर्मा बसुनिया, असित कुमार मल, अरूप चक्रवर्ती, रचना बनर्जी, सायनी घोष, खलीलुर रहमान, अबू ताहिर खान, यूसुफ़ पठान, मिताली बाग, माला रॉय, कालीपदा सोरेन, दीपक अधिकारी, जून मालिया, पार्थ भौमिक।

सूत्रों ने बताया कि बागी सांसदों ने

स्पीकर को एक अलग संसदीय समूह के तौर पर काम करने के अपने इरादे के बारे में बता दिया है। बागी गुट का कहना है कि उनका भाजपा या एनडीए में शामिल होने का कोई इरादा नहीं है, बल्कि वे स्वतंत्र रूप से काम करेंगे और पश्चिम बंगाल के हितों के लिए काम करेंगे।

माना जा रहा है कि यह ग्रुप संसद में महिला आरक्षण बिल और परिसीमन बिल (डिलिमिटेशन बिल) को पास कराने की केंद्र सरकार की कोशिशों पर भी बारीकी से नज़र रख रहा है।

यह ताज़ा घटनाक्रम टीएमसी सांसदों के बीच बढ़ती नाराज़गी की खबरों के कुछ दिनों बाद सामने आया है। कई नेताओं ने पार्टी के कामकाज और राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के प्रभाव को लेकर असंतोष ज़ाहिर किया है। संसद में हुई बगावत से पहले पश्चिम बंगाल विधानसभा में भी ऐसी ही अभूतपूर्व बगावत हुई थी, जहाँ बड़ी संख्या में विधायकों ने पार्टी के विधायक दल से अलग होकर टीएमसी के 28 साल के इतिहास का सबसे बड़ा अंदरूनी संकट खड़ा कर दिया था।

इस चिट्ठी का समय भी स्पीकर के फ़ैसले में एक अहम भूमिका निभा सकता है। सूत्रों का कहना है कि बागी सांसदों की चिट्ठी पर 18 मई की तारीख़ है, जो वरिष्ठ सांसद कल्याण बनर्जी को 19 मई को लोकसभा में पार्टी का चीफ़ व्हिप नियुक्त किए जाने से एक दिन पहले की तारीख़ है। अब स्पीकर को यह तय करना होगा कि क्या बागी गुट को तकनीकी और प्रक्रियात्मक आधार पर मान्यता दी जा सकती है या नहीं।

इस बगावत ने पार्टी पर नियंत्रण को लेकर एक लंबी कानूनी और राजनीतिक लड़ाई की संभावना भी पैदा कर दी है। उम्मीद है कि बागी गुट चुनाव आयोग के सामने टीएमसी के चुनाव चिह्न पर अपना दावा पेश करेगा और तर्क देगा कि वही पार्टी की संसदीय ताकत के बहुमत का प्रतिनिधित्व करता है। चुनाव आयोग के किसी भी फ़ैसले को हारने वाला पक्ष चुनौती दे सकता है, जिससे यह विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच सकता है।

बागी गुट से सार्वजनिक रूप से दूरी बनाने वालों में वरिष्ठ सांसद शत्रुघ्न सिन्हा भी शामिल हैं; उन्होंने ममता बनर्जी के प्रति अपनी निष्ठा दोहराई और बागी गुट का समर्थन करने वाली किसी भी चिट्ठी पर हस्ताक्षर करने से इनकार किया।

अभिषेक बनर्जी, सौगत राय, महुआ मोइत्रा, कल्याण बनर्जी, कीर्ति आज़ाद, प्रतिमा मंडल, साजिदा अहमद और सुदीप बंद्योपाध्याय के साथ-साथ वे भी उन सांसदों में शामिल हैं जो अभी बागी गुट से नहीं जुड़े हैं।

टीएमसी के संसदीय विंग के औपचारिक रूप से बंटने की संभावना के बीच, अब सबकी नज़रें स्पीकर के कार्यालय और चुनाव आयोग पर होंगी, जिनके फ़ैसले भारत की सबसे प्रभावशाली क्षेत्रीय पार्टियों में से एक का भविष्य तय कर सकते हैं।

महुआ मोइत्रा ने 19 बागी सांसदों पर साधा निशाना

पहले इस्तीफा दें फिर भाजपा के टिकट पर लड़ें चुनाव

नई दिल्ली। शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस पर कंट्रोल की लड़ाई और तेज़ हो गई। पार्टी की सांसद महुआ मोइत्रा ने बागी सांसदों पर तीखा हमला किया, जबकि बागी सांसदों ने खुले तौर पर भाजपा के नेतृत्व वाले नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (एनडीए) के साथ नज़दीकी रिश्ते बनाने का समर्थन किया और संसद में अपनी अलग पहचान बनाने की योजना पर आगे बढ़े। यह टकराव तृणमूल कांग्रेस के अंदर बढ़ते संकट के बीच हो रहा है, जो हाल ही में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद पैदा हुआ है। बागी सांसदों के एक गुट ने लोकसभा में बैठने के लिए अलग व्यवस्था की मांग की है, वहीं पार्टी से अलग हुए वरिष्ठ नेताओं ने नेतृत्व के कामकाज और भविष्य की दिशा पर खुलेआम सवाल उठाए हैं।

एक्स पर एक पोस्ट में मोइत्रा ने तर्क दिया कि बागी नेता संवैधानिक प्रावधानों को गलत समझ रहे हैं और वे एक अलग संसदीय गुट के तौर पर मान्यता का दावा नहीं कर सकते। उन्होंने लिखा कि टीएमसी के गद्दार सांसदों को कानून की जानकारी नहीं है। संविधान के 91वें संशोधन (2003) में अलग गुट बनाने का प्रावधान खत्म कर दिया गया था। सांसदों की संख्या मायने नहीं रखती। मूल राजनीतिक पार्टी के दो-तिहाई सदस्यों को किसी दूसरी पार्टी में विलय करना होता है। सभी 19 गद्दारों को इस्तीफा देकर भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ना होगा।

कृष्णानगर की सांसद ने अपनी एक

पुरानी पोस्ट का भी ज़िक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर बागी सांसद टीएमसी के दो-तिहाई सांसदों का समर्थन हासिल भी कर लेते हैं, तो भी वे अपने-आप एक स्वतंत्र संसदीय समूह के तौर पर काम करने के हकदार नहीं हो जाएंगे। मोइत्रा के अनुसार, ऐसा कोई भी कदम उठाने पर दल-बदल विरोधी कानून के तहत विलय से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों का पालन करना होगा। उन्होंने अपनी बात के समर्थन में सुभाष देसाई बनाम महाराष्ट्र के राज्यपाल के प्रधान सचिव मामले में सुप्रीम कोर्ट के 2023 के फ़ैसले का भी हवाला दिया।

पार्टी लीडरशिप ने बागी गुट की बात को खारिज कर दिया है, लेकिन बागी गुट के सदस्य अभी भी पूरे भरोसे के साथ अपनी बात कह रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए, बागी सांसद अरूप चक्रवर्ती ने दावा किया कि संसद में अलग बैठने की गुट की मांग का करीब 20 सांसद समर्थन कर रहे हैं। चक्रवर्ती ने कहा कि हमें 20 सांसदों का समर्थन हासिल है। इस आरोप को खारिज करते हुए कि बागी नेता राजनीतिक फायदे के लिए ऐसा कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि यह गुट टीएमसी को बचाना और उसे नए रूप में फिर से खड़ा करना चाहता है।

सुवेंदु अधिकारी ने गिनाईं भाजपा सरकार की उपलब्धियां

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के नेता सुवेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को डबल-इंजन गवर्नेंस मॉडल के ज़रिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार से राज्य के लोगों को मिले फ़ायदों पर ज़ोर दिया। कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, अधिकारी ने पीएम मोदी के नेतृत्व में लागू की गई विभिन्न विकास परियोजनाओं, कल्याणकारी योजनाओं और राष्ट्रीय सुरक्षा पहलों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि हम मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से काम करेंगे; इतने कम समय में भी हमने कुछ काम पूरे कर लिए हैं। जनता को 'डबल-इंजन' सरकार के फ़ायदे दिखने लगे हैं और आने वाले दिनों में ये फ़ायदे और भी साफ़ तौर पर दिखाई देंगे।

राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में अधिकारी ने कहा कि हमने बीएसएफ को ज़मीन सौंप दी है। यह प्रक्रिया रोज़ चल रही है; अब तक हमने लगभग 100 किलोमीटर तक की ज़मीन सौंप दी है। उत्तर बंगाल में, खासकर चिकन्स नेक कॉरिडोर से सटे इलाकों में, बीएसएफ ने बाड़ लगाने का काम शुरू कर दिया है। जैसा कि आपने देखा है, हम इसे तय समय में पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं; आखिरकार, यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। उन्होंने राज्य में पहले से रुके हुए कामों, जैसे कि जनगणना की प्रक्रिया, को लागू करने का भी ज़िक्र किया। अधिकारी ने कहा कि जल जीवन मिशन के लिए 39,000 करोड़ रुपये का समझौता हुआ है और आयुष्मान भारत के लिए समझौता दिल्ली में फ़ाइनल किया गया; आयुष्मान भारत कार्ड पाने के लिए 1.43 करोड़ परिवारों की पहचान की गई है। हमने प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना भी अपनाई है, जिससे कम आय वाले परिवारों का हर महीने का बिजली का खर्च खत्म हो जाएगा।

इस कार्यक्रम के व्यापक महत्व पर ज़ोर देते हुए उन्होंने कहा कि यह प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे देश में, राष्ट्रीय स्तर पर और हर राज्य में हो रही है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य मकसद और एजेंडा दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी की उपलब्धियों को उजागर करना है, जिन्होंने पिछले बारह वर्षों में किए गए बड़े कामों के ज़रिए सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का नया रिकॉर्ड बनाया है। मुख्यमंत्री ने पश्चिम बंगाल में दी जा रही कल्याणकारी सुविधाओं के आंकड़े भी बताए। उन्होंने कहा कि इसके अलावा, 54 लाख किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा सीधे उनके खातों में मिल रहा है।

खेल
प्रमुख समाचार

अफगानिस्तान के खिलाफ कई नए चेहरों को मिलेगा मौका

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम अफगानिस्तान के खिलाफ शनिवार से यहां शुरू होने वाली तीन मैच की एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला से अगले साल होने वाले विश्व कप की तैयारी शुरू करेगी। इस श्रृंखला में जहां रोहित शर्मा की मैच फिटनेस की परीक्षा होगी, वहीं चोटिल हार्दिक पंड्या के बैकअप के रूप में नीतीश कुमार रेड्डी के प्रदर्शन पर भी कड़ी नजर रहेगी। आईपीएल के दौरान मांसपेशियों में खिंचाव के कारण कुछ मैच नहीं खेल पाने वाले रोहित अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की श्रृंखला के लिए समय रहते पूरी तरह से फिट हो गए हैं, लेकिन भारतीय टीम और दर्शकों को विराट कोहली की कमी खलेगी जो मांसपेशियों में खिंचाव के कारण इस श्रृंखला से बाहर हो गए हैं।

विश्व कप से पहले भारत को लगभग 25 वनडे मैच खेलने हैं, जिससे टीम को खिलाड़ियों और अलग-अलग संयोजन आजमाने का पर्याप्त मौका मिलेगा। शुभमन गिल की कप्तानी में भारत ने तीन वनडे श्रृंखला खेली हैं जिनमें से दो में उसे हार का सामना करना पड़ा था। मुख्य कोच गौतम गंभीर के साथ मिलकर वह इस रिकॉर्ड में सुधार करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहेंगे। गिल और रोहित के पारी की शुरुआत करने की उम्मीद है, जबकि कोहली की अनुपस्थिति में तीसरे नंबर पर ईशान किशन और यशस्वी जायसवाल में से किसी एक को उतारा जा सकता है। टी20 कि भारतीय टीम के नवनियुक्त कप्तान श्रेयस अय्यर चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे। टीम के नंबर एक विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल मध्य क्रम का हिस्सा हैं और नीतीश कुमार रेड्डी संभवत: उनके बाद छठे नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे। रेड्डी की बल्लेबाजी क्षमता पर कभी संदेह नहीं रहा है, लेकिन हार्दिक के बैक-अप के रूप में क्या वह गेंदबाजी में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, यह देखना बाकी है।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 1695 अंक चढ़ा निफ्टी 23600 के पार पहुंचा

नई दिल्ली। शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल देखा गया और निवेशकों के लिए यह कारोबारी हफ्ता एक बड़ी खुशखबरी के साथ खत्म हुआ। सेंसेक्स और निफ्टी में लगभग दो फीसदी से ज्यादा की छलांग ने बाजार के सेंटीमेंट को पूरी तरह से जोखिम लेने के लिए तैयार कर दिया है। शुक्रवार के कारोबारी सत्र के अंत में, बीएसई सेंसेक्स ने 1,695.40 अंकों (2.29%) की लंबी छलांग लगाई और यह 75,527.95 के ऐतिहासिक स्तर पर बंद हुआ। इसी तरह, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 461.31 अंक (1.99%) उछलकर 23,622.90 के पार जाकर बंद हुआ। मार्केट में चौतरफा खरीदारी (ब्रॉड-बेस्ड बाइंग) देखने को मिली। इंडेक्स में श्रीराम फाइनेंस के शेयर 8% तक उछले, जबकि लार्सन एंड टुब्रो (एलएंडटी) में 5% की तगड़ी तेजी दर्ज की गई।

15 जून को लिस्ट होंगी 4 नई कंपनियां

नई दिल्ली। वेदांता समूह के डिमर्जर के बाद बनी चार नई कंपनियों के शेयर सोमवार 15 जून से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर कारोबार के लिए उपलब्ध होंगे। सूत्रों के अनुसार, यह वेदांता के पुनर्गठन की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है। पहले से सूचीबद्ध वेदांता लिमिटेड के अलावा अब वेदांता एल्युमिनियम मेटल लिमिटेड, वेदांता ऑयल एंड गैस लिमिटेड, वेदांता पावर लिमिटेड और वेदांता आयरन एंड स्टील लिमिटेड के शेयर भी निवेशकों के लिए उपलब्ध होंगे। वेदांता के डिमर्जर प्रस्ताव को पिछले वर्ष दिसंबर में राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण की मंजूरी मिली थी। मंजूर 1:1 डिमर्जर योजना के तहत वेदांता लिमिटेड के प्रत्येक एक शेयर के बदले निवेशकों को नई चारों कंपनियों का एक-एक शेयर आवंटित किया गया है।

डेटा सेंटर क्षेत्र में 280 अरब डॉलर के अवसर की संभावना

नई दिल्ली। कृत्रिम मेधा (एआई) के बढ़ते उपयोग और तेजी से हो रहे डिजिटल बदलाव के बल पर भारत की डेटा सेंटर मूल्य श्रृंखला के साल 2035 तक 280 अरब अमेरिकी डॉलर की संभावित ऑर्डर बुक हासिल करने की उम्मीद है। परामर्श कंपनी पीडब्ल्यूसी ने यह जानकारी दी। पीडब्ल्यूसी की भारतीय इकाई पीडब्ल्यूसी इंडिया के अनुसार, डेटा सेंटर सुविधाओं के मूल ढांचे के निर्माण में वर्ष 2035 तक लगभग 71.6 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष निवेश होने का अनुमान है, जबकि इससे जुड़े व्यापक परिवेश में इससे कहीं अधिक अवसर उपलब्ध होंगे। पीडब्ल्यूसी इंडिया ने कहा कि 280 अरब डॉलर के संभावित ऑर्डर अवसर का बड़ा हिस्सा सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों से जुड़े क्षेत्र में होगा। चिप, सर्वर और नेटवर्किंग प्रणालियों जैसे उपकरण कुल पूंजीगत व्यय का 65-75 प्रतिशत हिस्सा होंगे, जिनका अनुमानित मूल्य 180-210 अरब डॉलर है।

मस्क दुनिया के पहले ट्रिलेनियर बनने के करीब

वाशिंगटन। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क जल्द ही नया इतिहास रच सकते हैं। स्पेसएक्स के रिकॉर्डतोड़ आईपीओ के बाद मस्क की कुल संपत्ति 1 ट्रिलियन डॉलर के स्तर को पार करने के बेहद करीब है। इसके साथ ही मस्क दुनिया के पहले ट्रिलेनियर बन जाएंगे। स्पेसएक्स ने अपने आईपीओ में 555.6 मिलियन शेयर 135 डॉलर प्रति शेयर की कीमत पर बेचे, जिससे कंपनी का कुल मूल्यांकन लगभग 1.77 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। कंपनी ने इस ऑफरिंग के जरिए करीब 75 अरब डॉलर जुटाए हैं। यह लिस्टिंग 12 जून को नैस्डैक पर स्पेसएक्स टिकर के तहत शुरू होने की उम्मीद है। रॉयटर्स और फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार, इस आईपीओ से पहले मस्क की संपत्ति करीब 780 अरब डॉलर आंकी थी।

कमजोर मानसून, महंगा तेल और बढ़ती आर्थिक चिंता

जयंतीलाल भंडारी

कमजोर मानसून और कच्चे तेल की महंगाई की दोहरी मार से अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीतिजनित मंदी की चुनौती बढ़ गई है। अमेरिका ने ईरान पर नए सिरे से हमले तेज कर दिए हैं, जिससे वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने लगी हैं। हाल ही में विश्व मौसम विभाग ने कहा है कि इस वर्ष 2026 में भारत अल नीनो से अत्यधिक प्रभावित होगा। इससे भारत में कमजोर मानसून और सूखे की स्थिति कृषि, जल आपूर्ति और महंगाई के लिए चुनौतियां पैदा करेंगी। एशियाई विकास बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक, इस वर्ष 2026-27 में भारत में महंगाई 6.9 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच सकती है।

पेट्रोल, डीजल और गैस के महंगे होने का सबसे बड़ा असर आम आदमी की जेब पर पड़ने लगा है। खासतौर से खाड़ी देशों से आयातित कच्चे माल से बने उत्पादों की कीमतें सबसे ज्यादा बढ़ी हैं। आम आदमी के जीवन से जुड़ी वस्तुएं, कपड़े और घरेलू उपकरण आदि भी महंगे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस समय दैनिक जरूरतों का सामान बनाने वाली कई फास्ट-मूविंग कंज्यूमर गुड्स (एफएमसीजी) कंपनियां अपने उत्पादों की कीमत बढ़ाने या पैकेट के वजन घटाने के विकल्पों पर विचार कर रही हैं। ऐसे में एक ओर कमजोर मानसून और सूखे से निर्मित होने वाली चिंताओं पर ध्यान देना होगा, वहीं कच्चे तेल की ऊंची कीमतों से निर्मित महंगाई की चिंताओं पर भी ध्यान देना होगा।

किसानों को इस बड़े मौसमी संकट से बचाने के लिए सरकार ने एक जून से देशव्यापी %खेत बचाओ% अभियान के तहत रणनीतिपूर्वक कदम आगे बढ़ाए हैं। इसके तहत किसानों को उनके इलाके और फसल

के हिसाब से खास सलाह दी जा रही है, ताकि वे मौसम के जोखिमों को समझकर सही फसल लगाएं। किसानों को मौसम, मिट्टी और बाजार की मांग के हिसाब से कृषि उत्पादन संबंधी व्यावहारिक मार्गदर्शन भी दिया जा रहा है। सरकार ने एक व्यापक और सहयोगी ढांचा तैयार किया है, जिसमें पंचायतों, राज्य सरकारों, कृषि विज्ञान केंद्रों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों और स्थानीय कृषि विभागों को एक साथ जोड़ा गया है। नए कृषि मार्गदर्शन की पहुंच मजबूत करने के लिए 1,600 से ज्यादा विशेष टीमें बनाई गई हैं। ये टीमें किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड और पीएम-किसान जैसी योजनाओं का लाभ दिलाने में मदद भी करेंगी।

हालांकि वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ने से सरकार के नीतिगत हस्तक्षेप की गुंजाइश सीमित है, इसलिए सरकार के साथ-साथ उद्योग-कारोबार और हर वर्ग के लोगों को महंगाई का मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ना होगा। लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर अमल करना चाहिए, जिसमें किफायत बरतने की जरूरत बताई गई है। सरकार ने हाल ही में पेट्रोल में एथेनॉल का मिश्रण 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 85 प्रतिशत तक किए जाने का निर्णय लिया है, जिससे पेट्रोल की कीमत में प्रति लीटर 20 रुपये तक की कमी आएगी। सरकार को तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देना चाहिए। एथेनॉल और इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल से जहां आम आदमी सस्ता और प्रदूषण-मुक्त सफर कर सकेंगे, वहीं कच्चे तेल का आयात कम होने से देश का पैसा बचेगा और किसानों की कमाई भी बढ़ेगी। सरकार ने एथेनॉल मिले पेट्रोल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी खत्म कर दी है। उम्मीद करें कि सरकार भविष्य में नवीकरणीय ऊर्जा को पेट्रोल-डीजल का विकल्प बनाने जैसे दीर्घकालीन उपायों के साथ रणनीतिपूर्वक आगे बढ़ेगी।

विकसित भारत संकल्प सम्मेलन : केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पीएम मोदी के कार्यकाल की गिनाई उपलब्धियां

12 वर्षों में देश ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ

रायपुर। भाजपा रायपुर जिला अध्यक्ष रमेश ठाकुर के नेतृत्व में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन का आयोजन राजधानी रायपुर के शांतिनगर स्थित विमतारा भवन में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह उपस्थित रहे।

कार्यक्रम में रायपुर लोकसभा सांसद बृजमोहन अग्रवाल, प्रदेश महामंत्री अखिलेश सोनी, पश्चिम विधायक राजेश मूणत, उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा, रायपुर ग्रामीण विधायक मोतीलाल साहू, भाजपा रायपुर जिला प्रभारी राजेंद्र शर्मा, महापौर मीनल चौबे, नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव, प्रदेश उपाध्यक्ष नंदन जैन, प्रदेश मंत्री जयंती पटेल एवं अमित साहू सहित अनेक जनप्रतिनिधियों ने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके बाद वंदे मातरम् एवं छत्तीसगढ़ राजगीत के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई।

जिला अध्यक्ष रमेश ठाकुर ने मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि आज हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि हमारे छत्तीसगढ़ की पावन धरती पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विकसित भारत संकल्प सम्मेलन के लिए अपना महत्वपूर्ण समय दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 में लोकसभा सदन में जो संकल्प व्यक्त किया था, उसे आज लगातार पूरा किया जा रहा है।

अखिलेश सोनी ने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ष 2014 में संसद पहुंचे थे, तब उन्होंने संसद की सीढ़ियों को प्रणाम करते हुए कहा था कि यह सरकार जनता की सरकार होगी और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का कार्य करेगी। आज विकसित भारत की दिशा में गरीबों को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज और 80 करोड़ लोगों

को मुफ्त राशन जैसी योजनाओं का लाभ मोदी सरकार द्वारा दिया जा रहा है।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने सभी मंचासीन अतिथियों का स्वागत किया। उन्होंने उपस्थित पूर्व सैनिकों को नमन करते हुए कहा कि पीएम मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल में ऐसा कोई वर्ग नहीं है, जिसकी चिंता सरकार ने न की हो। उन्होंने छत्तीसगढ़ के निर्माता अटल बिहारी वाजपेयी को धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्हीं के कारण आज छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में है और आज पीएम मोदी की सरकार के नेतृत्व में प्रदेश लगातार विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा शिक्षा संस्थानों का विस्तार किया गया है। रायपुर से विशाखापट्टनम तक 6 लेन सड़क का निर्माण हुआ है। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि देश में इतना व्यापक और चौमुखी विकास होगा। पहले की सरकार प्रदेश को सालाना लगभग 3 हजार करोड़ रुपये देती थी, जबकि आज मोदी सरकार ने एक वर्ष में ही 40 हजार करोड़ रुपये की सौगात दी है।

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में पहले 10 हजार स्कूल थे, जबकि आज उनकी संख्या 60 हजार तक पहुंच गई है। पूरे देश में सबसे अधिक प्रधानमंत्री आवास छत्तीसगढ़ में स्वीकृत किए गए हैं। गरीब व्यक्ति ने कभी नहीं सोचा था कि उसका स्वयं का बैंक खाता होगा, जिसमें सीधे सरकारी योजनाओं का पैसा पहुंचेगा। पहले मोहल्ले में 5 लाख रुपये का काम होने पर भी लोग बैंड-बाजा लेकर आ जाते थे, जबकि आज मोहल्लों में करोड़ों रुपये के विकास कार्य हो रहे हैं।

मुख्य अतिथि भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि हमारे मित्र बृजमोहन अग्रवाल और हम दोनों पुराने युवा मोर्चा के साथी हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ महतारी को नमन करते हुए कहा कि आज 12 जून को हम यहां खड़े हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्रियों में शामिल हो चुके हैं।

उन्होंने कहा कि पीएम मोदी निरंतर देश की सेवा कर रहे हैं। जब पत्रकार मुझसे पूछते हैं तो मैं कहता हूं कि यूपीए सरकार 10 वर्षों तक विवादों में घिरी रही, जबकि मोदी उम्मीदों से घिरे हुए हैं। मैं बिहार से आता हूं। गांवों में पहले कितने पक्के घर थे, कितनों के पास दोपहिया या चारपहिया वाहन थे, यह सभी जानते हैं। लेकिन पिछले 12 वर्षों में देश में व्यापक परिवर्तन आया है। जहां सड़कें नहीं थीं, वहां आज चौड़ी और आधुनिक सड़कें हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ नए घरों का निर्माण भी किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि रोडवेज, एयरवेज और वाटरवेज सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास हुआ है। रेलवे में जितना विकास इन वर्षों में हुआ है, उतना पिछले 70 वर्षों में नहीं हुआ। देश में एयरपोर्ट की संख्या 74 से बढ़कर 164 हो गई है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। भारत की जीडीपी 4 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी है और विदेशी मुद्रा भंडार 300 बिलियन डॉलर से बढ़कर 683 बिलियन डॉलर हो गया है।

उन्होंने कहा कि पहले गैस सिलेंडर के लिए लंबी लाइनें लगानी पड़ती थीं, जबकि आज गांव-गांव तक गैस कनेक्शन पहुंच चुका है।

फिल्में समाज को संदेश देने का सशक्त माध्यमः राज्यपाल डेका

रायपुर। फिल्में और डॉक्युमेंट्री केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं हैं, बल्कि समाज को जागरूक करने और सकारात्मक संदेश देने का एक प्रभावी साधन हैं। राज्यपाल रमेन डेका ने आज राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता डॉक्यूमेंट्री फिल्मों के सम्मान समारोह में उक्त बातें कही। यह कार्यक्रम रायपुर के एक निजी होटल में छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम और संस्कृति विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया था।

राज्यपाल ने कहा कि आदिम युग से ही मनुष्य विभिन्न माध्यमों से अपने विचार और संदेश व्यक्त करता रहा है। समय के साथ नाटक, रेडियो, टेलीविजन और अब डिजिटल माध्यमों ने इस भूमिका को और व्यापक बनाया है। उन्होंने कहा कि पहले सिनेमा का मूल उद्देश्य केवल धन अर्जित करना नहीं था, बल्कि समाज को संदेश देना और जागरूक करना था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भी भारतीय सिनेमा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

राज्यपाल ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से बस्तर में नक्सलवाद के विरुद्ध उल्लेखनीय सफलता मिली है। फिल्म निर्माताओं को चाहिए कि अब वे बस्तर की समृद्ध संस्कृति से देश और दुनिया को परिचित कराएं। इससे क्षेत्र की सकारात्मक छवि को मजबूती मिलेगी। राज्यपाल ने सद्गति, चरणदास चोर और देवदास जैसी फिल्मों और नाटकों का उल्लेख करते हुए कहा कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन और जागरूकता लाने वाली फिल्मों की आज भी उतनी ही आवश्यकता है। राज्यपाल ने कहा की लोककलाओं, लोकगीतों, जनजातीय परंपराओं और पर्व-त्योहारों जैसे हमारे धरोहर को स्थायी रूप से संरक्षित करने का महत्वपूर्ण माध्यम डॉक्यूमेंट्री फिल्में हैं। उन्होंने कलाकारों से लोककला, लोकगीत, जनजातीय परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया।

राज्यपाल ने कहा कि मोबाइल की बढ़ती लत आज गंभीर सामाजिक समस्या बनती जा रही है। बच्चे खेल के मैदानों से दूर हो रहे हैं और उनकी रचनात्मकता प्रभावित हो रही है। उन्होंने कलाकारों से आग्रह किया।

अंडर-19 भारतीय महिला टीम की उपकप्तान बनीं महक नरवासे

रायपुर। राजनांदगांव जिले की होनहार क्रिकेटर महक नरवासे को भारतीय अंडर-19 महिला क्रिकेट टीम के टी-20 और वनडे दोनों में उपकप्तान नियुक्त किए जाने पर राजनांदगांव कलेक्टर जितेंद्र यादव और वनमंडलाधिकारी श्री आयुष जैन ने बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। अधिकारियों ने कहा कि महक ने अपनी प्रतिभा, कड़ी मेहनत और खेल के प्रति समर्पण के बल पर जिले, प्रदेश और देश का नाम रोशन किया है। कलेक्टर श्री यादव ने कहा कि महक की यह उपलब्धि जिले के युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने विश्वास जताया कि महक भविष्य में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगी।उल्लेखनीय है कि भारत और श्रीलंका के बीच अंडर-19 महिला टी-20 श्रृंखला 22 जून से शुरू होगी, जिसके बाद वनडे मुकाबले खेले जाएंगे। महक नरवासे दोनों प्रारूपों में भारतीय टीम की उपकप्तान के रूप में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाते हुए मैदान पर नजर आएंगी।

छत्तीसगढ़ जनहितैषी योजनाओं के लोन प्रकरणों को जल्द स्वीकृत करें बैंकर्स

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार की जनकल्याणकारी और स्वरोजगार योजनाओं का लाभ हितग्राहियों तक तेजी से पहुंचाने के लिए शासन ने कड़ा रुख अपनाया है। मंत्रालय महानदी भवन (नवा रायपुर) में वित्त विभाग की विशेष सचिव श्रीमती शीतल शाश्वत वर्मा की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय बैंकर्स उप समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए गए कि जनहित की योजनाओं से जुड़े ऋण (लोन) और अनुदान (सब्सिडी) के मामलों को बैंकर्स बिना किसी देरी के जल्द से जल्द स्वीकृत करें।

बैठक में मुख्य रूप से महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने के लिए महिला स्व-सहायता समूहों के बैंक लिंकेज को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। इसके अलावा, विभिन्न केंद्रीय व राज्य स्तरीय योजनाओं के तहत 31 मार्च तक बैंकों द्वारा दिए गए लोन और वित्तीय सहायता के मामलों की समीक्षा की गई, जिनमें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, पीएम स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, अंत्योदय स्वरोजगार योजना सहित अन्य योजनाओं के 31 मार्च तक के हितग्राहियों को बैंकों द्वारा प्रदत्त लोन एवं अन्य वित्तीय सहायता के प्रकरणों की स्थिति की विस्तार से समीक्षा की गई। विशेष सचिव श्रीमती शीतल शाश्वत वर्मा ने बैंक प्रतिनिधियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत आने वाले हितग्राहियों के आवेदनों को बेवजह लंबित न रखा जाए। फाइलों के त्वरित निपटारे के लिए उन्होंने बैंकर्स को एक व्यावहारिक व्यवस्था बनाने को कहा है।

बैंकर्स से कहा गया है कि वे स्वरोजगार और अन्य योजनाओं के हितग्राहियों के ऋण प्रकरणों के निराकरण के लिए प्रति सप्ताह एक निर्धारित दिन (फिक्स डे) तय करें, ताकि उसी दिन सभी आवेदनों की जांच कर उनका तत्काल निपटारा किया जा सके।

छत्तीसगढ़/राजधानी
प्रमुख समाचार

छत्तीसगढ़ को मिला पहला संभागीय पोर्टल

छरायपुर। डिजिटल सुशासन की दिशा में छत्तीसगढ़ ने एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। सरगुजा संभाग अब राज्य का पहला ऐसा संभाग बन गया है, जिसकी अपनी आधिकारिक वेबसाइट शुरू हो गई है। संभागायुक्त नरेंद्र कुमार दुग्गा ने शुक्रवार को https://division-surguja.cg.gov.in/ पोर्टल का शुभारंभ किया। यह पोर्टल नागरिकों, पर्यटकों और विभिन्न हितधारकों को एकीकृत डिजिटल मंच उपलब्ध कराएगा।राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) सरगुजा द्वारा विकसित यह वेबसाइट केंद्र सरकार के सुरक्षित SxWaaS प्लेटफॉर्म पर तैयार की गई है। आधुनिक तकनीक से लैस पोर्टल 'सिक्योर बाय डिजाइन' फ्रेमवर्क पर आधारित है तथा इसकी होस्टिंग एनआईसी के नेशनल डाटा सेंटर में की गई है। वेबसाइट हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है तथा मोबाइल, टैबलेट और कंप्यूटर पर सहजता से संचालित होगी।पोर्टल के माध्यम से नागरिक सरगुजा संभाग की प्रशासनिक संरचना, इतिहास, अधिकारियों की संपर्क सूची और सभी जिलों की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

पद्म पुरस्कारों के लिए आवेदन शुरू, 31 जुलाई तक भेजे जा सकेंगे नामांकन

रायपुर। देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने वर्ष 2027 के लिए पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कारों हेतु 31 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन नामांकन आमंत्रित किए हैं।प्राप्त जानकारी के अनुसार, इच्छुक व्यक्ति और संस्थाएं निर्धारित प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन पोर्टल पर योग्य एवं पात्र व्यक्तियों के नाम प्रस्तावित कर सकते हैं। नामांकन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। सामान्य प्रशासन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन ने भी सभी संबंधित विभागों, संस्थाओं और नागरिकों से ऐसे व्यक्तियों के नाम प्रस्तावित करने का आग्रह किया है, जिन्होंने कला, साहित्य, शिक्षा, चिकित्सा, विज्ञान, सामाजिक सेवा, खेल, लोक प्रशासन या अन्य क्षेत्रों में उल्लेखनीय और विशिष्ट योगदान दिया हो। नामांकन प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता एवं मापदंडों के अनुरूप तैयार कर निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रस्तुत करना होगा। इच्छुक आवेदक और संस्थाएं पद्म पुरस्कारों से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश तथा ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया की जानकारी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल,https://awards.gov.in/ का अवलोकन कर सकते हैं। पद्म पुरस्कार देश के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मानों में शामिल है।

कुष्ठ रोग पर दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित

रायपुर। राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत कुष्ठ रोग के संक्रमण को पूर्णत: समाप्त करने तथा जीरो ट्रांसमिशन के राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नया रायपुर में 02 दिवसीय क्षेत्रीय समीक्षा एवं रणनीतिक कार्ययोजना हेतु कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव एवं मिशन संचालक आराधना पटनायक, सचिव स्वास्थ्य, छत्तीसगढ़ अमित कटारिया, आयुक्त सह संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं सह मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़ संजीव कुमार झा, संयुक्त सचिव भारत सरकार निखिल गजराज, कुष्ठ रोग प्रकोष्ठ के उप महानिदेशक डॉ. सुनील वी. गिट्टे सहित महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और मध्यप्रदेश के मिशन संचालक, राज्य कुष्ठ अधिकारी व क्षेत्रीय निदेशक उपस्थित रहे। विशेषज्ञों ने कुष्ठ रोग के संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने, समय पर पहचान सुनिश्चित करने तथा रोग से होने वाली विकलांगता को समाप्त करने के लिए केंद्रित प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया।

खेत बचाओ अभियान' से खेती को मिलेगा नया बल

रायपुर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार 1 जून से 30 जून 2026 तक देशव्यापी 'खेत बचाओ अभियान' संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में कोरिया जिले में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और किसानों को जागरूक करने के लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। जिले के कृषि अधिकारियों एवं ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों द्वारा गांव-गांव पहुंचकर किसानों को प्रशिक्षण, संवाद और खेत प्रदर्शन के माध्यम से जानकारी दी जा रही है। अभियान के तहत किसानों को प्राकृतिक खेती के लाभ, मृदा स्वास्थ्य संरक्षण तथा रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग के प्रति जागरूक किया जा रहा है। अधिकारियों द्वारा बताया जा रहा है कि प्राकृतिक खेती से न केवल उत्पादन लागत कम होती है, बल्कि भूमि की उर्वरता और जैव विविधता भी सुरक्षित रहती है।किसानों को यूरिया-डीएपी के विवेकपूर्ण उपयोग के साथ-साथ एनपीके, एसएसपी, जैव उर्वरक, नैनो उर्वरक और हरित खाद के प्रयोग की जानकारी दी जा रही है। अभियान के अंतर्गत जिले के विभिन्न गांवों में लगातार कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

बाल श्रम उन्मूलन के लिए जागरूकता अभियान

रायपुर। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर प्रदेश में बाल श्रम के उन्मूलन तथा बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए व्यापक जन-जागरूकता अभियान संचालित किया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग, श्रम विभाग तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के समन्वित प्रयासों से आयोजित इस अभियान के माध्यम से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बाल श्रम के दुष्परिणामों तथा बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के महत्व के बारे में जागरूक किया गया। अभियान के तहत विभिन्न जिलों में होटल, ढाबा, दुकान, प्रतिष्ठान एवं मोटर वाहन गैराजों का निरीक्षण कर संचालकों को बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों की जानकारी दी गई। उन्हें बताया गया कि बच्चों से श्रम कराना कानूनन अपराध है तथा इसके लिए दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है। अधिकारियों ने व्यवसायियों से बाल श्रम मुक्त कार्यस्थल सुनिश्चित करने का आग्रह किया। ग्रामीण क्षेत्रों में चौपाल, जनसंवाद एवं जागरूकता बैठकों के माध्यम से अभिभावकों और ग्रामीणों को बच्चों की शिक्षा, सुरक्षा और समग्र विकास के प्रति जागरूक किया गया। उन्हें समझाया गया कि बच्चों का स्थान विद्यालय में है, न कि मजदूरी के कार्यों में। बच्चों को शिक्षा से जोड़कर ही उनके उज्ज्वल भविष्य और समाज के सतत विकास की मजबूत नींव रखी जा सकती है।

राजस्व संग्रहण में रायपुर नगर निगम का नया कीर्तिमान

एक ही दिन में 1.13 करोड़ की वसूली

■ आयुक्त संबित मिश्रा के नेतृत्व, नियमित मार्गदर्शन एवं स्पष्ट कार्यनीति से हासिल हुई बड़ी सफलता

रायपुर। नगर पालिक निगम रायपुर के राजस्व विभाग ने वित्तीय सुदृढ़ीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए आज एक ही दिन में अब तक 1 करोड़ 13 लाख 41हजार 532 रुपये की रिकॉर्ड राजस्व वसूली की है । नगर निगम आयुक्त श्री संबित मिश्रा द्वारा प्रतिदिन 1 करोड़ रुपये राजस्व संग्रहण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसे आज नगर निगम के राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने पूरी प्रतिबद्धता एवं टीम भावना के साथ सफलतापूर्वक प्राप्त किया।

राजस्व संग्रहण में रायपुर नगर निगम का नया कीर्तिमान, एक ही दिन में 1.13 करोड़ की वसूली आज नगर निगम के सभी जोनों में विशेष राजस्व अभियान चलाकर 515 संपत्तिकर धारकों से उक्त राशि की वसूली की गई। यह उपलब्धि न केवल रायपुर नगर निगम की वित्तीय स्थिति को और अधिक मजबूत करेगी, बल्कि रायपुर शहर में विकास एवं जनसुविधाओं से जुड़े कार्यों को भी नई गति प्रदान करेगी। राजस्व संग्रहण के आंकड़े यह भी दर्शाते हैं

कि रायपुर नगर निगम का अभियान लगातार सकारात्मक परिणाम दे रहा है।

वर्ष 2025 में जून माह के प्रथम 11 दिनों में जहां 44 लाख 17 हजार 342 रुपये की वसूली हुई थी, वहीं वर्ष 2026 में इसी अवधि में 62 लाख 49 हजार 628 रुपये का राजस्व संग्रह किया गया है। इस प्रकार पिछले वर्ष की तुलना में जून माह के पहले 11 दिनों में ही 18 लाख रुपये से अधिक की अतिरिक्त वसूली दर्ज की गई है, जो निगम की प्रभावी राजस्व रणनीति का प्रमाण है।

इस उल्लेखनीय सफलता के पीछे रायपुर नगर निगम आयुक्त श्री संबित मिश्रा का नियमित मार्गदर्शन, सतत मॉनिटरिंग, स्पष्ट निर्देश एवं परिणामोन्मुखी कार्यशैली प्रमुख आधार रही। आयुक्त श्री मिश्रा द्वारा राजस्व विभाग के कार्यों की निरंतर समीक्षा की जा रही है तथा लक्ष्य आधारित कार्य संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है। उनके नेतृत्व में राजस्व अमले ने पूरी सक्रियता के साथ कार्य करते हुए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया।

सभी जोन कमिश्नरों, उपायुक्त राजस्व डॉ. अंजलि शर्मा, सहायक राजस्व अधिकारियों एवं राजस्व विभाग के समस्त अधिकारियों-कर्मचारियों ने समन्वित प्रयासों के साथ अभियान को सफल बनाया। रायपुर नगर पालिक निगम प्रशासन ने इस उपलब्धि का श्रेय करदाताओं के सकारात्मक सहयोग एवं राजस्व अमले की मेहनत को भी दिया है।

नगर निगम प्रशासन का लक्ष्य प्रतिदिन 1 करोड़ रुपये राजस्व वसूली सुनिश्चित करते हुए शहर के विकास कार्यों के लिए संसाधनों को और अधिक सुदृढ़ बनाना है। आज की उपलब्धि इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है।

कृषि महाविद्यालय में व्याख्यान संपन्न

रायपुर। कृषि महाविद्यालय, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के सेमिनार हॉल में अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, रायपुर डॉ. आरती गुहे के मार्गदर्शन में ब्रह्माकुमारी डॉ. गीता बहन (आध्यात्मिक प्रेरक वक्ता, राजयोग प्रशिक्षण एवं परामर्श विशेषज्ञ, शांति सरोवर संस्थान, रायपुर) का प्रेरणादायक व्याख्यान आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए महाविद्यालय की प्राध्यापक, डॉ. अन्नू वर्मा द्वारा ब्रह्माकुमारी डॉ. गीता बहन का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात ब्रह्माकुमारी बहनों का पुष्पगुच्छ भेंट कर आत्मीय स्वागत किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों का स्वागत करते हुए महाविद्यालय परिवार ने उनके प्रति

सम्मान एवं आभार व्यक्त किया। अपने प्रेरणादायक उद्बोधन में डॉ. गीता बहन ने सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास, मानसिक शांति तथा आध्यात्मिक मूल्यों के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। वर्तमान समय में भौतिक उपलब्धियों के साथ-साथ मानसिक एवं आध्यात्मिक संतुलन बनाए रखना भी अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने विद्यार्थियों को जीवन में अनुशासन, समय प्रबंधन तथा सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की प्रेरणा दी। राजयोग ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित कर तनावमुक्त जीवन जी सकता है तथा अपने कार्यों में अधिक प्रभावशीलता और सफलता प्राप्त कर सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान अर्जित करना नहीं, बल्कि व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना भी है। विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहते हुए नैतिक मूल्यों का पालन करना चाहिए। उन्होंने व्याख्यान में उपस्थित सभी श्रोताओं को आत्मचिंतन एवं सकारात्मक जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.